आम बजट 2026

शिक्षा। स्वास्थ्य। रोजगार। पेंशन

युवा-महिला-बुजुर्ग

हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, मेडिकल में बढ़ी सुविधा तीन आयुर्वेदिक एम्स, पांच चिकित्सकीय पर्यटन केन्द्र

बजट में खास

शिक्षा के क्षेत्र को सौगात

- 01 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
- 05 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापना की घोषणा
- 04 टेलीस्कोप/खगोल विज्ञान सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी
- 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- 15000 माध्य. स्कूलों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- डिजिटल नॉलेज ग्रिड खोले जाएंगे
- हर जिले में छात्राओं के लिए होगी गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना

स्वास्थ्य क्षेत्र में ये नए संस्थान खोलने की घोषणा

- 05 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापना की घोषणा
- 02 नए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खुलेंगे
- 03 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे
- 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म
- 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा
- 07 नए आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव
- 07 पहले से मौजूद संस्थान होंगे अपडेट
- 17 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म
- कैंसर व शुगर की दवाइयां होंगी सस्ती
- एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नए संस्थान बनेंगे
- वेटनरी और पैरा-वेट कॉलेज/अस्पताल की स्थापना

बजट 2026-27 में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 55,727 लाख करोड़ रुपये उच्च शिक्षा विभाग और 83,562 लाख करोड़ रुपये स्कूल और साक्षरता विभाग के लिए हैं। इस बार शिक्षा के लिए आवंटित बजट पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 फीसदी अधिक रहा। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए बजटीय प्रावधान करते हुए भविष्य की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल विकास और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। साथ ही, देश के हर जिले में महिला छात्रावास खोलने की भी घोषणा की गई है। बजट में टियर-2 और टियर-3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे पेशेवर संस्थानों को सुविधा और प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

शिक्षा बजट 8.27% बढ़कर हुआ 1.39 लाख करोड़ रुपये

GIRLS HOSTEL

पिछले वर्ष से 8.27%
अधिक आवंटन

2026-27 के लिए शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं 2025-26 के बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल 1,28,650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

स्कूलों व कॉलेजों में 'कन्टेंट क्रिएटर लैब' बनेंगी

सरकार ने माना है कि भविष्य 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'डिजिटल कंटेंट' का है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कन्टेंट क्रिएटर लैब' बनाने का फैसला लिया गया है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 'एआई एप्लीकेशन' पर आधारित विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिससे देश की युवा शक्ति डिजिटल युग के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।

गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों का कायाकल्प

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में एक 'गर्ल्स हॉस्टल' बनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पतालों की क्षमता में 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। लघु उद्योगों की मदद के लिए सरकार एक अनूठी योजना लेकर आई। सीए, सीएस और सीएमए जैसे संस्थान अब शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार करेंगे, जिससे देश में 'कॉर्पोरेट मित्र' तैयार होंगे। ये एक्सपर्ट्स विशेष रूप से छोटे शहरों के व्यापारियों और उद्योगों को प्रोफेशनल मदद देंगे। आईआईएम की मदद से 10 हजार टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे।

बेटियों की पढ़ाई में अब नहीं आएगी कोई रुकावट

अक्सर देखा जाता है कि गांव या छोटे शहर की लड़कियों को बड़े कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन वहां रहने का इंतजाम करना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। बजट में लिया गया यह फैसला लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। जब हर जिले में अपना एक हॉस्टल होगा, तो मां-बाप भी बिना किसी डर के अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकेंगे। इससे न केवल पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम होगी, बल्कि लड़कियां खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। यह कदम महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की तरह देखा जा रहा है।

7 दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म

सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा, कई दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में हम दुर्लभ दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन इस पहल से अब भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा और भारत दुनिया को दवाई सप्लाई कर सकेगा। देश में ऐसे पहले से ही 7 संस्थान मौजूद हैं और इन्हें भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।

दवा उत्पादन के लिए दस हजार करोड़ किए जाएंगे खर्च

उम्मीदें...!
BUDGET 2026

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में हम दुर्लभ दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन इस पहल से अब भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा और भारत दुनिया को दवाई सप्लाई कर सकेगा। देश में ऐसे पहले से ही 7 संस्थान मौजूद हैं और इन्हें भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। जिला अस्पताल आधुनिक तकनीक से लैस होंगे तथा इमरजेंसी वार्ड की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी।

क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा

वित्त मंत्री ने दवाओं के साथ उसके विशेषज्ञों की भी जरूरत पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके जरिए थेरेपी और दवाओं की जांच जल्दी से हो जाएगी। ऐसे में देश में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाने की घोषणा हुई है।

युवाओं पर फोकस

युवाओं के सपनों को पांव रफ्तार से दौड़ेगा देश

सरकार ने आम बजट में सबसे बड़ी धुरी 'युवा शक्ति' और 'आधुनिक तकनीक' को बनाया है। सरकार ने इस बजट के जरिए न केवल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बायो-फार्मा और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार युवाओं को 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाना चाहती है। बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए भी विशेष रोडमैप तैयार किया गया है जो रोजगार व व्यापार में सहायक बनेंगे। बायो-फार्मा व एआई क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बायो-फार्मा और मेडिकल सेक्टर में आएगी क्रांति

सरकार ने भारत को दुनिया का मेडिकल हब बनाने के लिए सरकार ने 'बायो फार्मा शक्ति' योजना का ऐलान किया है। अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खुलेंगे। वहीं 7 पुराने संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, पशुपालन के क्षेत्र में भी 20 हजार नए वेटरनरी प्रोफेशनल तैयार करने के लिए विशेष कॉलेज खोले जाएंगे।

बुजुर्गों को रेल यात्रा में नहीं मिली छूट बाकी सब यथावत

भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद से बुजुर्गों को सफर में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वित्त मंत्री अपने पिटारे से यह तोहफा जरूर देंगी लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की घोषणा इस बजट में नहीं की गई जिससे बुजुर्गों को निराशा हाथ लगी। वहीं बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स की मौजूदा छूट सीमा भी पूर्व जैसे ही यानी 60 से 79 साल की उम्र वालों के लिए टैक्स छूट 3 लाख रुपये और 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपये ही रहेगी।

महिलाओं को मिला शी-मार्ट का तोहफा

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्व-स्हायता उपक्रम शी-मार्ट का ऐलान

भारत- विस्तार एआई टूल्स से कृषि उत्पादन में होगी सहायता

पीएम दिव्यांशा केंद्रों को बनाया जाएगा मजबूत

रोजगार के क्षेत्र में घोषणा

- 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' योजना
- खादी हथकरघा क्षेत्र को दिया जाएगा बढ़ावा
- निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने का लक्ष्य

केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक नई पहल शी-मार्ट की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं के व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। ताकि महिलाओं को और अधिक आर्थिक अवसर मिल सकें। शी-मार्ट्स समुदाय-संचालित रिटेल आउटलेट होंगे जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं खुद का कारोबार चला सकेंगी।

महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपए हो

वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की वह महिला सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम एक लाख रुपये हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य 2027 तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय को एक लाख रुपये तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उधार पर निर्भर रहकर काम करने की बजाय स्वयं के व्यवसाय की मालिक बनने में सहायता देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता (लोन) भी उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि वे अपने व्यापार को मजबूत कर सकें। बजट 2026 में महिलाओं के लिए यह नई पहल उनके आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता और स्वयं-का व्यवसाय चलाने वाली क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कदम है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए 'उद्यमों के मालिक' बनने की दिशा में "अगला कदम" बताया।

आम बजट पर आम नजरिया

पहला बजट जो एआई और आईटी को समर्पित

बजट एआई और आईटी को भारत के भविष्य के विकास की प्रमुख शक्ति के रूप में रेखांकित करता है। एआई समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर प्रभाव और कौशल आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति के गठन का सुझाव दिया गया है, जो कौशल विकास और रोजगार तैयारियों को दिशा देगी। सरकारी सेवाओं में एआई आधारित समाधानों के उपयोग, डिजिटल अवसंरचना के विस्तार तथा राज्य-स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सेवाओं को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को भी प्रमुखता दी गई है, जो चिप डिजाइन तथा निर्माण क्षमता को मजबूत कर इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई-आधारित उपकरणों के लिए अवसंरचना तैयार करेगा। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण कार्यक्रमों के लिए 8,000 करोड़ का आवंटन भी बढ़ाया गया है, जो घरेलू उर्ध्वाधर क्षमता के निर्माण में सहायक होगा।

इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का कुल बजटीय आवंटन बढ़कर 21,633 करोड़ किए जाने से एआई, डेटा प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं केंद्रित परियोजनाओं को बल मिलेगा। इंडिया एआई मिशन को विस्तारित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ का विशेष भाग निर्धारित किया गया है। डिजिटल कौशल कार्यक्रम और कंटेंट निर्माता लैब्स (15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में) की घोषणा की गई है। इससे एआई-आईटी आधारित रोजगारों और नवोन्मेषी कौशल के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। भारत की वैश्विक डिजिटल सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक हिस्सेदारी को 2047 तक 10% तक पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी।

- **प्रो.ओमप्रकाश व्यास**, डायरेक्टर, ट्रिपलआईटी, रायपुर

पशु चिकित्सक की व्यवस्था सार्थक निर्णय

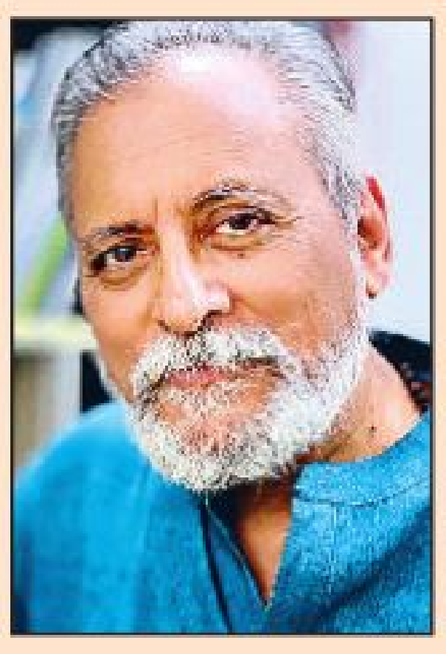

पशुधन की रक्षा के लिए पशु चिकित्सक की व्यवस्था को सुलभ बनाना बहुत सार्थक निर्णय है। महिला लघु उद्यमी के सहज बाजार लगाना बहुत ही अच्छा कदम है। मछुआरों की तरफ भी ध्यान दिया गया, ये सराहनीय है। कृषि क्षेत्र में किसानों को और नए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद थी। उद्यमियों को निर्यात के लिए थोड़ा अधिक प्रोत्साहन मिलना था। डीबीटी में कुछ परिवर्तन हो और केवल गरीबों को ही किसान सम्मान राशि प्रदान किया जाना था। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद थी। यह पूरी हुई। एआई और आईटी के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। बहनों में उद्यमिता बढ़ाने और भूमि के स्वास्थ्य सुधार के लिए थोड़े अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त नवचारों पर खर्च बढ़ाने के लिए उद्योग को नई छूट की उम्मीद एक वर्ग को थी। कुछ सीमा तक यह भी पूरी हुई है।

- **प्रो.एके गुप्ता**, आईआईएम, अहमदाबाद (पद्म पुरस्कार प्राप्त, गुजरात ग्रासरूट्स इनोवेशन ऑग्मेंटेशन नेटवर्क के संस्थापक)

चिंतन

आम बजट में भविष्य की तस्वीर दिखाई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026 एक ऐसा आर्थिक दस्तावेज़ है, जो भारत को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने की स्पष्ट मंशा दिखाता है। यह बजट विकासोन्मुखी,दीर्घकालिक सोच, रणनीतिक मजबूती और वैश्विक चुनौतियों के प्रति सजगता का परिचायक है, लेकिन साथ ही यह आम आदमी की तात्कालिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कमजोर भी नजर आता है। कहा जा सकता है कि यह बजट "कल" की तैयारी करता है, पर "आज" की परेशानियों को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। वित्त मंत्री ने 85 मिनट के लंबे भाषण में अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विस्तार से बात की, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव न होना यह संकेत देता है कि सरकार फिलहाल वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दे रही है। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने जैसे सुधार स्वागत योग्य हैं, मगर बढ़ती महंगाई के दौर में आम करदाता को इससे सीमित ही राहत मिलेगी। बजट का सबसे मजबूत पक्ष रक्षा क्षेत्र है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पेश हुए पहले बजट में सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये करना और आधुनिकीकरण व हथियार खरीद पर पूंजीगत खर्च में करीब 15% की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार सेना को तकनीकी और रणनीतिक रूप से और सक्षम बनाना चाहती है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है, हालांकि सामाजिक क्षेत्रों में इसी अनुपात में खर्च न बढ़ना सवाल भी खड़े करता है। अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से बचाने के प्रयास बजट में साफ झलकते हैं। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, ट्रंप-युग की टैरिफ मानसिकता और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में तनाव के बीच निर्यात प्रोत्साहन पर जोर दिया है। कपड़ा, चमड़ा, फिशरीज और दालों के निर्यात को बढ़ावा देने के कदम ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं। इससे रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बनेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अस्पतालों की घोषणा, दवाओं को सस्ता करने की पहल और 17 कैंसर मेडिसिन को ड्यूटी फ्री करना आमजन के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। आयुर्वेदिक एम्स जैसी घोषणाएं भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक ढांचे से जोड़ने की कोशिश मानी जा सकती हैं। शिक्षा और युवाओं पर केंद्रित योजनाएं बजट का एक और उल्लेखनीय पहलू हैं। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की योजना डिजिटल इंडिया और क्रिएटर इकोनॉमी की दिशा में कदम है। साथ ही करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा सामाजिक समावेशन और महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बजट चुनावी लोकलुभावन घोषणाओं से दूर नजर आता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के बावजूद किसी सीधे चुनावी लाभ वाली घोषणा का अभाव बताता है कि सरकार फिलहाल दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर आम बजट 2026 एक विज़न डॉक्यूमेंट है जो भविष्य की तस्वीर दिखाता है। यह बजट लोगों को संतुष्ट कर सकता है जो मजबूत रक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।

विश्लेषण

डॉ.जयंतीलाल भंडारी

विकसित भारत के लिए सुधारों का बजट

> वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। यद्यपि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया है और आयकर भरना आसान किया गया है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

यकीनन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह बजट आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत सुधारों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तीन कर्तव्यों पर आधारित किया है। इनमें उत्पादकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना, लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबके विकास के मद्देनजर ढांचागत सुधार के साथ प्रगति करना शामिल है।

इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए गए हैं। यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आयकर भरना आसान किया गया है। बजट के नए प्रावधानों से बुनियादी ढांचा, छोटे शहर, एमएसएमई, शिक्षा, पर्यटन और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लिए रोजगार के व्यापक मौके बढ़ेंगे। खास बात यह भी है कि आगामी वर्ष के बजट के तहत वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच सूझबूझ पूर्ण संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और सात फीसदी से अधिक विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। गौरतलब है कि नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार, उद्यमिता बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) स्वदेशी प्रोत्साहन और हरित ऊर्जा पर बड़े ऐलान किए हैं। इनके साथ-साथ भारत को वैश्विक बायो फॉर्मा केंद्र बनाने, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण, नए राष्ट्रीय जल मार्ग, सात हाई स्पीड कोरिडोर, व्यापार सुगमता, कंटेनर निर्माण, बुजुर्गों के लिए मजबूत इकोसिस्टम, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के विकास के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, वित्त मंत्री के समक्ष बजट तैयार करते समय चुनौतियां भी रही हैं। इन चुनौतियों में रुपये में लगातार गिरावट, अमेरिका का ऊंचा टैरिफ, मैन्युफैक्चरिंग व कृषि की धीमी रफ्तार शामिल हैं। निसंदेह वित्त मंत्री बजट के तहत गरीब, युवा, महिलाएं, किसानों के कल्याण के नए उपायों के साथ विकास योजनाओं पर भी अपने आवंटन को बढ़ाते हुए दिखाई दी हैं। बजट में रोजगार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दी हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस बजट में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रेलवे, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और क्षमता संवर्धन के साथ दीर्घावधि वृद्धि, वैश्विक क्षमता निर्माण और एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड के सुधार उभरकर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बजट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने संबंधी रणनीतियां भी दिखाई दी हैं। युवाओं के रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। सीतारमण बजट में खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए भी आपूर्ति संबंधी नए कदमों के साथ आगे बढ़ी हैं। बजट में वित्त मंत्री ने रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने की रणनीति भी अपनाई है। विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान भी बजट में दिखाई दे रहे हैं। नए बजट में हर क्षेत्र में आर्टिफिशल इटेंलिजेंस (एआई) को अहमियत हेतु प्रावधान किए गए हैं, ताकि भारत एआई का वैश्विक हब बन सके। सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए भी बजट में अधिक धन का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में भारत को दुनिया के बाजार में और अधिक प्रभावी रूप से जुड़ने और भारत को निर्यात का नया हब बनाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत की है।

भारत को यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के प्रोत्साहनमूलक प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को भी राहत देने के मद्देनजर वित्त मंत्री नए निर्यात प्रोत्साहनों की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं।निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने इस बजट में सीमा शुल्क के लिए जहाँ राहत दी है, वहीं सीमा शुल्क में सुधार भी किए है। यह बजट इसलिए भी खास रहा है, क्योंकि यह बजट पुराने टैक्स युग से नए टैक्स युग की दहलीज पर खड़ा बजट है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह नया इनकम टैक्स कानून लागू किया है। इससे देश के करोड़ों आयकरदाता लाभांवित होंगे। साथ ही नई श्रम संहिताएं भी आगामी वित्तीय वर्ष में लागू होने से श्रम उत्पादकता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास का नया अध्याय दिखाई देगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट कोई साधारण वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट देश के आर्थिक परिदृश्य को ऐतिहासिक मोड़ देने वाला बजट है। इस बजट से जहां देश में साहसिक सुधारों का नया युग शुरू हो सकेगा, वहीं आम आदमी के लिए अधिक राहत और देश के लिए तेज विकास का नया परिदृश्य निर्मित होगा।

उम्मीद करें कि एक ओर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 के बजट के बजट के लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक रखने में कामयाब होगी। उम्मीद करें कि इस अभूतपूर्व बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

आम बजट

प्रमोद भार्गव

आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट

नए आम बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह आयकर की सारिणी में छूट और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन बजट होगा, लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। इसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बजट की उम्मीदों में तमाम आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनियाद रख दी है। इस समय भारत उद्योग,प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, किंतु यह बजट कालांतर में चीन को चुनौती बनने वाला है। इस बजट में दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के द्वार खोले जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खनिज के साथ कृषि भी है। अतएव ईयू से जो संधि हुई है, उसके तहत भारत को स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर, ग्लास, तेल रिफाइनरी और खाद के निर्यात का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भारत भूमि को कुदरत ने अटूट प्राकृतिक संपदा दी हुई है। इस संपदा का उत्खनन और उसका उपयोग देश के लोगों के लिए हो, इस नजरिए से दुर्लभ खनिजों के उत्खनन के लिए बजट में ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। साथ ही वस्त्र, खेलकूद सामग्री,जैविक दवाओं,कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। रसायन पार्क विकसित होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन दो की शुरुआत की जाएगी। चूंकि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उपाय निरंतर कर रही है, इस हेतु सेमीकंडक्टर की उपलब्धता जरूरी है। इस दृष्टि से यह उत्पादन और निर्माण के ढांचागत विकास को स्थापित करने का महाबजट है। दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा हेतु संसद के मॉनसून सत्र में माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस नए कानून से व्यवसायियों को लीज पर खनन करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लीथियम, कोबाल्ट, निकल, हीरा जैसे दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा भी मिल गई है। भारत इन खनिजों के लिए अब तक चीन पर निर्भर था, लेकिन चीन ने इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी। यही वे खनिज हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और अंतरिक्ष उपकरणों में काम आते हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा लगाए गए अनर्गल टैरिफ के बाद चीन ने भारत को उपरोक्त खनिज देने का वादा किया हुआ है। ईयू से समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों के आयात-निर्यात का दायरा विस्तृत हो गया है। इसीलिए भारत अब अपनी शर्तों पर विकसित देशों के साथ व्यापार भी करेगा। अब माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पारित हो जाने से उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएंगे। मध्यप्रदेश की धरती हीरा और सोना तो उगलती ही है, तांबे और चूने का यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कटनी में चूने के भंडार हैं। शडहोल और उमरिया में कोयला एवं बॉक्साइड, छिंदवाड़ा में कोयला, बैतूल में ग्रेफाइड और सतना में सिमेंट के भंडार भरे पड़े हैं। मध्यप्रदेश में ईंधन खनन के लिए 12 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कोयला आधारित 37 प्रतिशत मीथेन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। जबलपुर में सोने के नए भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट सहित 30 दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज की गई है। इनके उत्खनन व प्रसंस्करण के बाद लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में जैविक औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। सरकार आयुर्वेद दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देगी। इन दवाओं का निर्माण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये रोग को जड़ से दूर करती हैं। सात द्रुत गति के रेल गलियारे बनेंगे। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के कारखाने खुलेंगे। छोटे नगरों में तीर्थस्थल विकसित होंगे। इस उपाय से छोटे नगरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को धर्म संबंधी रोजगार मिलेंगे। एक जिला,एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है। साफ है यह बजट अन्य आम बजटों से एकदम अलग है। इसमें मतदाता को लुभाने और आयकरदाताओं को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उद्योग केंद्रित बजट है, जिसके स्थाई और फलदायी परिणाम धीमी गति से आएंगे। जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती देंगे, बल्कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योग के सभी सूत्र सुदृढ़ जीवन की आधारशिला

संकलित

दर्शन

योग प्राचीन काल से भारतीय आध्यात्मिक संचेतना का केंद्र रहा है। इसके आदिम सूत्रधार परमयोगी भगवान शिव हैं। योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा है। समाधि अर्थ में इसका प्रयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए किया जाता है, जब साधक अपनी साधना की चरमावस्था में परमात्मा से एकाकार होकर उसका साक्षात्कार कर लेता है। अग्निपुराण में भी मन एवं आत्मा तथा आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा गया। सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का भेद होने पर भी पुरुष का आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना योग कहलाता है। कठोपनिषद् के अनुसार, जब इंद्रियां मन के साथ और मन अविचल बुद्धि के साथ स्थिर हो जाता है तो यह अवस्था योग की होती है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 'योगः कर्मसु कौशलम्' कहकर योग का जो स्वरूप अजरुन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह सामान्य जन के सर्वाधिक निकट है। कोई भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग को सिद्ध कर सकता है। योगसूत्र के प्रणोता महर्षि पतंजलि संयमन अर्थ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उनके अनुसार यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा आदि आठ अंगों से संपन्न प्राणायाम की विविध क्रियाएं योग कहलाती हैं। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। बुद्धि में स्थिरता आती है। चिंतन उत्कृष्ट होता है। मन में सद्विचारों का उदय होता है। नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। परिणामतः आत्मिक और शारीरिक शक्तियों में वृद्धि होती है।

मन का भोजन हमारे विचार

संकलित

प्रेरणा

एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी ये प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन हैं। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच-विचार करना बंद कर देना चाहिए। तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न तीन बार पूछा था और बुद्ध ने भी तीन बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने तीन बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से तीन बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी तीन बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से तीन बार प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी तीन बार दिया, ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए।

थाईपुसम त्योहार

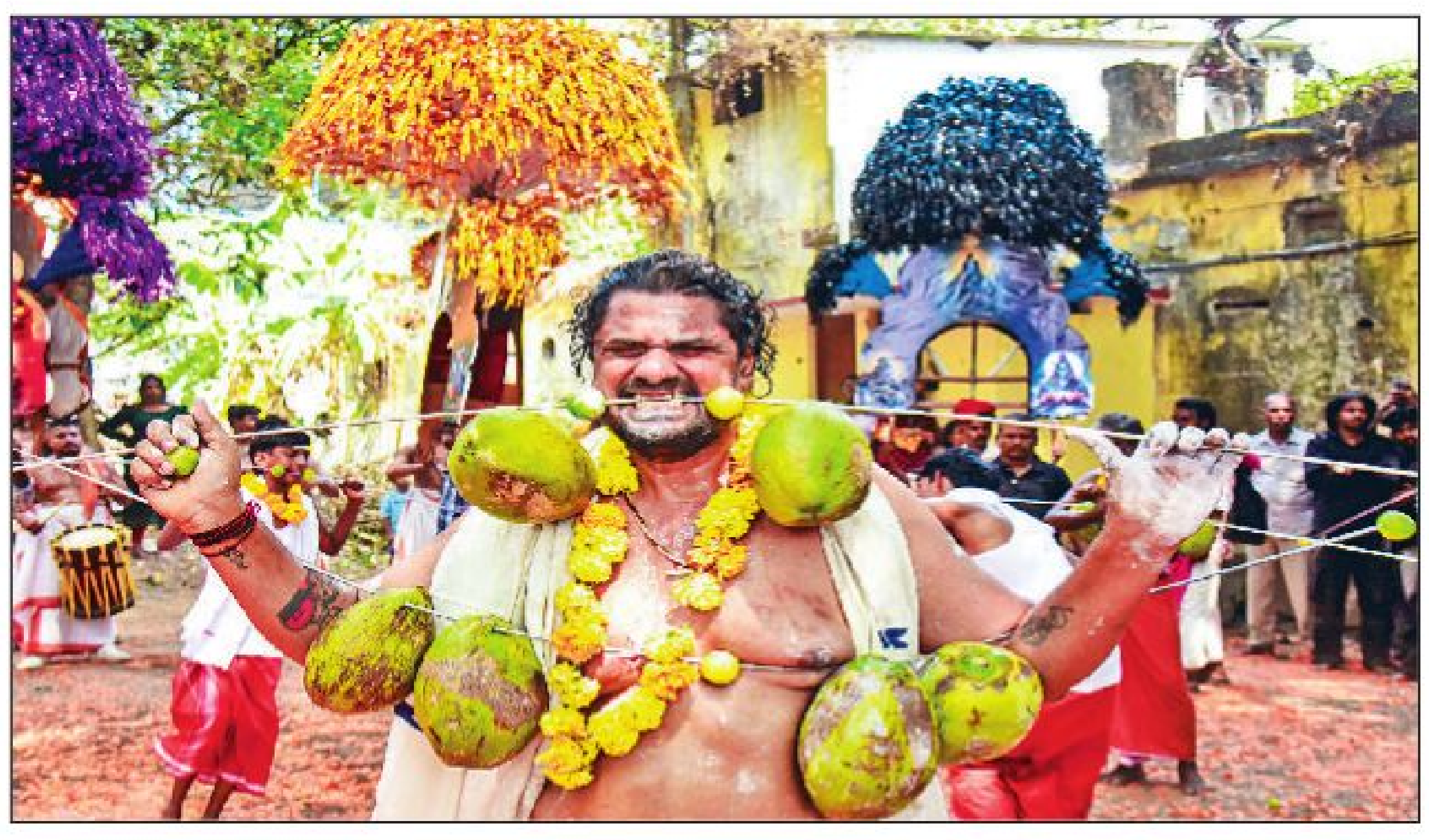

भगवान मुरुगन की जयंती के अवसर पर एक अपनी जीभ में सांग छेद कर थाईपुसम त्योहार में हिस्सा ले रहा है।

आज की पाती

उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करना जरूरी

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन अगर हम इनका सावधानी से प्रयोग न करें तो यह हमारे लिए कभी भी हानिकारक बन सकती हैं और अक्सर खबरें भी पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि इन चीजों के प्रयोग करते कई बार हादसा हो गया। सर्दियों में गैस गीजर, कोयले की अंगीठी और अन्य गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए लोग गैस से चलने वाले गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रयोग में जरा सी भी असावधानी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। गैस गीजर को बाथरूम में लगाने के साथ-साथ एक खिड़की जरूर रखें। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। - *संजय शर्मा, दुर्ग*

करंट अफेयर

इजराइल की रफाह सीमा क्रॉसिंग खोलने की घोषणा

इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गयी। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है और तैयारियां पूरी होने के बाद गाजा के निवासी यहां से आवागमन शुरू कर सकेंगे। मिस्र के एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि फलस्तीनी सुरक्षा अधिकारी मिस्र वाले द्वार से होकर क्रॉसिंग में दाखिल हुए और फलस्तीनी द्वार की ओर बढ़े, जहां वे एक यूरोपीय संघ मिशन के साथ जुड़ेंगे, जो प्रवेश और निकास की निगरानी करेगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि एंबुलेंस भी मिस्र वाले द्वार से होकर गुजरीं।

ऑफ बीट

रात में पसीना आने के कई कारण हो सकते हैं

पसीना आना शरीर की शीतलन प्रणाली का एक सामान्य हिस्सा है, जो गर्मी छोड़ने और शरीर के इष्टतम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन नियमित रूप से रात में जागना, अत्यधिक पसीने से भीगना सही नहीं है। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस, अंत:स्रावी तंत्र का हिस्सा है और शरीर के लिए तापमान नियंत्रण केंद्र है। इसमें तापमान सेंसर होते हैं जो केंद्रीय रूप से (अंगों में) और परिधीय रूप से त्वचा में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं (थर्मोरिसेप्टर्स) से जानकारी प्राप्त करते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स शरीर के तापमान में बदलाव का पता लगाते हैं, हाइपोथैलेमस को वापस संकेत भेजते हैं। ये संकेत या तो शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने को सक्रिय करेंगे या शरीर को गर्म करने के लिए कंपकंपी को सक्रिय करेंगे। उम्र या लिंग कोई भी हो, किसी को भी रात में पसीना आने का अनुभव हो सकता है। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को रात में पसीना अधिक आता है, इसका मुख्य कारण रजोनिवृत्ति और संबंधित बदलते हार्मोन स्तर हैं। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव से नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो हाइपोथैलेमस में तापमान विनियमन को प्रभावित करते हैं।

---

2 फरवरी पर विशेष

वेटलैंड

वेटलैंड जो अंग्रेजी का शब्द है के लिए हिंदी में अनेकानेक शब्दों का उपयोग देखने में आता है आर्द्र ,जलोध,नम,दलदली भूमि ये सभी शब्द एक ही मायने और अर्थ प्रकट करते हैं और इनकी उपस्थिति हमारे जैव मंडल के लिए अति आवश्यक है जिसमें जल चर थल घर,नभ चर समाहित हैं इन सभी की जीवन सुरक्षा में वेट लैंड की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसका संरक्षण संवर्धन आवश्यक है इन उदाहरणों से समझा जा सकता है झील, ताल तलैया, पोखर, तालाब या वो सभी जल संग्रहण के केंद्र जहां पानी की गहराई 6 मीटर से ज्यादा न हो ये सभी स्थान वेटलैंड (नम भूमि) को इंगित करते हैं जो मिट्टी, पानी,जैव विविधता को पुष्ट कर जीव जगत को सुरक्षित जीवन प्रदान करते रहते हैं।

वेटलैंड प्राकृतिक रुप से जल शोधन का कार्य कर जल को साफ सुथरा कर पेयजल आपूर्ति कर अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं वहीं ये बाढ़ आने पर इसकी रोकथाम कर प्राकृतिक बफर बन ढाल का कार्य कर सभी की सुरक्षा करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में वेट लैंड अग्रणी भूमिका में हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु रक्षक का कार्य प्राकृतिक रुप से करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है आज जिस प्रकार से भी जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसे संतुलित रखने में आद्र भूमि अपनी महती भूमिका निभाते दिखते हैं।

इनकी आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 के अंतर्गत भारत शासन द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 लागू कर इसकी सुरक्षा को सर्वोपरि माना वहीं राज्य शासन द्वारा 17.12.2018 को राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कर इसकी सुरक्षा हेतु कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का परिपालन सुनिश्चित किया एवं सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठन सुनिश्चित किया गया इस प्रकार के निर्णयों से ये बात तो स्पष्ट होती है कि शासकीय और गैर शासकीय सभी स्तरों पर वेटलैंड को संरक्षित संवर्धित करने की भावना बलवती होती जा रही है जो एक शुभ संकेत है इस प्रकार के नजरिए से हमारे नगरीय और ग्रामीण वेटलैंड को असमय हो रही मृत्यु से बचाया जा सकेगा साथ ही भू-जल स्तर जो तेजी से नीचे जा रहा है उसे भी बचाया जा सकेगा और अस्तित्व-सह अस्तित्व के भाव से समाज परिवार और प्रकृति के भाव सुरक्षित रह सकेंगे।

-प्रभात मिश्र

रविवार को शेयर बाजार खुला और गिरा धड़ाम से, बजट में एसटीटी पर सख्ती से टूटा

- सेंसेक्स से 8 लाख करोड़ रुपए साफ, निवेशकों में बेचैनी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

आम बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) से जुड़े प्रावधानों ने शेयर बाज़ार की धारणा को गहरी चोट पहुंचाई है। बजट के तुरंत बाद आई भारी बिकवाली के चलते शेयर बाज़ार से करीब 8 लाख करोड़ रुपये का बाज़ार पूंजीकरण घट गया। विश्लेषकों का मानना है कि एसटीटी से जुड़ी सख्ती और स्पष्ट राहत के अभाव ने निवेशकों, खासकर शॉर्ट-टर्म और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को निराश किया।

एसटीटी बना गिरावट की बड़ी वजह

बजट में सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एसटीटी के दायरे और प्रभाव को लेकर जो संकेत दिए, उससे बाज़ार में लागत बढ़ने की आशंका गहराई। विशेषज्ञों के मुताबिक, एसटीटी में किसी भी तरह की वृद्धि या उसमें राहत न देना सीधे तौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम, खासकर डेरिवेटिव्स और इंट्रा-डे कारोबार को प्रभावित करता है। यही वजह रही कि बजट के बाद पहले ही सत्र में आक्रामक बिकवाली देखने को मिली।

छोटे निवेशक और ट्रेडर सबसे ज्यादा प्रभावित

एसटीटी का बोझ सीधे हर सौदे पर पड़ता है, चाहे निवेशक को मुनाफा हो या नुकसान। इस कारण छोटे निवेशक, डे-ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा दबाव में आए। बाज़ार जानकारों का कहना है कि इससे इक्विटी बाज़ार की आकर्षण क्षमता घटती है और पूंजी का रुख दूसरे एसेट क्लास की ओर मुड़ सकता है।

ब्रोकरेज और एक्सचेंज शेयरों पर दबाव

एसटीटी से जुड़ी चिंताओं का असर ब्रोकरेज, एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों पर भी साफ दिखा। कारोबार घटने की आशंका से इन कंपनियों के शेयरों में औसत से कहीं ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

सरकार का पक्ष और दीर्घकालिक तर्क

सरकार का कहना है कि बजट में राजकोषीय संतुलन बनाए रखना जरूरी है और एसटीटी जैसे कर बाज़ार से स्थिर राजस्व का स्रोत हैं। साथ ही सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर खर्च बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे दीर्घकाल में आर्थिक गतिविधियों और कॉरपोरेट मुनाफे को सहारा मिल सकता है।

आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार एसटीटी पर स्पष्टीकरण या भविष्य में पुनर्विचार का संकेत देती है, तो बाज़ार की धारणा में सुधार आ सकता है। फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहने और गुणवत्ता वाले शेयरों पर दीर्घकालिक नजर रखने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल, बजट में एसटीटी को लेकर उठे सवालों ने यह साफ कर दिया है कि शेयर बाज़ार केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि लेन-देन की लागत से भी गहराई से प्रभावित होता है। जब तक इस मोर्चे पर भरोसा बहाल नहीं होता, बाज़ार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। सोमवार को बाज़ार के हालत पर इसकी संभावनाओं पर रविवार देर शाम तक विशेषज्ञों ने चुप्पी बनाए रखना ही ठीक समझा।

आम बजट में 7 रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण पर दिया गया जोर

भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे

इलेक्ट्रॉनिकी कल-पुर्जा निर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया

- *उपकरण और सामग्री उत्पादन, भारतीय आईपी का पूरी तरह डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा*
- *खनिज समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मदद के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना की*
- *5 वर्षों की अवधि में 10 हजार करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिवेश के निर्माण की योजना*

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करने पर जोर दिया गया है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम बजट में 'पहला कर्तव्य' के तहत छह क्षेत्रों का हिस्सा होगा।

भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय बजट में अगले पांच वर्षों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए उचित प्रणाली का निर्माण होगा। इसके लिए बजट में अभिकल्पित कार्यनीति में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क और सात मौजूदा संस्थानों का अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें एक हजार से अधिक प्रत्यायित भारत क्लीनिकल ट्रायल्स केन्द्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। केन्द्रीय बजट में वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत करने और एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर तथा विशेषज्ञों के जरिए समय से अनुमोदन के लिए प्रस्ताव किया गया है।

देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमता में विस्तार करने और भारत सेमीकंडक्टर मिशन (1.0) को आधार मानकर केन्द्रीय बजट में उपकरण एवं सामग्री निर्माण, भारतीय आईपी का पूरी तरह से डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2.0) शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए सरकार का ध्यान उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों पर रहेगा।

राज्यों को चैलेंज रूट के जरिए कलस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर 3समर्पित रसायन पार्कों की स्थापना में मदद के लिए योजना का प्रस्ताव

अप्रैल 2025 में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय 22 हजार 919 करोड़ रुपये था। बजट 2026-27 में इस राशि को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय बजट में खनिज समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना में मदद करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने चैलेंज रूट के जरिए कलस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर तीन रसायन पार्कों की स्थापना में राज्यों को मदद करने के लिए एक योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। केन्द्रीय बजट में दो स्थानों पर उच्च प्रौद्योगिकी टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। इसकी स्थापना सीपीएसई डिजिटल रूप से समर्थित ऑटोमेटिड सर्विस ब्यूरो के रूप में करेगी। जो स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। निर्माण और अवसंरचना उपकरण (सीआईई) को बढ़ावा देने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च घरेलू विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के स्तर पर उन्नत सीआईई को मजबूत करना है। यह बहुमंजली इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग संबंधी उपकरण हो सकते हैं। बजट में वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिवेश के निर्माण के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए, पांच वर्ष की अवधि में 10 हजार करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन है।

श्रम गहनन वस्त्र उद्योग के लिए, बजट में पांच उपभागों वाले एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। पहला, रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और आधुनिक फाइबरों में आत्म-निर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना; दूसरा, मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक कलस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना; तीसरा, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं मजबूत करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम; चौथा, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र तथा परिधानों को बढावा देने के लिए टैक्स इको पहल; पांचवां, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 ।

तकनीकी वस्त्रों के मूल्यवर्धन पर ध्यान देते हुए बजट में चुनौती मूड में वृहद वस्त्र उत्पाद स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे वैश्विक बाजार में जगह बनाने और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। बजट में कहा गया है कि इससे प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाया जाएगा और सहायता भी मिलेगी। इस पहल से हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा।

बजट पेश करने के दौरान श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के किफायती सामानों के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरने की संभावना है। बजट में उपकरण डिजाइन के साथ-साथ सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव किया गया है।

रायपुर सांसद बृजमोहन ने कहा

छत्तीसगढ़ को 52 हजार करोड़ की हिस्सेदारी, यह खोलेगा विकास का नया द्वार

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

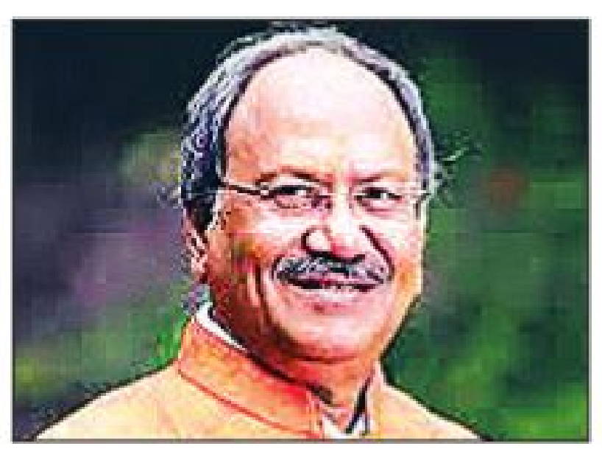

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आम बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि यह विकसित भारत के लिए एक सफ़ल नींव साबित होगा।साथ ही इससे खुशहाल छत्तीसगढ़ के लिए भी रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए इस साल 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित है। जो रोज़गार के नए द्वार खोलेंगे समूचे बजट में पिछली बार के 49 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 53 लाख करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। खर्च प्रस्ताव में 10 फ़ीसदी की ऐसी बढ़ोतरी युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध करायेगी छत्तीसगढ़ को भी इस साल 42 हजार करोड़ की बजाए 52 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जिससे राज्य में विकास के नये रास्ते निकलेंगे। युवाओं और महिला बाल विकास पर भी और बेहतर ढंग से कार्य हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के लिए माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इससे खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इस पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कदम राज्य की अपार खनिज संपदा से खुशहाली के अनेक रास्ते निकालेंगे। राज्य की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रेल्वे कॉरिडोर से भी छत्तीसगढ़ में विकास बढ़ेगा। यह बजट देश को 2047 तक विकसित करने के लिए बनाया गया है। 10 हजार करोड़ का एमएसएमई फंड देश को विकास की राह में और आगे ले जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए यह घोषणा की कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यगों (एमएसएमई) की सहायता के लिए मझोले (श्रेणी-दो) और छोटे (श्रेणी-तीन) शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का एक दस्ता तैयार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताया कि केंद्र सरकार ने छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज को इंसेंटिव देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड शुरू करने की योजना की घोषणा की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस साल का बजट रक्षा, बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय, बिजली और किफायती आवास पर केंद्रित है। इससे सामाजिक कल्याण, प्राथमिकताओं और वित्तीय विवेक के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा गया है।

स्टार्टअप, डीप टेक और डेटा सेंटर का नया गढ़ बनेगा हरियाणा : नायब

कहा, हरियाणा बनेगा एआई नवाचार का केंद्र, विश्व बैंक देगा 470 करोड़ रुपए की मदद

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा स्टार्टअप, डीप टेक और डेटा सेंटर का नया गढ़ बनेगा। उन्होंने शनिवार देर सायं चंडीगढ़ में आयोजित टी.आई.ई. एआई शिखर सम्मेलन–2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही। वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया के संकल्प को साकार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि "ग्लोकल एआई – रियल इम्पैक्ट" केवल एक विषय नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता है, जिसमें वैश्विक सोच को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि दि इंडस एंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन भविष्य की तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को नई दिशा देने वाला सशक्त मंच है। इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री असीम गोयल, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जे. गणेशन तथा टी.आई.ई. चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट पुनीत वर्मा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एआई के अनुसंधान, नवाचार और उत्तरदायी नीति निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एआई स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों की पहचान और उपचार को अधिक सटीक बना रही है, शिक्षा में व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया को सशक्त कर रही है तथा कृषि क्षेत्र में किसानों को उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बाजार और मूल्य संवर्धन में सहायता प्रदान कर रही है। छोटे और मध्यम उद्यम एआई के माध्यम से अपनी दक्षता बढ़ाकर वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एआई को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा एआई मिशन' स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 470 करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है। इस मिशन के अंतर्गत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

कहा- बंगाल में भाजपा की आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय निश्चित

ममता आज करेंगी सीईसी से मुलाकात एसआईआर से जुड़े मुद्दे रखेंगी सामने

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में हार सुनिश्चित होने के कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री बनर्जी रविवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार की शाम दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने वाली हैं। ममता बनर्जी सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सीईसी से मुलाकात के दौरान मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े मुदे उठाएंगी। उन्होंने कहा, मैं उन्हें बताऊंगी कि एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है।

उन्होंने दावा किया कि राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा की आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय निश्चित है। बनर्जी ने कहा कि जिस कारण भाजपा एसआईआर का दुरुपयोग कर रही है, वह सबके सामने है। भाजपा को चुनौती देते हुए ममता ने कहा, मैं उनसे कहूंगी, अगर हिम्मत है तो राजनीतिक लड़ाई लड़ो। हम इंच-इंच लड़ने के लिए तैयार हैं।

वे (भाजपा) संघीय ढांचे को कैसे खत्म करना चाहते हैं? मैं सब बताऊंगी। हमने क्या किया, यह भी बताऊंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने सांसदों को एसआईआर के नाम पर की जा रही कोशिशों के बारे में जानकारी देंगी। उन्होंने कहा, भाजपा नेता जानते हैं कि बंगाल में हारेंगे। इसलिए एसआईआर का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर भाजपा में हिम्मत है, तो मैं उनसे अपील करूंगी कि चुनाव आयोग (ईसीई) और एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिक और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़ें।

एनसीबी के विलय पर असमंजस की

शरद पवार मुंबई पहुंचे तो बारामती लौट गईं डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार

एजेंसी ⏭ मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसी बीच, एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार रविवार सुबह बारामती से मुंबई के लिए रवाना हो गए, जबकि नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार देर रात बारामती लौट आईं। शरद पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के चार दिन बाद मुंबई के लिए रवाना हुए। सुनेत्रा ने शनिवार को मुंबई में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुणे जिले के बारामती स्थित अपने आवास लौट आईं। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों के बीच यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि शरद और सुनेत्रा के बीच कोई मुलाकात या बातचीत हुई या नहीं।

एयर इंडिया ने भरी शंघाई से नई दिल्ली के बीच पहली उड़ान

छह साल के बाद नई दिल्ली और शंघाई के बीच हुई सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत, इससे संबंध सुधरेंगे

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भारत और चीन के बीच पिछले साल पूरी तरह से खत्म हुए एलएसी विवाद के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जारी कवायद के बीच एक खुशखबरी सामने आई है। जिसमें ये पता चला है कि भारत ने करीब छह साल के लंबे अंतराल के बाद रविवार को एक बार फिर से नई दिल्ली से शंघाई के बीच सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत कर दी है। पूर्व में 2020 से इस पर रोक लगी हुई थी। दोनों देशों के बीच हवाई यातायात के नजरिए से यह एक बेहद महत्वपूर्ण लिंक है। जिस पर उड़ान सेवाओं का आगाज एयर इंडिया ने किया है। 1 फरवरी को ही एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान ने शंघाई के पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए पहली उद्घाटन उड़ान भरी है। जिसमें कुल करीब 230 यात्रा सवार थे। एयर इंडिया इस रूट पर सप्ताह में चार बार अपनी उड़ान सेवाओं का संचालन करेगी। विमानन कंपनी का यह निर्णय इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि दोनों देशों के बीच आमजन में आवाजाही को लेकर रुचि बरकरार है। संभव है कि इसकी मदद से भारत और चीन के बीच आगामी वक्त में शिक्षा, पर्यटन और व्यापार के संबंध में भी लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिले।

महावाणिज्य दूतावास की प्रतिक्रिया

शंघाई में भारत के महादूवाणिज्य-दूत प्रतीक मिश्रा ने शंघाई के पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयर इंडिया की फिर से शुरू हुई इस नॉनस्टॉप उड़ान सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एक्स पर पोस्ट में महावाणिज्य दूतावास ने कहा, यह उद्घाटन समारोह 6 साल बाद दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान अपने संबोधन में प्रतीक मिश्रा ने खासतौर पर इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बेहतर हवाई संपर्क दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क, व्यापार, पर्यटन, वाणिज्य, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।

बजट से पहले आमजन को झटका

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हो गया 49 रु. का इजाफा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट से ठीक पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 49 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 फरवरी से लागू हो गई है। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत अब बढ़कर 1,740.50 रुपए हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे लोगों के रसोई का बजट बिगड़ सकता है।

जुनी कॅसेट खरंच बंद व्हायला हवी...

दरवर्षी १ फ्रेब्रुवारीला अर्थमंत्री बजेट सादर करतात. ज्याद्वारे आपल्याला लक्षात येतं की सरकार कोणत्या घटकांवर पैसे खर्च करणार आणि सरकारला हा पैसा कशाद्वारे मिळणार. लोकांच्या कल्याणासाठी आणि पायाभूत सुविधांवर हा पैसा खर्च होणार असतो. सर्वसामान्य माणूस आणि बजेट असा सहसंबंध जोडला तर आपल्याला ‘नको ना तीच तीच कॅसेट लावूस भाई’ अशी अस्सल आणि सगळ्या अवतीभवतीच्या विश्लेषणात चपखल बसेल अशी प्रतिक्रिया असते.

कोणत्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि कोणत्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या एवढाच अर्थ सर्वसाधारणपणे सर्वमान्य असलेला दिसतो. आपलाच पैसा आपल्यावर कशा तऱ्हेने खर्च होणार , याचा पूर्वअंदाज बजेटमध्ये असतो. आपण स्वतःला सुजाण वगैरे नागरिक म्हणतो. पण याकडे गांभीर्यानं पाहणं आणि अभ्यासणं आपण टाळतो. कारण तशी आपली ‘मेंटल कंडिशनिंग’ झालेली असते. ती तशी होण्यात एक प्रकारे समाजाने हातभार लावलेला असतो. आपल्याला वारंवार सामना कराव्या लागणाऱ्या किचकट समस्या जागोजागी दिसतात. पण जागरूक नागरिक म्हणून याचा थेट संबंध कसा अर्थकारणाशी, सामाजिकतेत जोडलेला आहे हे आपण विसरतो. त्यामुळेच वारंवार आपल्याला जुन्याच धोरणात्मक घोषणांचे ‘बच्चन’ दिले जाते. माझ्यासकट आमचा शेजारी सार्वजनिक शौचालयातील ट्यूबलाइट उडाली, नळाला पाणीच आलं नाही, गटारांची लादीच मधोमध उपडी पडली वगैरे तक्रारी करतो, पण आज अर्थसंकल्पात १२ वर्षांपासून नियोजनबद्ध विकास सुरू आहे असं दणदणीत वाक्य उच्चारलं गेलं. या वाक्याला संसदेचे बेंच दाणदाण वाजले; तेव्हा आम्हाला कळलं ‘अर्रे विकास होतोय, पण घोषणा करण्यापुरताच’. २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेखालून बाहेर काढलं असंही वाक्य उच्चारलं गेलं. त्यात मी कुठाय? असं उभं राहून कुणी विचारलं तर तो देशद्रोही ठरेल नाही? आमची सुधारणांची एक्स्प्रेस वेगाने विकास करतेय असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. अहो पण नैसर्गिक संसाधनांना ओरबाडणं हा विकास नाही. लोक निसर्ग वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरतायत त्यांना सरकार ‘आंदोलनजीवी’ म्हणतं. रचनात्मक सुधारणेचे कैक पर्याय वेगवेगळ्या संस्थांनी देऊनही त्याचा विचार न करणं आणि आमचा रचनात्मक सुधारणेवर भर असणार आहे, असं अर्थसंकल्पात सांगणं हे नेमकं काय आहे हे जरा इस्कटून सांगा राव! शेतकऱ्यांचा जीव घ्यायचा, सेंद्रिय शेती करायला सांगायची. पण रासायनिक खतांच्या किमती वाढलेल्या दिसतात त्याकडे कोण पाहणार? मुंबईत ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब’ उभारणार असल्याचं सांगणार पण या देशातील कित्येक शाळा, महाविद्यालयं, प्राथमिक आरोग्य केंद्रं पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. नीटनेटकी स्वच्छतागृहे आपल्याला उभी करता आलेली नाहीत. शिक्षक नाहीत, त्यांना वेळेवर पगार नाही, नव्या भरत्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांचा आलेख निदान समोर ठेवून त्या घोषणांतून आपण पुढे किती मजल मारली, हे ठणकावून सांगण्याऐवजी अमुक-अमुक कोटींच्या आकडेवारीवर खेळत राहणं याला काही अर्थ असल्यास आम्हाला यात काडीचाही रस नाही, जे चाललंय ते चालू दे, आपल्या बोलण्यानं काही होणार आहे का, असे नेहमीचे प्रश्न सर्वसामान्यांकडून येणार असल्यास, जे चाललंय ते चुकीचं चाललंय, हा आमचा पैसा आहे तो योग्य कारणासाठी वापरला जावा, असं भान यायला इथला अवकाश आणखी लोकाभिमुख व्हायला हवा. कुणाला काय मिळालं यापेक्षा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि त्या विकासात ज्या सर्वसामान्य तळागातील लोकांचं सहकार्य आहे, अशा लोकांनी आम्हाला नेमका विकास कसा हवाय, माझं शहर, माझं गाव हे विकासाच्या कोणत्या प्रारूपात आम्हाला हवंय हे सांगायला हवं. केवळ पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या शहरातील पायाभूत सुविधा वाढवणं हे प्रारूप योग्य नाही.

शेती-शिक्षण-आरोग्य या घटकांवर घोषणा होतात. पण दर्जेदार शिक्षण आणि त्याचा प्रसार हे आपल्याला साध्य झालेलं नाही. हवामान बदल आणि त्यामुळे ओढवणारी नैसर्गिक हानी याला अजूनही आपण हलक्यात घेतोय आणि डोंगरांना पोखरत निघालोय. केरळ, आंध्र प्रदेश वगैरे राज्यांत खनिज उत्खननाची केंद्रे करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या विकासात निसर्गाचा समतोल कसा राखला जाईल, हे विचारायची सोय नाही. कारण प्रश्न विचारले की आपण विकासाच्या आड येतो.

प्रदीप कोकरे
युवा लेखक, संपादक

या अर्थसंकल्पात काहीही नवं नाही. त्यामुळं काय चांगलं काय वाईट याच्या फंदात न पडलेलं बरं. पण नुसत्या आकडेवारीची आणि आर्थिक धोरणांच्या घोषणांची ही जुनी कॅसेट बंद व्हायला हवी. आपण काही नवं, देशहिताचं देणार नसू, सांगणार नसू तर खुल्या मनानं मान्य करावं. औपचारिक कार्य आहे तर घ्या उरकून असा अट्टहास त्यामागे नको.

प्रदूषण नियंत्रण तरतुदींत घट असमर्थनीय!

पर्यावरण मंत्रालयाच्या खिशात मागील वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्के अधिक तरतूद पडली असली, तरी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासंदर्भातील तरतुदी कमी करण्यात आल्या आहेत, त्या का?

डॉ. जयंत गाडगीळ
पर्यावरणविषयक संशोधक
jayantgadgil22@gmail.com

कोणत्याही अर्थसंकल्पातील पर्यावरणावरील तरतुदी या राज्यकर्ते आणि नोकरशाहीची पर्यावरणविषयक प्रश्नांची जाण अधोरेखित करतात. प्रत्येक देशाच्या पर्यावरणविषयक समस्या पूर्ण वेगळ्या असतात. त्यामुळे पर्यावरणविषयक तरतुदी कोणत्याशा टेक्स्टबुकातून उधार घेता येत नाहीत, ना त्यात अन्य एखाद्या देशाचे अनुकरण करता येत. या समस्या सोडवण्यासाठी कितपत सर्जनशील विचार केला आहे, यावर त्या तरतुदींचे स्वरूप आणि यश अवलंबून असते.

भारतात दरडोई उपलब्ध जमीन व नैसर्गिक संसाधने इतर अनेक मोठ्या, विकसित अर्थव्यवस्था, देश यांच्या तुलनेत चार (चीनच्या तुलनेत) ते वीस (अमेरिकेच्या तुलनेत) पट कमी आहेत. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग तसेच स्त्रिया व बालकांवर होणारे हवामान बदलांचे विपरीत परिणाम अधिक तीव्र असतात. त्यामुळे या सर्वांना या अर्थसंकल्पाने काय दिले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे महत्त्वाचे ठरते.

भारतात हवामान बदलांसंदर्भातील निरंतर विकास ध्येयांसाठी (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) ठळक तरतुदी असणे गरजेचे होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यावरण मंत्रालयाच्या खिशात मागील वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्के अधिक तरतूद पडली असली, तरी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासंदर्भातील तरतुदी कमी करण्यात आल्या आहेत. विविध प्रकारच्या पर्यटनामुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांची वाढ होणार हे गृहीत धरले, तरी प्रदूषणाचा मुद्दा अतिशय गंभीर स्वरूप धारण करत असताना प्रदूषणविषयक तरतूद कमी करणे समर्थनीय आहे का? वाघ व हत्ती यांचा मानवाशी होणारा संघर्ष लक्षात घेता मागील वर्षीपेक्षा सुमारे दुप्पट तरतूद करण्यात आली हे स्वागतार्ह आहे, पण प्रदूषणासाठीच्या तरतुदीत घट करून तीच रक्कम वाघ व हत्तींकडे वळवली आहे का, असाही प्रश्न पडतो. विविध विकास प्रकल्पांसाठी जंगलाचे सलग क्षेत्र आक्रसत असताना अशा संघर्षात वाढ होण्याची शक्यता आहे, त्या दृष्टीने ही तरतूदही कमी पडेल असे वाटते.

विदा वा क्लाउडसाठी तरतुदी

विविध खासगी व परदेशी उद्योगांना २०४७पर्यंत पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी लागणारा पाणीसाठा, ऊर्जा आणि त्याचा पर्यावरणावर येणारा ताण कसा मोजणार व त्याची किंमत कोण मोजणार? यापूर्वी चैनीच्या शीतपेयांचे उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्यांना उत्तेजन देताना, स्थानिकांच्या पिण्याच्या पाण्यावर व त्याच्या दर्जावर संक्रांत आल्याची उदाहरणे आहेत.

हवेतील कार्बन कमी करण्याच्या दृष्टीने संशोधन व सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी अनुक्रमे २० हजार व २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुढील पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे, हे स्वागतार्ह असले, तरी हे संशोधन प्रत्यक्षात उपयोगात येण्यास वेळ लागणार असल्याने त्याचे चांगले परिणाम दिसण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. याउलट हवामान बदलांचे दुष्परिणाम मात्र आत्ताच दिसू लागले आहेत.

छोट्या उद्योगांना उत्तेजन देताना, पदार्थांच्या पुनर्वापराला चालना दिली, त्यावरील जीएसटी कमी केला, तर व्यर्थवस्तू व्यवस्थापनातून संपत्ती निर्माण होते. कमी कौशल्ये असणाऱ्या व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला त्याचा लाभ होतो. विकेंद्रित स्वरूपाच्या उद्योगांना चालना मिळू शकते. १८ टक्के जीएसटी कायम ठेवल्यामुळे या दिशेने काही उत्तेजन मिळालेले नाही. रद्दीच्या देवघेवीवरील कर दोन टक्के असला तरी त्यातून तयार झालेल्या मालावर अगदी मोजक्या प्लास्टिकला व कागदाच्या पुनर्वापराला ५ टक्के जीएसटी आहे. एकूण पुनर्वापराचे प्रमाण, त्यातील प्लास्टिकचा व कागदाचा वाटा लक्षात घेता, दिलेल्या करसवलतीचा पर्यावरणास उल्लेखनीय फायदा होईल, असे दिसत नाही.

प्रत्यक्ष पर्यावरणाशी संबंधित नसलेला पण त्यावर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा- जागतिकीकरणाचा अंत होत आहे, अशी हाकाटी ऐकू येऊ लागली आहे. त्यामुळे स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्माण करणे, त्यातही उद्योगांसाठी पर्यावरणस्नेही तंत्रनिर्मिती व ते वापरण्यासाठी नवउद्यमींना उत्तेजन देणे गरजेचे आहे. त्याची सुरुवात होण्यासाठी संशोधनाकरिता तरतूद वाढवावी लागेल. यापुढे रुपया कसा आला आणि कसा गेला याचे गणित मांडताना त्याच धर्तीवर पर्यावरणाचा जमाखर्चही मांडणे अत्यावश्यक ठरेल. तरच खऱ्या अर्थाने अर्थसंकल्पांत पर्यावरणाचा किती गांभीर्याने विचार केला गेला हे सांगता येईल.

खासगी विमा आरोग्यहक्क देईल?

भारताला एका शाश्वत आरोग्य धोरणाची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय पातळीवर याविषयी चर्चा होत नाही आणि या संदर्भातील प्रारूप विकसित होत नाही तोपर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ मागील पानावरून पुढे अशाच धर्तीवर सुरू राहतील...

सौमित्र जोशी
आरोग्य अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
soumitrajoshi12071993
@gmail. com

भारताने १९९० च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. आरोग्य क्षेत्रावरही याचे दूरगामी परिणाम झाले. नंतर आलेल्या सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी आरोग्य खर्च आणि योजनांना कात्री लावली. डाव्यांच्या पाठिंब्यावर उभ्या असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मात्र आपल्याला ‘नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन’, ‘आशा’ या प्रकारच्या नवीन कल्याणकारी योजना आणलेल्या दिसतात. अर्थात आरोग्यावरचा खर्च एकंदरीत कमी असला तरी सर्वच सरकारांच्या काळात मातामृत्यू, बालमृत्यू, लसीकरण इत्यादी कार्यक्रमांवर बऱ्यापैकी लक्ष देण्यात आले. गेल्या १५ वर्षांत एकूण सरकारी आरोग्य खर्च हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १ ते १.८ टक्के होता. देशातील एकूण सरकारी आरोग्य खर्चापैकी साधारण ४२ टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलते तर राहिलेला ५८ टक्के वाटा हा राज्य सरकारे उचलतात. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आरोग्य मंत्रालयासाठी सुमारे एक लाख १० हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत; यापैकी ३९ हजार कोटी रुपये ‘नॅशनल हेल्थ मिशन’साठी राखीव आहेत. याचबरोबर ‘बायोफार्मा शक्ती’ उपक्रमांतर्गत पाच वर्षांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य हा राज्य सूचीतील विषय आहे त्यामुळे राज्यपातळीवर आरोग्य खाते कसे चालवायचे, या खात्यासाठी किती तरतूद करायची याचे निर्णय सर्वस्वी राज्य सरकारचे असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारवर या बाबतीत काही बंधने आहेत. परंतु आरोग्यासंबंधी एक महत्त्वाचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो, तो म्हणजे विमा. भारतात सध्या २८ खासगी तर चार सरकारी आरोग्य विमा कंपन्या आहेत. आरोग्य विमा कंपन्या वाढल्या असल्या तरी सद्यःस्थितीत केवळ १८ टक्के लोकांपर्यंत खासगी विमा पोहोचला आहे. खरे तर आर्थिक उदारीकरणामुळे आणि मार्केट एफिशियन्सीच्या तत्त्वानुसार, स्पर्धा वाढून स्वस्त आणि बहुतेक रोगांचा समावेश असलेला विमा सर्वांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित होते, पण तसे झालेले दिसत नाही. त्याचबरोबर गरजेच्या वेळी विमा कंपनी किती क्लेम सेटल करते आणि रुग्णालयाच्या देयकातील किती रक्कम कुटुंबाला भरण्यास सांगते याचा अनुभव सुज्ञ वाचकांना असेलच. या स्थितीला अर्थशास्त्रीय भाषेत बाजारपेठेचे अपयश म्हटले जाते. आरोग्य विमा बाजारपेठेच्या यशापयशाचे सखोल मूल्यांकन करण्यासाठी लागणारा सर्व कच्चा डेटा विमा नियमक (आयआरडीएआय) त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देत नाहीत.

आरोग्य धोरण कसे असावे याची काही प्रारूपे अस्तित्वात आहेत. एका बाजूला अमेरिकेचे खासगी विमा आधारित प्रारूप आहे तर दुसरीकडे पश्चिम युरोपातील वेलफेअर प्रारूपे अस्तित्वात आहेत. भारत या कुठल्याच प्रकारचे प्रारूप राबवत नाही. एका बाजूला सरकारने खर्च कमी केलेला असला तरी खासगी क्षेत्रदेखील खुजे राहिले आहे. भारतात खासगी क्षेत्राचा आरोग्य क्षेत्रातील वाटा जीडीपीच्या साधारण तीन टक्के आहे, अमेरिकेत हाच वाटा जीडीपीच्या ९.५ टक्के आहे. तर भारतामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा आरोग्यातील वाटा जीडीपीच्या साधारण १.८ टक्के आहे, अमेरिकेत हाच वाटा साधारण ८.५ टक्के आहे. भारतात सरासरी आयुर्मान उंचावले आहे त्यामुळे येत्या काळात खर्च काढणारे कर्करोग, हृदयरोगासारखे आजार बळावणार आहेत. वृद्ध होत जाणारी लोकसंख्यादेखील वाढणार आहे. बहुतेक सरकारी रुग्णालयांत परिस्थिती बिकट आहे आणि दुसऱ्या बाजूला विमा उत्पादनेही तितकी भरवशाची नाहीत. परिणामी कुटुंबात खर्च काढणारे एखादे मोठे आजारपण आले तर फक्त गरीब नाही तर उच्च मध्यमवर्गीयदेखील आयुष्याची सारी पुंजी गमावून बसू शकतात.

सध्याचा परिस्थितीत भारताला एका शाश्वत आरोग्य धोरणाची आवश्यकता आहे. हे आरोग्य धोरण जर्मनीच्या सामाजिक विम्यासारखे असावे, ब्रिटनच्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवेसारखे (एनएचएस)सारखे असावे की भारताने स्वतःचे काही नवीन प्रारूप तयार करावे, यावर संसदेत आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर साधक-बाधक चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सद्यःस्थितीत आरोग्य विमा असणाऱ्यांचे क्लेम न्याय्य पद्धतीने मिळावेत म्हणून केंद्र सरकार विमा नियमकाचे (आयआरडीएआय) हात बळकट करू शकते. अर्थात राष्ट्रीय पातळीवर याविषयी चर्चा होत नाही आणि या संदर्भातील प्रारूप विकसित होत नाही तोपर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ मागील पानावरून पुढे अशाच धर्तीवर सुरू राहतील.

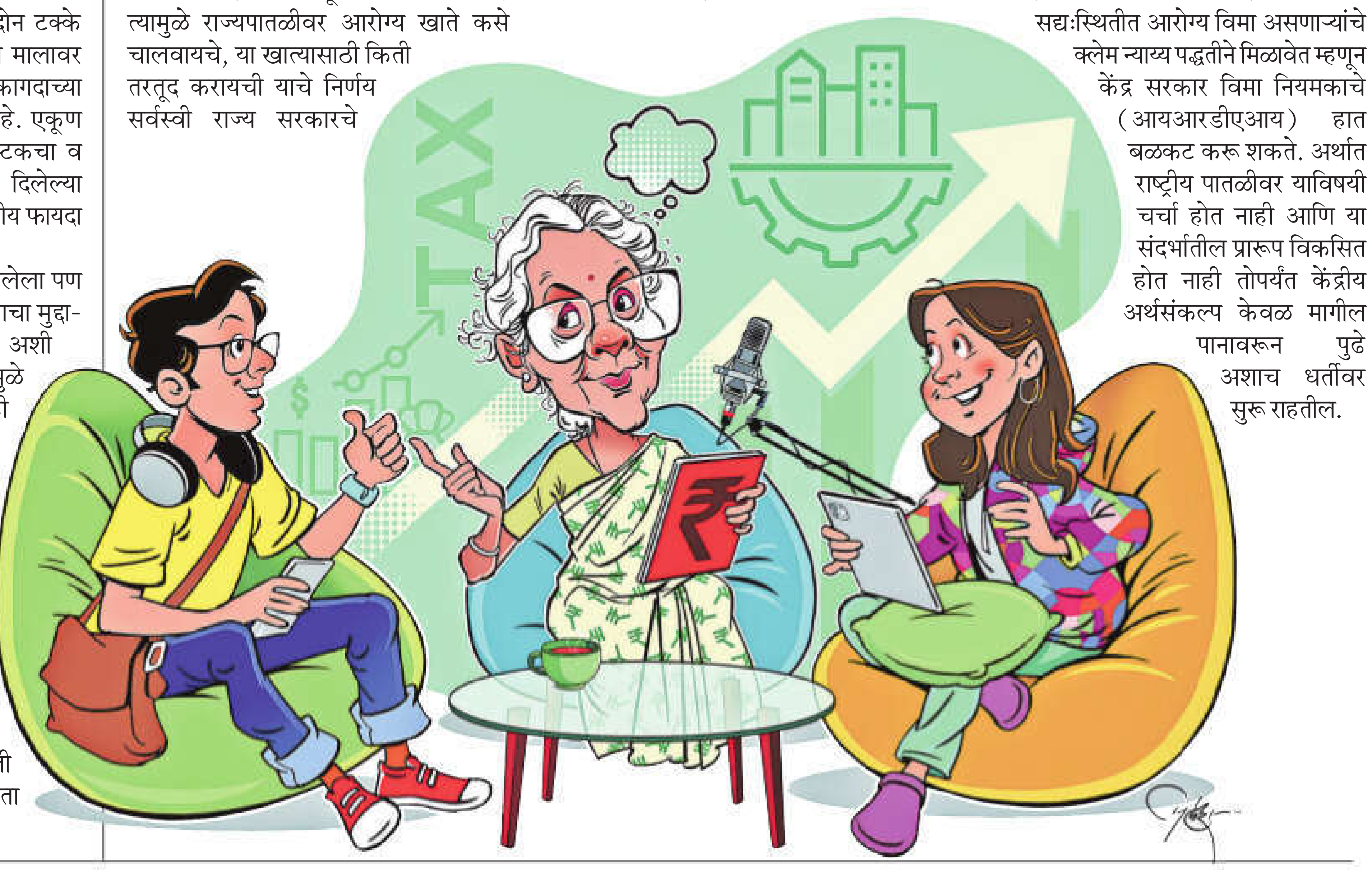

खगोल शास्त्रज्ञांसाठी सुखद धक्का!

लडाखमध्ये एनएलओटी या अतिशय उपयुक्त दुर्बिणीची उभारणी, आंध्र प्रदेशात नवीन तारांगण आणि खगोल प्रशिक्षण संस्था या घोषणांनी अंतराळ संशोधनाचा मार्ग प्रशस्त होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

प्रा. अनिकेत सुळे
होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र
aniket.sule@gmail.com

या वेळच्या अर्थसंकल्पात खगोल शास्त्रज्ञांसाठी खास घोषणा झाली आहे. दोन नवीन दुर्बिणी, एका महत्त्वाच्या दुर्बिणीचे नूतनीकरण आणि एक नवीन प्रशिक्षण संस्था अधिक तारांगण या घोषणेत अंतर्भूत आहे.

राष्ट्रीय महा दृश्य-अवरक्त प्रकाश दुर्बीण (नॅशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलिस्कोप- एनएलओटी) ही लडाखमधील हान्ले या गावी उभारली जाणार आहे. या दुर्बिणीच्या आरशाचा व्यास हा दहा मीटरहून अधिक असेल. जगभरात सध्या ८-१२ मीटर व्यास असलेल्या दहा ते पंधरा दुर्बिणी कार्यरत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे खगोल संशोधन याच दुर्बिणींच्या साहाय्याने होते. आता तर २५ मीटरहून अधिक व्यासाच्या तीन अतिमहाकाय दुर्बिणींसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यातील एका (तीस मीटरची दुर्बीण ः थर्टी मीटर टेलिस्कोप- टीएमटी) प्रकल्पात भारताची भागीदारीदेखील आहे. पण आजघडीला भारतातल्या सर्वांत मोठ्या दृश्यप्रकाश दुर्बिणीचा व्यास हा फक्त ३.४ मीटर आहे. जागतिक दर्जाची खगोल निरीक्षणे करण्यासाठी, तसेच टीएमटी तयार होण्यापूर्वी भारतीय खगोल शास्त्रज्ञांना मोठ्या दुर्बिणींवर काम करण्याचा अनुभव देण्यासाठी एक ८-१२ मीटर व्यासाची दुर्बीण भारतात असणे आवश्यक होते.

दुसरी मोठी दुर्बीण म्हणजे राष्ट्रीय महा सौर दुर्बीण (नॅशनल लार्ज सोलार टेलिस्कोप- एनएलएसटी) ही लडाखमधीलच पँगाँग सरोवराकाठी उभारली जाईल. आकाराचा विचार करता सध्या आपली सर्वांत मोठी सौर दुर्बीण ही उदयपूर येथे असून तिच्या आरशाचा व्यास हा साधारण ५० सेंटीमीटर आहे. तर एनएलएसटीचा व्यास त्याच्या पाच पट म्हणजेच अडीच मीटरहून अधिक असेल. सूर्याचे निरीक्षण करताना दुर्बिणीला सतत थंड करावे लागते, म्हणून मोठ्या सौर दुर्बिणी सहसा तलावाकाठीच बांधल्या जातात. पँगाँगचे पाणी हे अधिकच थंड असल्याने त्याचा निरीक्षणांना फायदा होईल. त्याचबरोबर चीन सीमेच्या जवळ बांधल्या जाणाऱ्या या मोठ्या प्रकल्पाने भारताचा या क्षेत्रावरील दावाही बळकट होईल.

हान्ले हे भारताचे ‘वेधशाळांचे गाव’ आहे. आता तर तेथे भारतातील पहिले ‘अंधाऱ्या आकाशाचे राखीव क्षेत्र’ जाहीर झाले आहे. या हान्लेमध्ये एकवीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला पहिली दुर्बीण उभारली गेली ती म्हणजे दोन मीटर व्यासाची हिमालयीन चंद्रा दुर्बीण (एचसीटी). २५ वर्षांनंतर या दुर्बिणीची यंत्रसामग्री आणि त्यावरील शास्त्रीय उपकरणे जुनी झाली असून त्यांचे नूतनीकरणदेखील या अर्थसंकल्पातली एक महत्त्वाची घोषणा आहे.

आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी अमरावती येथे एका नवीन तारांगणाची, तसेच त्याबरोबरीने खगोल प्रशिक्षण संस्थेची घोषणा करण्यात आली आहे. आपण नेहमी जी तारांगणे पाहतो त्यांत मोठ्या घुमटाच्या आत प्रक्षेपक (प्रोजेक्टर) बसवलेले असतात आणि घुमटाच्या अंतर्भागात आकाश प्रक्षेपित केले जाते. मात्र आता म्हैसुरूमध्ये एक नवीन तारांगण बांधले गेले आहे ज्यात अख्ख्या घुमटभर एलईडीचे पडदे आहेत. त्यामुळे प्रक्षेपकांची गरजच नाही. यातून तयार होणारे आकाशाचे चित्र हे इतर तारांगणांपेक्षा अनेक पटींनी चांगले असते. आता याच नवीन प्रकारचे दुसरे तारांगण अमरावती येथे बांधले जाईल. या सर्व प्रकल्पांतून भारतातील खगोल संशोधनाला नव्याने चालना मिळेल.

परदेश प्रवासाचा मार्ग अधिक सुकर...

परदेश प्रवास करू इच्छिणाऱ्यांचा मार्ग या अर्थसंकल्पाने काहीसा सुकर केला आहे, मात्र भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष धोरणात्मक पावलं उचलल्याचं दिसत नाही.

वीणा पाटील
संस्थापक, वीणा वर्ल्ड
veena@veenaworld.com

अर्थसंकल्पाकडे पर्यटनाच्या दृष्टीने पाहताना केवळ आकडे किंवा सवलती नव्हे, तर दिशा आणि दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचे ठरतात. २०२६च्या अर्थसंकल्पात पर्यटनासाठी थेट आर्थिक सवलती जाहीर झालेल्या नसल्या, तरी पर्यटन व्यापक, दर्जेदार आणि भविष्योन्मुख व्हावे, यासाठीचे प्रयत्न स्पष्टपणे जाणवतात. वैद्यकीय पर्यटनासासाठी पाच प्रादेशिक केंद्रांची उभारणी करून भारताला जागतिक आरोग्य-पर्यटनाच्या नकाशावर ठामपणे उभं करण्याचा मानस आहे. आधुनिक रुग्णालयं, तपासणी सुविधा, उपचारांनंतरची निगा, पुनर्वसन आणि आयुष प्रणाली यांचा एकत्रित विचार यात दिसतो. त्याचबरोबर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम व पूर्व घाट, समुद्रकिनारे आणि पक्षीनिरीक्षण क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

लोथल, धोलाविरा, सारनाथ, हस्तिनापूर, लेह पॅलेससारख्या ऐतिहासिक स्थळांना केवळ अवशेष न ठरवता, कथा आणि संदर्भ सांगत खास अनुभव देण्याचा प्रयत्नही उल्लेखनीय आहे. सीप्लेन सेवा, बौद्ध परिपथांचा विकास, साहसी पर्यटनासाठी ट्रेल्स आणि मार्गदर्शकांसाठी प्रशिक्षण योजना यातून पर्यटनाकडे अनुभव, गुणवत्ता आणि शाश्वतता या अंगांनी पाहिलं जात असल्याचं दिसतं.

हे सगळं पाहिलं, तर २०२६चा अर्थसंकल्प पर्यटनासाठी ‘तात्काळ लाभ’ देणारा नाही, तर दीर्घकालीन पाया घालणारा आहे.

एक छोटा पण अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय विशेष लक्ष वेधून घेतो, तो म्हणजे परदेशी पर्यटनावरचा टीसीएस (टूर बुक करताना भरावा लागणारा एक कर) सरळ दोन टक्क्यांवर आला आहे. हा बदल गेली कित्येक वर्षं अपेक्षित होता.

टीसीएस नंतर परत मिळतो, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण प्रश्न होता रक्कम अडकण्याचा. आधीची पद्धत अशी होती- परदेशी टूर घेतली, तर पाच टक्के टीसीएस आणि खर्च ठरावीक मर्यादेपलीकडे गेला, तर पुढे थेट २० टक्के. परदेशी टूर म्हणजे काही हजारांची गोष्ट नसते. पाच टक्के म्हणजे रक्कम लक्षणीय असते. ती लगेच परत मिळत नाही. कधी काही महिने, कधी संपूर्ण आर्थिक वर्षभर अडकून पडते. त्यामुळे काही पर्यटक परदेश प्रवास पुढे ढकलून देशांतर्गत प्रवासाचा पर्याय निवडत. या पार्श्वभूमीवर टीसीएस दोन टक्क्यांवर येणं हा मोठा दिलासा आहे. आता एकच दर असल्यामुळे प्रवासी आणि टूर ऑपरेटर दोघांसाठीही प्रक्रिया सुलभ होईल. कोणतेही स्लॅब, कोणतीही अट, कोणताही गोंधळ नाही. परिणामी, पर्यटनासाठी परदेशी जाणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते.

भारतासारख्या विकसित होत असलेल्या देशात, प्रत्येक नागरिकाने आजूबाजूचं जग पाहणं गरजेचं आहे. जग कसं चालतं, व्यवस्था कशा उभ्या राहतात, समाज कसा घडतो हे प्रत्यक्ष अनुभवण्यासारखं आहे. परतावा कधी मिळतो, कोणत्या आर्थिक वर्षात मिळतो याबाबत गोंधळ होऊ शकतो. काहींना वाटू शकतं – ‘आधी जास्त परत मिळायचा’ पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. आधी जास्त परत मिळायचा, कारण आधी जास्त रक्कम अडकत असे. आता ती कमी झाल्यामुळे कमी पैसे परत मिळतात. ही धोरणाची नाही समजुतीची अडचण आहे.

भारताला आपण अभिमानाने ‘इन्क्रेडिबल इंडिया’ म्हणतो. खरंतर जगात जिथे जे काही पाहायला मिळतं, त्याचं काही ना काही रूप भारतात आहे. तरीही, या अर्थसंकल्पात परदेशी पर्यटकांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी, थेट घोषणा फारशा दिसत नाहीत, ही गोष्ट नोंद घेण्यासारखी आहे. वैद्यकीय पर्यटन, बौद्ध परिपथ, वारसास्थळांचा विकास यांतून दीर्घकालीन दृष्टिकोन दिसतो, पण भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष धोरणात्मक पावलं उचलल्याचं दिसत नाही. हे थोडंसं खटकणारं असलं, तरी सरकारकडे या संदर्भात दीर्घकालीन आराखडा असावा, अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. कदाचित पुढील अर्थसंकल्पात भारताला जागतिक पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे मांडण्यासाठी पावलं उचलली जातील, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.

डेलूलू!

औद्योगिक उत्पादनवाढ, लघुउद्योग आदींवरला यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा भर योग्यच; पण शहर विकास, बँकिंग, उच्चशिक्षण यांबाबत तसे म्हणता येत नाही...

प्रत्येक नवी पिढी काही एक नवीन आव्हाने घेऊन जन्माला येते आणि त्या आव्हानांचे वजन तीस जन्मभर वाहावे लागते. सध्या 'मिलेनियल्स', 'जेन झी' अशा पिढ्यांची चर्चा प्रत्येक पातळीवर ऐकू येते. जे बाजारात विकले जाते ते विकणे हे कोणत्याही राजकारण्यांचे आवडते कर्तव्य. त्यानुसार या संकल्पना राजकारण आणि अर्थकारणातही आल्या आणि साहजिकच त्यांचे प्रतिबिंब निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आजच्या अर्थसंकल्पात पडले. त्यांनी सादर केलेला हा सलग नववा अर्थसंकल्प. हा एक विक्रम. त्यासाठी त्या निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. इतका सलग विश्वास एखाद्यावर एखाद्या पंतप्रधानाने दाखवणे ही बाबही तशी दुर्मीळ. निर्मला सीतारामन यांच्यावरील विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग नऊ वर्षे कायम ठेवला. ही बाब त्यांच्या नेतृत्वातील सकारात्मकता दर्शवणारी. त्याबाबत त्यांचेही अभिनंदन आवश्यक. आता अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण. ते दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्यात अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या काही नावीन्यपूर्ण कल्पनांवर भाष्य असेल आणि दुसरा टप्पा या 'मिलेनियल्स', 'जेन झी' अशांस उद्देशून केलेल्या 'युवाशक्ती- प्रणीत अर्थसंकल्पा'बाबतचा असेल.

या अर्थसंकल्पात निर्मलाबाईंचा काही नवीन करण्याचा निर्धार खचितच दिसतो. सूक्ष्मजीवशास्त्र तंत्रज्ञानातील विकास, दुर्मीळ खनिजांचे उत्खनन, भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक 'सेमी कंडक्टर' विकास आदींसाठी विशेष मोहिमांचे संकल्प अर्थमंत्र्यांनी यंदा सोडले. ते सर्वच स्वागतार्ह. विशेषतः 'आर्टिफिशल इंटेलिजन्स' (एआय) विकासासाठी यांची गरज आहे. वास्तविक 'एआय'ची बस आपली चुकल्यात जमा आहे. चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आदींनी या क्षेत्रात घेतलेली आघाडी इतकी मोठी आहे की ती भरून काढण्याचे स्वप्नही आपण पाहू शकत नाही हे वास्तव. परंतु मागे पडलो म्हणून पुढे जाण्यासाठी सुरुवातच करायची नाही, असे नसते. ती सुरुवात आता आपल्याकडून होऊ लागलेली आहे, ही बाब महत्त्वाची. वस्त्रोद्योग हे आपले एक महत्त्वाचे क्षेत्र. परकीय चलन मिळवून देणारे. त्या क्षेत्राच्या विकासाचा निर्धारही अर्थसंकल्पात आहे. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे आपल्या तिरुपूर ते सुरत व्हाया भिवंडी/ इचलकरंजी येथील सर्व संबंधित उद्योगांस फटका बसला. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्धार महत्त्वाचा. अर्थसंकल्पात असाच स्वागतार्ह उल्लेख आढळतो तो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राबाबत. कोणताही आजचा बडा उद्योग हा कालचा लघु वा मध्यम वा सूक्ष्म उद्योग असू शकतो. प्रयत्नांच्या जोरावर तो मोठा होतो. या प्रयत्नांस सरकारची जोड देण्याची इच्छा अर्थसंकल्प व्यक्त करतो. लहान उद्योगांस वाढीच्या प्रत्येक टप्प्यावर भेडसावणारे भांडवल, बाजारपेठ विस्तार आणि मनुष्यबळ हे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारतर्फे एक हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी स्थापन केला जाईल. ते छानच. तसेच क्रीडा साहित्यनिर्मितीसाठी काही ठोस पावले उचलताना सरकार दिसते. या देशात नद्या आणि सागरी मार्गांचे भले थोरले जाळे आहे. त्याच्या वापराचे निर्धार वारंवार व्यक्त होतात. पण या जाळ्यांतून वाहतूक होऊ लागल्याचे त्या प्रमाणात दिसत नाही. ताजा अर्थसंकल्प काही निश्चित मार्गांवर व्यापारी तत्त्वाने मालवाहतूक सुरू करण्याचा इरादा व्यक्त करतो. तो स्तुत्य. पर्यटन, साहसी खेळ यांस उत्तेजन देण्याचा अर्थसंकल्पातील विचारही स्वागतार्ह. या इच्छांकडे संशयाने पाहावे असे काही नाही.

> **...संरक्षण खर्च लक्षणीयरीत्या वाढवणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने आशेवर चालणाऱ्या समभाग बाजाराला मात्र निराशाच दिली...**

शहर विकास योजनांबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. महत्त्वाची महानगरे वगळता अन्य 'ब', 'क' दर्जाची शहरे निवडून त्यांचे आर्थिक विकास क्षेत्रात रूपांतर करण्याची प्रतिज्ञा या अर्थसंकल्पात आहे. वरवर पाहता त्यात गैर काही नाही. परंतु विश्लेषकाच्या सूक्ष्मदर्शकातून त्याकडे पाहिल्यास काही प्रश्न दिसतात. जसे की या लहान शहरांच्या विकासाची जबाबदारीही केंद्रच उचलणार असेल तर ती शहरे ज्या राज्यांत आहेत ती राज्य सरकारे आणि शहर पालिका मग नक्की काय करणार? दुसरे असे की गेले जवळपास दीड दशकभर विविध शहर विकास योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडल्या गेल्या. 'जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्निर्माण योजना'पासून अनेक. त्यातून या शहरांचा नक्की कोणता आणि किती विकास झाला, याचा काही ताळेबंद आहे काय? निदान 'पं. नेहरू' यांच्या नावाची योजना निरुपयोगी ठरली हे सिद्ध करण्यासाठी तरी या योजनांचा जमाखर्च सादर करणे ही सामाजिक जबाबदारी ठरते. आगामी योजनांच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी अशा जमाखर्चाची गरज आहे. ती पूर्ण न करताच नवनव्या योजना केंद्र शहरांसाठी जाहीर करत राहते. त्यातून राज्येही परावलंबी होतात आणि शहरे पंगू ती पंगूच राहतात. त्यात वस्तू/सेवा कराच्या अंमलानंतर राज्यांचे उत्पन्नस्रोत आटले आणि शहरे तर दुष्काळग्रस्त बनली. अशा प्रसंगी त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी उपाययोजना करावयाची की त्यांच्या विकासाची जबाबदारीही केंद्राने आपल्या उरावर घ्यायची हा प्रश्न.

असाच प्रश्न पडतो तो बँकिंग क्षेत्रास २०४७ सालापर्यंत महान बनवण्यासाठी काय करावे लागेल हे सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा ऐकल्यावर. बँकांच्या आजाराबाबत आपल्याकडे इतक्या वेळा निदान केले गेले आहे की आता नव्याने निष्कर्ष काढणार तरी काय? प्रतीक्षा आहे ती उपाययोजनांची. त्याचा पत्ता नाही. हे म्हणजे एखाद्याच्या गंभीर आजारावर प्रत्यक्ष औषधपाण्याची गरज असताना रुग्णास या वैद्यकाकडून त्या वैद्यकाकडे नेत बसण्यासारखे. भारतीय बँकांचा आजार कोणता आणि त्यावर उपाय काय, हे सर्व जाणतात. केंद्र सरकारने या बँकांतील स्वतःची मालकी कमी करणे ही या उपायांची सुरुवात. त्यास प्रारंभ न करता आणखी एका समितीमार्फत उच्चस्तरीय निदानातून काय हाती लागणार? बाकी सेवा क्षेत्र विकासादी मुद्द्यांसाठीही अशीच उच्चस्तरीय समिती नेमली जाणार आहे. समिती सदस्यांच्या भत्त्यापाण्याची सोय इतकेच काय ते.

आणखी एका मुद्द्यातील अनुस्यूत विरोधाभासाचा विचार व्हावा. हा मुद्दा शिक्षणाबाबतचा. एका बाजूने देशात अधिकाधिक परदेशी विद्यापीठे यावीत, देशात विद्यापीठनगरे - युनिव्हर्सिटी टाउन्स- स्थापन केली जावीत यासाठी सरकार विविध उपाययोजना, आर्थिक तरतुदी यंदाच्या संकल्पात जाहीर करते. त्या योग्यच. पण त्याच वेळी शिक्षणासाठी परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्यांस उत्तेजन, कर्ज सवलत इत्यादींचीही घोषणा करते. हा विरोधाभास धोरण-धरसोड दर्शवतो. भारतीयांनी परदेशात शिक्षणासाठी जावे ही आपली गरज नाही. उलट या परदेशात जाणाऱ्यांना थांबवावे ही आपली निकड. त्यासाठी परदेशी विद्यापीठांस येथे आवतण दिले जाते. असे असताना त्याच वेळी परदेशात शिकण्यास जाणे सरकार स्वस्त करते. परदेशातील सुंदर-स्वागतार्ह वातावरणात शिकणे स्वस्त होणार असेल तर येथे शिकायला थांबणार कोण आणि त्यांनी का थांबावे याचा विचार व्हावा.

बाकी आयकर वगैरेबाबत या अर्थसंकल्पात भाष्य करावे असे काही नाही. समभाग बाजारातील वायदे- उलाढालींवरील कर लावण्याची प्रतिक्रिया बाजाराने घसरून व्यक्त केलेली आहेच. वास्तविक परदेशी गुंतवणूकदार येथील गुंतवणूक काढून घेत असताना आहे ती अधिक कशी राहील हे पाहायला हवे होते. अर्थमंत्र्यांना बाजारपेठ निर्देशांकात रस नसावा. त्यामुळे असे काही त्यांनी केले नाही. अखेर बाजाराने आपले मत व्यक्त केले. ते तसेच राहिले तर गुंतवणूकदारांस यावेसे वाटेल का, इतकीच शंका. ती व्यक्त करताना पहलगाम हल्ल्याने आणि सिंदूर मोहिमेने शिकवलेला संरक्षण धडा केंद्र सरकार पटकन शिकले असे दिसते. त्यातूनच संरक्षणावरील खर्चात घसघशीत वाढ या अर्थसंकल्पात झाली. ते योग्य.

अन्यथा नजरेत ठळकपणे भरणारी बाब म्हणजे भांडवली गुंतवणुकीचा (कॅपेक्स) भार आपल्याच खांद्यावर वाहण्याचा सरकारचा यत्न. या सरकारने सत्ता हाती घेतली त्या वर्षी सरकारतर्फे होणारा भांडवली खर्च होता जेमतेम दोन लाख कोटी रुपये. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम साडेबारा लाख कोटींवर गेली असून त्यातून सरकारची परिस्थिती सुधारली हे जसे दिसते तसेच विकासाची जबाबदारी घेण्यातील खासगी क्षेत्राची उदासीनताही प्रकर्षाने अधोरेखित होते. म्हणजे विकसित भारतासाठी आवश्यक तितकी गुंतवणूक करण्याची जबाबदारी घेण्यास खासगी क्षेत्र तयार नाही, असा त्याचा अर्थ. हे योग्य नाही. यात बदल झाला नाही तर आजची 'जेन झी' या अर्थसंकल्पाचे वर्णन 'डेलूलू' (डेल्युजनल, भ्रामक/ स्वप्नाळू) असे करेल.

काटकसरीचा अर्थसंकल्प

डॉ. रुपा रेगे

प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस, सिम्बॉयोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स

देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसते...

गेल्या काही वर्षांत भारतीय धोरणकर्त्यांना (मग ते सरकारी क्षेत्रांतील असोत की रिझर्व्ह बँकेतील) अनेक आकस्मिक आव्हानांना तोंड देत देशाचे आर्थिक व वित्तीय स्थैर्य सांभाळावे लागत आहे. या आघातांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात बघावयास मिळते.

आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च रु. १२.२ लाख कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यांत इतर सहायक अनुदानांची भर टाकली तर एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनामधील या खर्चाचे प्रमाण आता ४.४ टक्के एवढे वाढले आहे जे २०१७-१८ मध्ये केवळ २.७ टक्के होते. तर दुसरीकडे 'संरक्षणा'वरील खर्च एका वर्षात १५.३ टक्क्यांनी वाढवून रु. ७.८४ लाख कोटींपर्यंत नेला आहे.

मंदावलेल्या रोजगारनिर्मितीची समस्या लक्षात घेऊन, वस्तूनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न झाला आहे. उदाहरणार्थ बायोफार्मा क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रथमच रु. ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच देशाला चिप निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० सुरू करून त्यासाठी प्रथमच रु. एक हजार कोटी देण्यात आले आहेत. इतरही काही योजना, उदा. एसएमई ग्रोथ फंड (रु ५०० कोटी), क्रीडा-क्षेत्रातील वस्तू (रु. ५०० कोटी), केमिकल पार्क्स (रु. ६०० कोटी) वगैरेंसाठी प्रथमच यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूनिर्मिती क्षेत्र, मायक्रोफूड प्रोसेसिंग क्षेत्र, नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, न्यूक्लियर पॉवर प्रकल्प, मत्स्यपालन क्षेत्र, वस्त्रोद्योग कार्यक्रम, नॅशनल फायबर योजना इत्यादी उद्योगांना यंदाही मदत सुरू ठेवण्यात आली आहे.

पण तरीही या अर्थसंकल्पाचे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाबरोबर गुणोत्तर घेतले तर ते फक्त १३.६ टक्के असून गेल्या वर्षीपेक्षा कमीच आहे. गेल्या वर्षी ते १४.२ टक्के होते. दरवर्षी हे गुणोत्तर कमी होत चालले आहे. कारण आपल्या सार्वजनिक कर्जाचा (Public Debt) वाढलेला बोजा. अनेक देश आजमितीला 'सार्वजनिक कर्जा'च्या वाढीव बोज्याने हैराण झाले आहेत.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातील (२०२६-२७) खर्च भागविण्यासाठी, केंद्रीय सरकारला रु. १७.२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे सरकारी रोखे बाजारातून काढावी लागणार आहेत. हा आकडा रोखेबाजारातील व्यापाऱ्यांच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. अनेक राज्य सरकारेही खर्च भागविण्यासाठी सरकारी रोखे बाजारातून कर्जे घेत असतात. सरकारी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात उचलल्या जाणाऱ्या या कर्जामुळे, व्याजाचे दर आणखी वर जाण्याची भीती आहे. एकीकडे केंद्रीय सरकार अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे दर कमी करत आहे ज्यामुळे सरकारचा 'महसूल' वाढत नाही. दुसरीकडे प्रोत्साहक खर्च भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेत आहे, ज्यामुळे सरकारी तसेच खासगी क्षेत्राला वाढीव व्याजाच्या दरांचा सामना करावा लागत आहे. याचा विपरीत परिणाम खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीवर होताना दिसतो. तसेच खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी व्याजदर खाली आणण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सफल होत नाहीत.

२०२५ च्या वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूक झपाट्याने कमी करत नेली. त्यामुळे त्यांना आकृष्ट करण्याच्या हेतूने 'ब्रोकरेज' वरील १८ टक्के जीएसटी काढून घेण्यात आला आहे. तसेच अनिवासी भारतीयांसाठी गुंतवणुकीच्या संधी वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. वैयक्तिक गुंतवणूक मर्यादा पाच टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली असून, एकूण परकीय होल्डिंगची मर्यादा २४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी मालमत्ता विक्रीवरील टीडीएस नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. पण या सगळ्यांमुळे भारतात येणारा परदेशी भांडवलाचा ओघ किती प्रमाणात वाढू शकेल हा प्रश्नच आहे. शेवटी परदेशी गुंतवणूकदार भारतातील उद्योगांची कामगिरी, ते कमावत असलेल्या नफ्यातील सातत्य, सरकारी कर्जाचे व्यवस्थापन या बाबींना सर्वाधिक महत्त्व देतात.

नेहमीप्रमाणेच आरोग्य व्यवस्था, ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, कौशल्य व पर्यटन या क्षेत्रांसाठी भरपूर घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पण प्रत्यक्ष आकडे पाहिले की हे खर्च देशाच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत किती नगण्य आहेत हे जाणवते. उदाहरणार्थ आरोग्य आणि कुटुंब-कल्याण मंत्रालयाला देणात आलेले वाटप हे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनात फक्त ०.२६ टक्के एवढेच आहे तर शिक्षण मंत्रालयाला देणात आलेले वाटप हे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनात फक्त ०.३५ टक्के आहे. वर्षानुवर्षे हे गुणोत्तर असेच थंडावलेले आहे.

फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी नवीन सकल राष्ट्रीय उत्पादन सीरिज प्रकाशित होईल. त्यातून नवीन आकडे, नवीन गुणोत्तरे बघावयास मिळतील. पण वाढलेल्या कर्जाची टांगती तलवार डोक्यावर असेल तर इच्छा असूनही एका मर्यादेपलीकडे धोरणकर्ते विशेष काही करू शकत नाहीत, हेच २०२६-२७ साठीचा अर्थसंकल्प स्पष्टपणे दाखवून देतो.

ruparege@gmail.com

बळहीन आकांक्षा

राथिन रॉय

प्रमुख, ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट

आर्थिक शहाणपणाचे पाठबळ असेल, तर धोरणात्मक दिशाबदल तरी करता येतो, तो तर नाही. मग आहे काय?

सरकारच्या एकूण खर्चाशी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) प्रमाण किती, यावर सरकारच्या आर्थिक प्रयत्नांचा आकार ठरतो. हे प्रमाण सातत्याने घटते आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ते १२.८ टक्के आणि २०१८-१९ मध्ये १२.२ टक्के होते. कोविडमुळे २०२०-२१ मध्ये ते १७.७ टक्क्यांवर गेले; पण पुन्हा ओहोटी लागून २०२३-२४ मध्ये ते १५ टक्के, २०२५-२६ मध्ये १३.९ टक्के होत येत्या आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) १३.६ पर्यंत येईल. म्हणजे, २०१६ पेक्षा थोडेसेच अधिक.

मिळणारा महसूल फारसा वाढत नसल्यामुळे सरकारी खर्चात घटतो. महसूलप्राप्तीची वाढ २०१६-१७ मध्ये ८.९३ टक्के होती आणि येत्या वर्षातही ती ८.९९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खासगीकरण, निर्गुंतवणूक यांतून मिळणारा महसूल आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ०.६ टक्के होता, तो येत्या आर्थिक वर्षात (२०२६-२७ मध्ये) तर ०.२ टक्केपर्यंत घसरला आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात (मार्च २०२६ पर्यंत) सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे ४७,००० कोटी रु. चे उद्दिष्ट ठेवले होते. केवळ ३४,००० कोटी रु. मिळाले. करांखेरीज अन्य स्रोतांकडून जास्त महसूल मिळत नाही, ही स्थिती २०१६-१७ मधील प्रमाण जीडीपीच्या १.७७ टक्के असल्याने होती. येत्या वर्षासाठीचा अंदाजही १.७ टक्के इतकाच आहे.

थेट करांपैकी, कॉर्पोरेट करातून मिळणारा महसूल दहा वर्षांपूर्वी जीडीपीच्या ३.२ होता, तर त्याच (२०१६-१७) आर्थिक वर्षात वैयक्तिक उत्पन्नावरील करातून मिळालेला महसूल जीडीपीच्या २.३ टक्के होता. २०२६-२७ मध्ये हे प्रमाण कॉर्पोरेट करासाठी ३.१ टक्के, तर वैयक्तिक उत्पन्नावरील करासाठी ३.७ टक्केच प्रस्तावित आहे.

योग्यरीत्या चालणाऱ्या कोणत्याही देशाचे सरकार मध्यवर्ती बँकेच्या नफा आणि लाभांशावर महसुलासाठी अवलंबून राहात नाही. भारतात मात्र, आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सरकारला दिलेल्या लाभांशाचा वाटा एकंदर करेतर महसुलापैकी २३ टक्के इतका होता तो येत्या आर्थिक वर्षात ४७ टक्के होणार असे सरकारच सांगते ! याचा अर्थ असा की, रिझर्व्ह बँकच सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील नफादायी तेलकंपन्या वा वित्तीय संस्थांपेक्षाही- जास्त महसूल पुरवते आहे. हे आर्थिक शहाणपण नव्हेच. कर्जे काढून सरकार खर्चाचे प्रमाण वाढवू शकते. या बाबतीत मात्र सरकारला श्रेय दिलेच पाहिजे. त्याने कर्जे आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच, आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ३.५ टक्के होती ती कोविड-वर्षात (२०२०-२१ मध्ये) प्रचंड ९.२ टक्क्यांवर गेली तरीही, भारत सरकारने सरत्या आर्थिक वर्षात ती ४.४ टक्के केली आणि येत्या वर्षात तूट ४.३ टक्केच ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त केला.

खर्च न वाढवताही दोन प्रकारे आगेकूच करता येते- पहिले म्हणजे गळके छप्पर आणि नळ दुरुस्त करणे; दुसरा प्रकार म्हणजे समष्टी अर्थशास्त्राला नवी दिशा देणे. यापैकी पहिला प्रकार सरकारने 'नवे प्राप्तिकर नियम' अखेर एकदाचे अमलात आणायचे ठरवण्यातून साधलेला आहे, तो अभिनंदनीयच. अर्थात, करप्रशासनच बदलण्यासाठी नोकरशाहीलाच सरळ करावे लागेल, ते महत्कार्य तूर्तास होईल असे वाटत नाही. प्रत्यक्ष कर खात्याच्या सचिवपदी असलेली व्यक्ती 'भारतीय महसूल सेवे'तली नसल्याने, फार अपेक्षा करता येत नाहीत. पण करप्रशासन बदलण्याच्या दृष्टीने सुरुवात तरी आजपासून झाली, इतकेच मानता येईल. अशाच सकारात्मक बाबी म्हणजे अतिमहत्त्वाची इलेक्ट्रॉनिक साधने उत्पादित करणाऱ्यांना २०३२ पर्यंत जाहीर केलेली जंगी करसवलत आणि २०४७ पर्यंत भारतातूनच विदामेघ (क्लाउड) सेवा कार्यरत होण्यासाठी विदा-केंद्रे (डेटा सेंटर्स) उभारण्यास वाव देण्याची घोषणा.

नवधोरणाची दिशा शोधण्याचा प्रयत्नही हा अर्थसंकल्प करत नाही. अर्थसंकल्पीय भाषणात विकास परिवर्तनाला गती देण्यासाठी किंवा काळाच्या तीन महत्त्वाच्या समस्या- महागाईपायी स्थिरच राहणारे वेतन, कुशल व अकुशल तरुणांची बेरोजगारी आणि बहुतेक आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कमी उत्पादकता- सोडवण्यासाठी कोणतीही सुसंगत रणनीती किंवा दृष्टिकोन सादर केला गेलेला नाही. राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक तसेच मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण यांतून खरे तर मध्यम मुदतीच्या समष्टी वित्तीय धोरणांचा अंदाज देता येऊ शकतो- तसे काही यंदाही झालेले नाही. गोम अशी की, कोणतीही अधिकृत भारतीय संस्था पुढल्या पाच-सहा वर्षांसाठीसुद्धा (२०३२ पर्यंत) आपल्या अर्थव्यवस्थेतल्या महत्त्वाच्या निर्देशकांचे विश्वसनीय अंदाज देत नाही. पण २०४७ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था कशी असेल, याबद्दल सारे नुसते बोलतात.

भविष्याची जाणीवच या अर्थसंकल्पाला नाही, असे नव्हे- ती आहे, त्यावर उपाय असावेत याचे भानही आहे; पण ते कसे याचे धोरण स्पष्ट नाही. म्हणजेच अर्थसंकल्पीय आकांक्षेला पुरेसे बळ नसून ती क्षीण आहे- एकंदरीत, आर्थिक विकास प्रत्यक्ष होत नसला तरीसुद्धा सत्ता आपलीच, याची खात्री असल्याचे हे लक्षण मानावे लागेल.

@EmergingRoy

तारेवरची कसरत

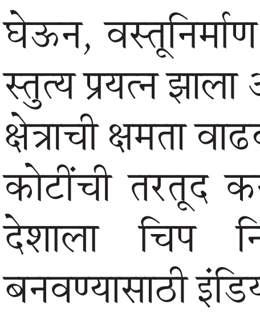

डॉ. अजित रानडे

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

देशाची वाढ अजूनही मुख्यत्वे सरकारच्या खांद्यावर आहे; खासगी गुंतवणूक अपेक्षेइतकी पुढे येत नाही; व्याजदर खाली येत नाहीत आणि विषमतेवर फारसे भाष्य नाही.

खरं सांगायचं तर, या अर्थसंकल्पाकडे आपण 'उत्सव' म्हणून पाहायचा की 'तणाव-चाचणी' (stress test) म्हणून, हा प्रश्नच आहे. या अर्थसंकल्पाकडे टाळ्या वाजवण्यासाठी बघण्यापेक्षा डोळे उघडे ठेवण्यासाठी बघायला हवं. कारण आज देशाच्या 'मॅक्रो' आकड्यांचा मुखवटा चमकदार आहे. आर्थिक वाढ उत्तम आहे, महागाई कमी आहे, बँका नफ्यात आहेत, एनपीए नियंत्रणात आहे, कॉर्पोरेट ताळेबंद निरोगी आहे, नफा वाढतो आहे. पण हा मुखवटा उतरवला की त्याखाली दिसतात काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न. आर्थिक वाढीचं इंजिन अजूनही सरकारच्या कॅपेक्सवरच का अवलंबून आहे? कमी महागाईचा आधार जर खाद्यपदार्थांच्या किमतींच्या घसरणीमुळे असेल, तर उद्या त्या किमती उलटल्या की काय? रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत जबरदस्त घसरण का? परकीय थेट गुंतवणूक म्हणजेच नेट एफडीआय या वर्षी शून्य का? आणि जागतिक भू-राजकारणाचा वारा जरा उलटा फिरला तर 'सेंटिमेंट'चा फुगा किती वेळ टिकणार? ग्रामीण मजुरी (wages) इतकी वर्षं ठप्प का आहे? आणि शेतीतील मजूरवर्ग कमी होण्याऐवजी वाढला (किंवा परत वाढतो) का?

म्हणूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला सलग विक्रमी नववा अर्थसंकल्प हा अतिउत्साही न होता काळजीपूर्वक व्यवहार्य (cautious pragmatism) दिसतो. हा 'शोभेचा मुकुट' नाही; तो कसरतीचा दोर आहे. वर चालायचंय, खाली पडायचं नाही. खर्च व उत्पन्न साधारण ७-८ टक्क्यांच्या दराने वाढवायचे, वित्तीय तूट ४.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणायची, हे ऐकायला तांत्रिक वाटेल. पण त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे : सरकार म्हणतंय, 'हात आखडता घेणार नाही; पण उधळपट्टीही करणार नाही.' हा संयम चांगला. पण या संयमाच्या मागे एक कठोर वास्तव आहे. सरकार आणि राज्यांची एकत्रित कर्जउचल 'मोठ्या लाटेसारखी' बाजारात येतेय. जवळजवळ ३० लाख कोटी रुपयांचे बॉण्ड्स बाजारात येत आहेत (borrowing). त्यामुळे व्याजदर खाली यायचा हट्ट सोडून वरच चिकटून बसतात. आणि मग खासगी गुंतवणूकदार म्हणतो, 'खर्चाचं भांडवलच महाग असेल तर मी नवा कारखाना/ क्षमता का वाढवू?'

इथंच देशाची वाढ हळूच राज्य-चालित होत जाते आणि 'खासगी गुंतवणूक' ही शब्दरचना भाषणापुरती राहते. सरकारचा कॅपेक्स चांगला; रस्ते, रेल्वे, बंदरे या सगळ्याची गरज आहे. पण सरकारचा कॅपेक्स खासगी कॅपेक्सची जागा घेऊ शकत नाही. कारण राज्य कायम 'इंजिन' होऊ शकत नाही; त्याने 'ट्रॅक' तयार करायचा असतो. इंजिन खासगी उद्योजकतेचं असायला हवं. आज नेमकं उलटं चाललंय. खासगी क्षेत्राचा खर्च वाढताना दिसत नाही, उलट तो तेवढाच राहिला आहे.

या वर्षीचा आणखी एक नाजूक मुद्दा म्हणजे कर महसूल. आकडे बघितले तर एक चित्र दिसतं की सरकार कर-उत्पन्नाच्या अंदाजांवर चालतंय; पण प्रत्यक्ष कर-संकलन तितकं वेगवान नसेल, तर वर्षअखेरीस 'शॉर्टफॉल'ची भीती असते. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत महसुलात केवळ तीन टक्क्यांनी वाढ झाली. मग पर्याय दोनचः (१) खर्च कमी करा... यात पहिला बळी बहुतेकदा भांडवली खर्चाचाच जातो; किंवा (२) उधारी वाढवा- आणि व्याजदर आणखी घट्ट करा. हे दोन्ही पर्याय पुढच्या वर्षाच्या वाढीसाठी घातक आहेत

काही समंजस गोष्टी

या अर्थसंकल्पात 'भविष्य' हा शब्द केवळ घोषणेत नाही, तर काही ठिकाणी धोरणात दिसतो. उदाहरणार्थ, सेवा-क्षेत्रात १० टक्के जागतिक हिस्सा मिळवायचा हे उद्दिष्ट आहे. आणि त्यात फक्त आयटी नाही, तर पर्यटन, आरोग्यसेवा, मेडिकल टुरिझम, कंटेंट, डिझाइन अशी मोठी व्याप्ती आहे. ही दिशा योग्य आहे. भारताला 'फॅक्टरी ऑफ द वर्ल्ड' व्हायचं असेल तर उत्पादन हवंच; पण 'ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड' ही ताकदही आपण वापरली पाहिजे. त्यासाठी कौशल्य, भाषा, मानके, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल क्षमता या सगळ्याची जोड लागते.

एमएसएमईकडे लक्ष देणंही योग्य आहे आणि मुख्य म्हणजे ते वेळेवर दिलं जात आहे. लहान उद्योगांना मारणारा विषाणू म्हणजे देणी देण्यात होणारा उशीर (पेमेंट डिले) आणि खेळत्या भांडवलाची कोंडी. मोठ्या कंपन्यांकडून वेळेत पैसे मिळाले नाहीत, तर छोटा उद्योग श्वास घेऊ शकत नाही. अशा समस्या सोडवणारे उपाय हीच खरी ''प्लंबिंग रिफॉर्म'' असते. ळफीऊच्या मदतीने लघुउद्योगांना (छोट्या व्यवसायांना) कार्यभांडवलासाठी कर्ज/वित्तपुरवठा सहज मिळू शकतो. पण अर्थमंत्र्यांनी एक महत्त्वाची ''सोप्या अंमलबजावणीची'' सुधारणा गमावली. जीएसटी पोर्टल थेट उद्यम (वऊअट) शी डेटा-लिंक करून देणी देण्यासाठी उशीर करणाऱ्यांना स्वयंचलितपणे दंड/दंडात्मक कारवाई करता आली असती. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांकडून लघुउद्योगांना वेळेत पैसे देण्याचा दबाव आपोआप वाढला असता.

पुण्यासाठी दोन मोठ्या घोषणा, पण अंमलबजावणीचे काय?

या अर्थसंकल्पात 'सिटी इकॉनॉमिक रिजन्स' (City Economic Regions)ची तरतूद महत्त्वाची आहे. त्यासाठी देशात पाच केंद्रांची निवड केली गेली असून त्यात पुणे परिसराचा समावेश आहे. यातून पुढच्या काही वर्षांत रु. पाच हजार कोटींची मदत/गुंतवणूक पॅकेज मिळेल, असा संकेत आहे. पुण्यासाठी ही मोठी संधी आहे. कारण पुणे आधीच ऑटो, ईव्ही, शिक्षण, आयटी, स्टार्टअप्स, हेल्थकेअर यांचा संगम आहे. पण स्पष्ट सांगायचे म्हणजेः पैसा येतो म्हणून विकास होत नाही. विकास होतो तो प्रकल्प निवड, अंमलबजावणी, संस्थात्मक क्षमता, आणि 'एकच खिडकी' नाही तर 'एकच जबाबदारी'मुळे.

दुसरी घोषणा, मुंबई पुणे हाय-स्पीड रेल ही घोषणा आकर्षक आहे, आणि योग्य अंमलबजावणी झाली तर मुंबईझ्पुणे एकत्रित श्रमबाजार बनू शकतो. ऑफिस, उद्योग, शिक्षण, आरोग्यसेवा या सगळ्याची 'कनेक्टिव्हिटी' वाढली तर उत्पादकता वाढते. पण या प्रकल्पाला नुसता 'स्पीड'चा उत्सव नको. 'स्टेशन्सभोवतीचा नियोजनहीन विकास', 'भूसंपादनाचे गोंधळ', 'प्रकल्प विलंब' आणि 'खर्चवाढ' याकडे दुर्लक्ष करतो. हाय-स्पीड रेल म्हणजे केवळ ट्रेन नाही; ती शहर-प्रदेश नियोजनाची परीक्षा आहे.

काय खटकतं?

जे बोलायला हवं होतं, ते टाळलं गेलं. हा अर्थसंकल्प 'विषमता' आणि 'संपत्ती-एकवटणे' याबाबत फार सावध आहे. म्हणजे त्याबाबत जवळजवळ मौनच बाळगलं आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वाढतेय, पण सर्वांचं उत्पन्न समान वेगाने वाढतंय का? मध्यमवर्गाचा पगार, असंघटित क्षेत्रातील मजुरी, ग्रामीण खरेदीशक्ती - इथं पुरेशी धारणा दिसते का? फक्त मॅक्रो पातळीवरील परिस्थिती अनुकुल आहे म्हणून समाधान मानता येत नाही.

दुसरी उणीव म्हणजे खासगी गुंतवणुकीसाठी अत्यंत निर्णायक असलेली जीएसटी-आयटीसीची रचना. विशेषतः भांडवली वस्तूंवरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट. उद्योगांनी मशिनरीवर, बांधकामावर, उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इनपुट्सवर जीएसटी भरला; पण त्या क्रेडिटचा वापर/ परतावा अडकला, तर तो जीएसटी गुंतवणुकीवरचा करच बनतो. या अर्थसंकल्पात हा मुद्दा ठोसपणे मांडायला हवा होता.

तिसरं, घरगुती आर्थिक बचत. आपल्याकडे बचत आहे, पण तिचा मोठा भाग भौतिक मालमत्तेत (सोने, जमीन) जातो. आर्थिक बचत कमी झाली की देशाच्या गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन भांडवल तयार होत नाही. मग परत कर्जावर अवलंबून राहावं लागतं आणि व्याजदरांच्या दोरावर चालण्याची वेळ येते. सरकारला इथं 'पैसा जमा करा' एवढंच सांगता येणार नाही, तर लोकांचा विश्वास वाढवणारी आणि दीर्घकालीन बचत आकर्षित करणारी वित्तीय साधने, नियमन, विवाद निवारण यावर ठोस काम करावं लागेल.

थोडं धाडस हवं होतं

हा अर्थसंकल्प जाणीवपूर्वक सावध आहे. काही ठिकाणी तो योग्य दिशेने बोट दाखवतो. उदा. सेवा-निर्यात, कौशल्य, क्लस्टर्स, एमएसएमई. पुण्यासाठी सिटी इकॉनॉमिक रीजनची निवड आणि मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल या दोन घोषणा तर मोठी संधी देतात.

पण एक वास्तवही नजरेआड करता येत नाही : देशाची वाढ अजूनही जास्त करून सरकारच्या खांद्यावर आहे; खासगी गुंतवणूक अपेक्षेइतकी पुढे येत नाही; व्याजदर खाली येत नाहीत; आणि विषमतेवर फारसं भाष्य नाही. पुढच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प 'सावध' असण्याबरोबरच विशेषतः गुंतवणुकीचे अडथळे काढण्यात, जीएसटी-आयटीसीसारख्या मूलभूत सुधारण्यात, आणि वाढीचा लाभ अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या स्पष्ट भाषेत अधिक ठाम असायला हवा. हा अर्थसंकल्प भविष्यासाठी क्षमता-निर्मितीकडे लक्ष देतो, पण त्याच वेळी राजकोषीय शिस्त राखत अतिशय सावधपणे 'तारेवरची कसरत' करतो.

खरं तर विकसित अर्थव्यवस्थेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणं ही एक रुटीन, जवळजवळ कंटाळवाणी बाब असायला हवी; त्यातून अचानक, तुटक (डिस्कॉन्टिन्युअस) बदल घडवण्याचं कारण नसावं. उलट, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेची स्थिती मांडणारं भाषण करावं आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टं ठरवून त्याची दिशा स्पष्ट करावी. विकसित भारतात आपण याची अपेक्षा करू.

ajit.ranade@gmail.com

१७.२ लाख कोटींची बाजार उसनवारी. २०२६-२७ मध्ये केंद्राकडून १७.२ लाख कोटी रुपयांची आजवरची सर्वाधिक बाजार उसनवारी केली जाईल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पाने केली. तरीही कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर हे २०२६-२७ मध्ये ५५.६ टक्क्यांपर्यंत सुधारण्याची अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्प
२०२६-२०२७

अनिवासी भारतीयांना देशांतर्गत भांडवली बाजाराविषयी आकर्षण आहे आणि त्यांना गुंतवणुकीची तीव्र इच्छा आहे. या स्वागतार्ह उपायामुळे केवळ भांडवलाचा ओघ वाढेल, इतकेच नाही तर चलन आणि भांडवली बाजार स्थिर होण्यासही मदत होईल.

- मनोज पुरोहित,
वित्तीय सेवा कर, कर आणि नियामक सल्लागार, बीडीओ इंडिया

वित्त/ बँकिंग

अर्थसंकल्पाने विकसित भारतासाठी बँकांच्या सज्जतेसाठी ‘उच्चस्तरीय समिती’ प्रस्तावित केली आहे. सरकारी बँकांच्या एकत्रीकरणाचा नवीन टप्पा त्यायोगे खुला होणे अपेक्षित आहे. मात्र भांडवली बाजारात याचे विपरीत परिणाम उमटले. स्टेट बँक ४ टक्क्यांनी, तर बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांमध्ये सर्वाधिक अनुक्रमे ६.५ टक्के आणि ५ टक्क्यांची घसरण झाली.

अनिवासी भारतीयांना थेट गुंतवणुकीस मुभा

- देशांतर्गत भांडवली बाजारातील तरलता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाबाहेर राहणाऱ्या भारतीय व्यक्तींना देशांतर्गत भांडवली बाजारात गुंतवणुकीची मुभा दिली आहे.
- अनिवासी भारतीयांना पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट योजनांतर्गत थेट भारतीय समभागांमध्ये गुंतवणूक करता येईल.
- भारताबाहेरील व्यक्तींना पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेद्वारे सूचिबद्ध भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी.
- या योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीसाठी गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

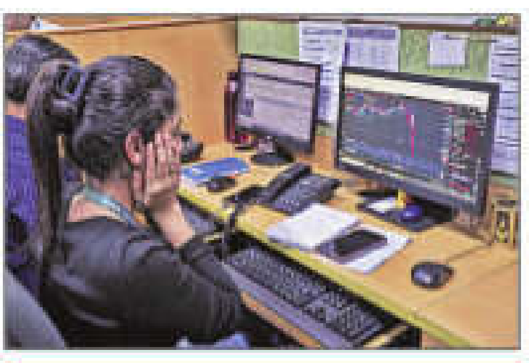

अर्थसंकल्पदिनी सेन्सेक्स

२०२६-२७	८०,७२२.९४	-१५४६.८४
२०२५-२६	७७,५०५.९६	५.३९
२०२४ - २५	८०,४२९.०४	-७३.०४
२०२४-२५ (अंतरिम)	७१,६४५.३०	-१०६.८१
२०२३-२४	५९,७०८.०८	१५८.१८
२०२२-२३	५८,८६२.५७	८४८.४
२०२१-२२	४८,६००.६१	२,३१४.८४

ऊर्जा स्थित्यंतराला गती

- अणुऊर्जा, बॅटरी एनर्जी स्टोअरेज आणि सोडियम अँटिमोनेट यातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात शुल्क कपातीची घोषणा अर्थसंकल्पात रविवारी करण्यात आली. यामुळे जीवाश्म इंधनाकडून, स्वच्छ अपारंपरिक ऊर्जेकडे स्थित्यंतरास गती मिळणार आहे.

- भारताने अपारंपरिक ऊर्जेचे ५०० गिगावॉटचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत गाठण्यासाठी वार्षिक किमान ५० गिगावॉटची क्षमता निर्माण करावी लागणार आहे. देशातील औष्णिक विजेची निर्मिती कमी करून त्याजागी अणुऊर्जेवर भर देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंवरील आयात शुल्क २०२५ पर्यंत माफ करण्यात आले आहे.
- सौर पॅनेलमध्ये सौर काचेचा वापर केला जातो. या सौर काचेच्या निर्मितीसाठी सोडियम अँटिमोनेटचा वापर होतो. आधी सोडियम अँटिमोनेटवरील आयात शुल्क ७.५ टक्के होते. आता ते माफ करण्यात आले आहे.

आज शिकतोय, ते उद्या उपयोगी पडेल?

अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि अर्थमंत्र्यांनी त्याला ‘युवाशक्ती ड्रिव्हन बजेट’ असं संबोधित केलं. आमच्यासारख्या तरुण पिढीचं लक्ष पुन्हा एकदा शिक्षण क्षेत्राकडे गेलं. पण आज शिक्षणाकडे पाहण्याची तरुण पिढीची दृष्टी बदलली आहे. बजेटच्या आकड्यांहून अधिक प्रत्यक्ष कृतीवर या पिढीचा अधिक भर आहे. आज आमच्यासारख्या युवा पिढीसमोर एकच प्रश्न आहे तो म्हणजे, ‘आज जे शिकतोय, ते उद्या प्रत्यक्षात उपयोगी पडणार आहे का?’

आज शिक्षण म्हणजे फक्त क्लासरूम, परीक्षा आणि डिग्री नाही; ते स्किल्स, टेक्नॉलॉजी, अनुभव आणि ‘जॉब रेडीनेस’ यांचा ‘कॉम्बो’ आहे. आज शिकण्याची आणि शिकवण्याची पद्धत बदललीय. ऑनलाइन कंटेंट, प्रॅक्टिकल लर्निंग, प्रोजेक्ट- बेस्ड अभ्यास, हे सगळं नॉर्मल झालंय. बजेटमध्ये डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेव्हलपमेंट आणि न्यू एज लर्निंग यावर दिलेला भर ही काळाची गरज आहेच. पण त्याचबरोबर ‘डिग्री आहे पण जॉब नाही’ ही समस्या अनेकांना जाणवते. त्यामुळे शिकताना थेट उपयोगी पडणाऱ्या स्किल्सवर लक्ष देणं आवश्यक आहे आणि सध्याच्या बजेटमध्ये तो प्रयत्न दिसतोय.

शुभम सरंगुले,
वकील, उच्च न्यायालय

कॉलेजची फी दिवसेंदिवस वाढतेय, ‘एज्युकेशन लोन’चा ताण अनेकांच्या डोक्यावर आहे आणि स्कॉलरशिप्स पुरेशा दिल्या जात नाहीत. यंदाच्या बजेटमध्ये लॅब्ज, हॉस्टेल्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आहेत, पण आमच्यासारख्या तरुणाईला एज्युकेशन परवडेल कसं यावर अधिक ठोस उपाय अपेक्षित होता...

‘फ्युचर स्किल्स’ हा या बजेटचा केंद्रबिंदू. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा, कोडिंग, रोबोटिक्स, डिझाइन थिंकिंग यासारख्या क्षेत्रांत शिकण्यासाठी क्रिएटर लॅब्स आणि स्किल-बेस्ड सेंटर्सची घोषणा सकारात्मक आहे. कारण आजच्या आधुनिक जगात डिग्रीपेक्षा स्किल्स वरचढ ठरतात. कॉलेजमध्ये शिकलेलं नोकरी करताना कसं वापरायचं, हे कळलं तरच शिक्षणासाठी घालवलेल्या वेळेचं आणि पैशांचं सार्थक होईल. या घोषणांमुळे शिकणं या ‘थिअरीत’ न अडकता ‘प्रॅक्टिकल’ होईल, अशी अपेक्षा कुठेतरी निर्माण होते.

‘युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स’ची कल्पना महत्त्वाची ठरते. इंडस्ट्रियल हब्सजवळ शिक्षणसंस्था असतील, तर कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातला गॅप कमी होण्यास मदत मिळेल. अभ्यासक्रम चालू असतानाच इंटर्नशिप, लाइव्ह प्रोजेक्ट्स आणि रिअल वर्क एक्सपोजर मिळालं, तर पुढे नोकरी शोधताना अडचणी कमी होतील. शिकत असतानाच ‘काम कसं असतं.’ याची सवय लागणं हे आज खूप आवश्यक आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘गर्ल्स हॉस्टेल’ ही घोषणा विशेष लक्ष वेधून घेणारी. मुलींसाठी विशेषतः उच्च शिक्षणाचा मार्ग अनेकदा राहण्याची गैरसोय असल्यामुळे बंद होतो. ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातून येणाऱ्या मुलींना राहण्याची सोय नसेल तर ही संधी हुकते. या निर्णयामुळे शिक्षण सुरक्षितता आणि समानता या दोन्ही गोष्टींना महत्त्व दिलं गेलं आहे, असं वाटतं. ‘डिजिटल लर्निंग’सोबत ‘टीचर अपस्किलिंग’वर भर देणंही योग्य पाऊल आहे. टेक्नॉलॉजी बदलतेय, अभ्यासक्रम बदलतोय, त्यामुळे शिकवण्याची पद्धतही अपडेट होणं गरजेचं आहे.

सेन्सेक्सला १५४६ अंशांची झळ

अर्थसंकल्पदिनी गुंतवणूकदारांच्या ११ लाख कोटींना तिलांजली

लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी

मुंबई : विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार २०१४ पासून सत्तेत आल्यापासून १५ वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी आठ प्रसंगी सेन्सेक्स नकारात्मक पातळीवर बंद झाला असून, गुंतवणूकदारांना एकत्रितपणे ११ लाख कोटी रुपयांची मत्ता त्यातून लयाला गेली आहे. रविवारीही अर्थसंकल्पाने झालेल्या निराशेने गुंतवणूकदारांना तब्बल ११ लाख कोटींचा फटका बसला आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने आतापर्यंत १५ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत, ज्यात २०१९ आणि २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सादर केलेल्या दोन अंतरिम अर्थसंकल्पांचा समावेश आहे. रविवारी अर्थसंकल्पदिनी गेल्या सहा वर्षातील सर्वात मोठी एक दिवसीय घसरण सेन्सेक्स आणि निफ्टी या प्रमुख निर्देशांकांनी अनुभवली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी समभाग उलाढाल कर (एसटीटी) वाढवण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये रविवारी सुमारे २ टक्क्यांची घसरण झाली. सकाळच्या सत्रातील वाढ गमावत, सेन्सेक्स २,३७०.३६ अंशांनी म्हणजेच, २.८८ टक्क्यांनी घसरला आणि दुपारच्या सत्रात ८०,००० च्या खाली ७९,८९९.४२ पातळीपर्यंत गडगडला. अखेरीस सेन्सेक्स १,५४६.८४ अंशांनी (१.८८ टक्के) घसरून ८०,७२२.९४ पातळीवर बंद झाला.

दुसरीकडे निफ्टी ४९५.२० अंशांनी (१.९६ टक्के) घसरून २४,८२५.४५ पातळीवर स्थिरावला. दिवसादरम्यान, त्याने ७४८.९ अंश गमावत २४,५७१.७५ ही सत्रातील नीचांकी पातळी गाठली होती.

अर्थसंकल्पात जागतिक व्यापार शुल्कामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांना बळ देण्यात आले आहे. या उपायांनंतरही, बाजाराची प्रतिक्रिया नकारात्मक राहिली आहे. वायदे बाजारातील व्यवहारांवर वाढवलेल्या एसटीटीमुळे निर्माण झालेल्या नकारात्मक दृष्टिकोनामुळे, बाजारात निराशादायी वातावरण होते, निरीक्षण जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे संशोधन प्रमुख विनोद नायर यांनी नोंदवले.

२८.७ लाख कोटी

केंद्राकडून २०२६-२७ मध्ये अंदाजित कर महसूल, २०२५-२६ साठी सरकारला करापोटी २६.७ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज.

१३ टक्के

वायदे बाजारातील उलाढालीवर करवाढीने ग्रो, एजंल वन, बीएसई लि. च्या समभागांत इतकी मोठी घसरण.

१४ अब्ज डॉलर

भारतात विदा केंद्रा (डेटा सेंटर) स्थापन करून त्याद्वारे जागतिक पातळीवर क्लाऊड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७ पर्यंत करमाफी अर्थसंकल्पात दिली गेली आहे. यातून सध्या १० ते १४ अब्ज डॉलर असलेल्या या बाजारपेठेत आणखी गुंतवणूक येईल.

२००० कोटी

माहिती-तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रासाठी सेफ हार्बर कलमात सुधारणा करून त्याची मर्यादा ३०० कोटींवरून, २,००० कोटी रुपयांवर.

भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटींवर

नवी दिल्ली : पायाभूत सुविधा विकासाला गती आणि आर्थिक विकासाला पाठबळ देण्यासाठी, पुढील आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चात ९ टक्के वाढ करून तो १२.२ लाख कोटी रुपयांवर नेण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
सीतारामन म्हणाल्या की, सार्वजनिक भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये २ लाख कोटी रुपये होता. त्यात आता अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. तो २०२५-२६ मध्ये ११.२ लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आला. आता आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी त्यात वाढ करून तो १२.२ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. सरकारने गेल्या दहा वर्षांत पायाभूत सुविधा विकासावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. देशातील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांच्या विकासावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. या छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील.

BANKING
DATA

बँकिंग २०४७ साठी उच्चस्तरीय समिती प्रस्तावित

लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी

मुंबई : पुढील टप्प्यातील बँकिंग सुधारणांची शिफारस करणारी आणि बँकिंग क्षेत्राच्या ताळेबंद, नफाक्षमता आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी उच्चस्तरीय बँकिंग समिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी अर्थसंकल्प मांडताना प्रस्तावित केली.

विकसित भारतासाठी म्हणजेच २०४७ सालातील उमद्या बँकिंग प्रणालीच्या संकल्पचित्राची मांडणी ही समिती करेल, असे अर्थमंत्र्यांनी या संबंधाने प्रतिपादन केले. तथापि आजवर स्थापित जवळपास तीन डझनभर बँकिंग समित्यांचा पूर्वानुभव पाहता प्रस्तावित समिती ही केवळ आणखी एक भर ठरू नये, असा उद्योग क्षेत्रात मतप्रवाह आहे.

ही जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, तिचे कार्यक्षेत्र हे स्पष्टपणे निर्धारित केले जाईल, असे या समितीबद्दलच्या साशंकतेला दूर करणारे उत्तर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिले. त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही अशा समितीचा विचार करत आहोत, जी संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राची तपासणी करेल, जेणेकरून ती २०४७ सालासाठी ठरविलेल्या दीर्घ पल्ल्याच्या उद्दिष्टानुरूप बँकिंग क्षेत्राचा चेहरा बदलवू पाहणाऱ्या नियोजनानुरूप एक एक पाऊल टाकण्यास मदत करणाऱ्या शिफारसी देऊ शकेल.’ भारताच्या आगामी अर्थविस्ताराच्या टप्प्यांशी जुळवून घेईल, अशा परिणामकारक आणि सुसज्ज बँकिंग प्रणाली साकारण्याचा उद्देश यामागे आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.

४३ समित्यांमध्ये भर

आजवर बँकिंग प्रणालीत सुधारणांसाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीत ४३ समित्यांनी कार्यकाळ पूर्ण केला असून, पैकी काहींच्या शिफारशी प्रकाशात आल्या, परंतु आंशिक अथवा शून्य अंमलबजावणी झाली. काही समित्या या आधीच्या समित्यांच्या अहवालांच्या फेरविचारासाठी, तर काही समित्यांचे अहवाल स्वीकारले गेले तरी त्यांना जाहीर स्वरूपही मिळू शकले नाही. काही ठळक समित्या अशा -

- **नरसिम्हम समिती १ व २** (बँकांची पुनर्रचना)
- **रंगराजन समिती** (बँकांचे संगणकीकरण)
- **राजन समिती** (जागतिक अरिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर सुधारणा)
- **गोयपोरिया समिती** (सेवा गुणवत्ता)
- **नचिकेत मोर समिती** (आर्थिक समावेशन)
- **आर. व्ही. गुप्ता समिती** (ग्रामीण पतपुरवठा)
- **पी. जे. नायक समिती** (सरकारी बँकांची स्वायत्तता)
- **उषा थोरात समिती** (बँकेतर वित्तीय कंपन्या)
- **ए. घोष समिती** (फसवणूक, अनिष्ट प्रथा)
- **के. माधव दास समिती** (नागरी सहकारी बँका)
- **एस.पी. तलवार समिती** (अशक्त सरकारी बँकांची पुनर्रचना)
- **बिमल जालान समिती** (नवीन बँक परवाने)
- **खन्ना समिती** (बुडीत कर्जे)

कर्तव्यपूर्ती... केवळ शब्दांचा खेळ!

आर्थिक पाहणी अहवालाने धोरणात्मक लवचिकतेसाठी शिस्तबद्ध स्वदेशीचा प्रस्ताव सुचवतानाच एक सुनियोजित त्रिस्तरीय रणनीतीचा उल्लेख केला होता. जागतिक आर्थिक अस्थिरतेमुळे अपरिहार्य ठरलेल्या आत्मनिर्भरतेसाठी अर्थमंत्री प्रयत्न करतील, अशीही शक्यता पाहणी अहवालाने निर्माण केली होती. मात्र, निर्मला सीतारामन यांच्या सलग नवव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात डामडौलच जास्त होता. भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक विकास, सर्वस्पर्शी प्रयासांबरोबरच कर्तव्यपूर्तीची पुरवणी जोडली. मात्र, कर्तव्याच्या तुलनेत केवळ शब्दांचा खेळच भासावा अशी त्याची स्थिती.

तीन कर्तव्ये:

१. आर्थिक विकासाचा वेग वाढवून तो कायम ठेवणे आणि त्यासाठी उत्पादकता वाढवून जागतिक दर्जाच्या सुधारणा निर्माण करणे.

२. जनतेचा आकांक्षा पूर्ण करून त्यांचे कौशल्य वाढवणे, त्यांच्या क्षमता वाढवणे आणि भारतच्या समृद्धी मार्गात त्यांना सहभागी करून घेणे

३. आणि तिसरे अर्थातच ‘सबका साथ सबका विकास’

आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवून निर्यात क्षमतांवर जोर देणे, पायाभूत सुविधांसाठी १२.२ लाख कोटींची भांडवली तरतूद, ‘चॅम्पियन’ लघू व मध्यम उद्योगांसाठी १० हजार कोटींचा निधी, शहरांना आर्थिक विकास केंद्र बनवण्यासाठीचा रोडमॅप, बायोफार्मा शक्ती आणि वैद्यकीय उत्पादनांवर भर, सेमिकंडक्टर मिशनसाठी ४० हजार कोटींची तरतूद अशा सहा क्षेत्रांसाठी अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी विशेष काही नसले तरीही मेडिकल टुरिझम, शैक्षणिक हब/शिक्षण आणि एव्हीजीसी क्षेत्राबद्दल प्रस्ताव असून, त्यावर भरीव तरतूद केली आहे. मेडिकल टुरिजम हब स्थापन करण्यासाठी सरकार सहाय्य देईल. ही केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच खाजगी कंपन्या सोबत भागीदारीत उभारली जातील. जेणेकरून विदेशातून आरोग्यसेवा घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांसाठी भारताला एक मोठी संधी मिळेल. या हब्समध्ये उच्च-स्तरीय उपचार, निदान, आरोग्य-शिक्षण आणि सेवा, पारंपरिक औषध, रिसर्च आणि पुनर्वसन सुविधा एकत्र असतील, ज्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत मेडिकल टुरिजममध्ये स्पर्धात्मकपणे उभा राहील.

सपक आणि अपेक्षित अर्थसंकल्प. ज्यात विशेष असं काहीच नाही. आगामी काळच दिशा ठरवेल तोपर्यंत ‘मागच्या पानावरून पुढे’ असेच चालू राहील.

अजय वाळिंबे
भांडवली बाजार अभ्यासक

अर्थसंकल्पात शिक्षणातून रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माणावर भर दिला गेला आहे. पाच नवीन शैक्षणिक टाऊनशिप्स विकसित करण्याची घोषणा आहे. या टाऊनशिप्स उद्योग, संशोधन, कौशल्य प्रशिक्षण आणि उच्च शिक्षण यांना एकत्रित करून विद्यार्थ्यांना थेट रोजगारक्षम कौशल्य देतील. यामध्ये विद्यापीठ, कॉलेजखेरीज आवश्यक निवासी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा समाविष्ट आहेत. या शिक्षण नगरी स्थानिक अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यासाठी आणि उद्योग-शिक्षण समन्वय वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरतील. विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध केली जाईल. याशिवाय १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. लहान व मध्यम वयोगटातील विद्यार्थ्यांना एव्हीजीसी संबंधित कौशल्य देणे, रोजगार-सक्षम बनवणे आणि भारताला ग्लोबल क्रिएटिव्ह सेक्टर म्हणून उभे करणे आहे.

मालवाहतुक सुलभ, जलद आणि स्वस्त करणे आवश्यक होतेच. सध्याचा लॉजिस्टिक्स खर्च जीडीपीच्या १४% आहे तो ८-९% पर्यंत कमी करणे हा उद्देश आहे. हा उद्देश यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात पूर्ण होईल. भारतामध्ये दोन मुख्य कॉरिडॉर आधीच सुरू असून प्रस्तावित मुंबई-पुणे आणि दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या या कॉरिडॉरचा मोठा फायदा पुणे ऑटो क्लस्टर, जेएनपीटी तसेच नवी मुंबई एयरपोर्ट मूळे महाराष्ट्राला होईल अशी अपेक्षा आहे.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र ढासळता रुपया, अनपेक्षित चलन वाढ, जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या रोजच्या नवीन घोषणा तर देशांतर्गत अनेक राज्यातून जाहीर झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ सारख्या लोकानुनयी योजना, राज्यांवरील वाढती कर्ज, उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ, कुशल कामगारांचा अभाव तसेच बेरोजगारी या सगळ्यां आव्हानांचा सामना करताना परदेशी गुंतवणूक आणणे, आर्थिक नियोजन करणे तसेच वित्तीय तूट कमी करणे तारेवरची कसरत ठरणार आहे. अर्थसंकल्पात, सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स अर्थात एसटीटी मध्ये दरवाढ जाहीर होताच शेअर बाजारात मोठी घसरण उडाली. अर्थात प्रस्तावित वाढ ही केवळ फ्युचर ऑप्शन व्यवहारांवर लागू होणार आहे आणि ती अपेक्षित होती. फ्युचर व्यवहारवरील कर दर ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्के, टीआर ऑप्शनवरील कर ०.१२५ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्के करण्यात आला आहे. सट्टेबाजीला आळा घालून दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी ही वाढ सुचवली असावी. कर चुकवेगिरीसाठी शेअर बायबॅकच्या वापराला निरुत्साहित करण्याच्या उद्देशाने, प्रवर्तकांना अतिरिक्त बायबॅक कर भरावा लागेल.

भास्कर इन्फो • महिला vs पुरुष

पांच साल में महिला निवेशक 3 गुना, नौकरी में दोगुनी बढ़ीं

कोविड के बाद टैक्स, नौकरी और निवेश तीनों क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक भूमिका मजबूत हो रही है। हालांकि, वर्कफोर्स में अब भी पुरुषों का वर्चस्व है। अब हर चौथी निवेशक महिला है।

करदाता; 5 साल में महिलाएं 37% बढ़ीं, पुरुष अब भी 3 गुना

2020-21 के बाद से तेजी से बढ़ीं महिला टैक्स पेयर्स

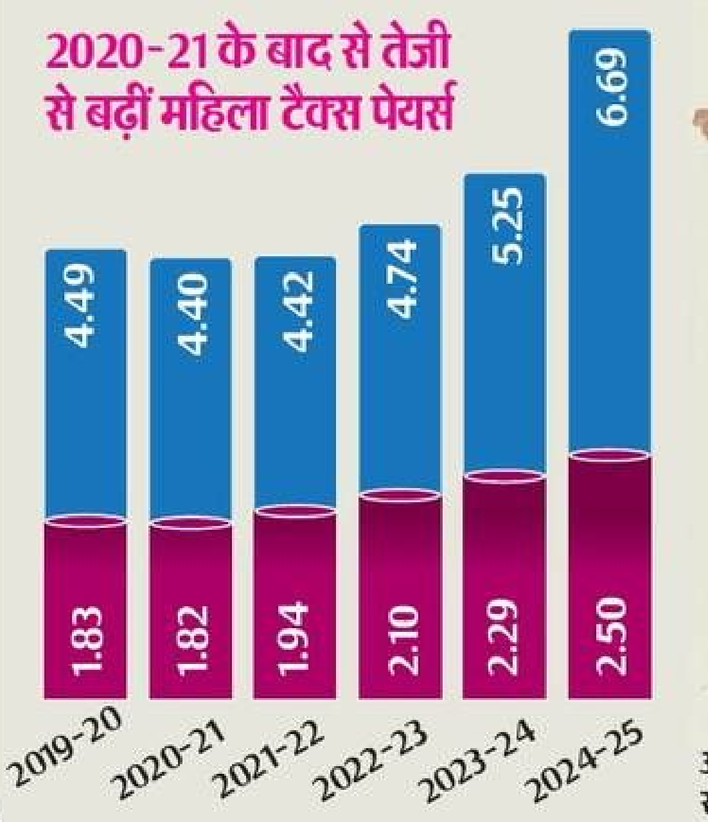

आंकड़े करोड़ में
स्रोत : आयकर विभाग व संसद

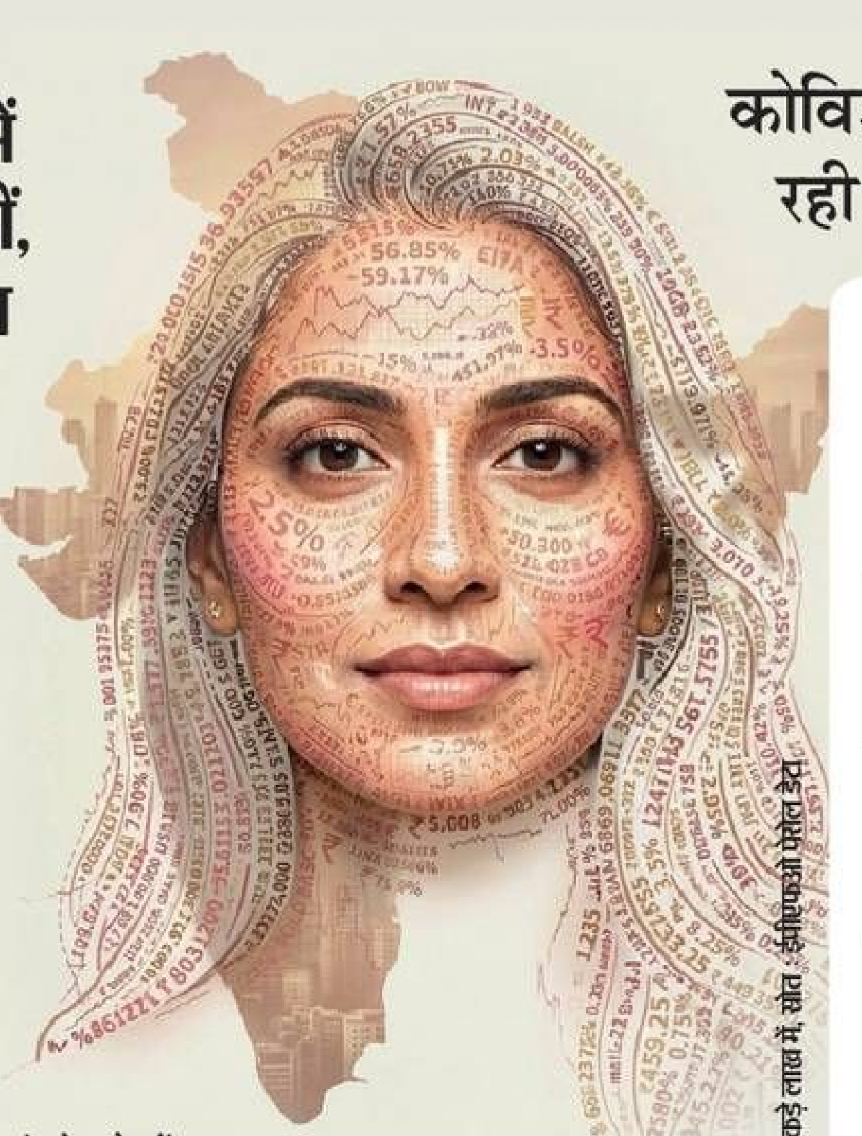

वर्कफोर्स; महिलाएं 70% बढ़ीं, पर हर महिला की तुलना में 4 पुरुष

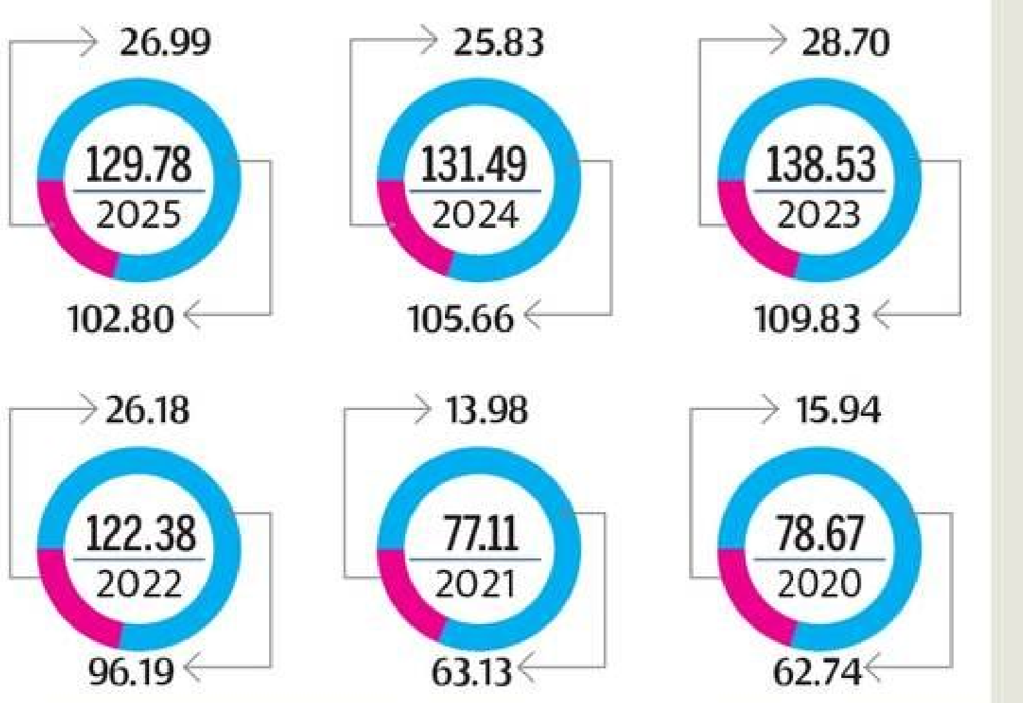

आंकड़े लाख में, स्रोत : ईपीएफओ पेरोल डेटा

निवेश; पुरुष हिस्सेदारी 9% घटी, महिलाएं इतनी ही बढ़ीं

वर्ष	कुल निवेशक	पुरुष	महिला
2025	12.0	9 (75%)	3 (25%)
2024	10.7	8.13 (76%)	2.57 (24%)
2023	8.0	6.24 (78%)	1.76 (22%)
2022	5.5	4.51 (77%)	0.99 (23%)
2021	4.0	3.36 (84%)	0.64 (16%)

- 2021 से 2025 के बीच पुरुष निवेशकों की हिस्सेदारी 84% से घटकर 75% तक आ गई है। महिला निवेशकों का हिस्सा 16% से छलांग लगाकर 25% तक पहुंच गया। यानी हर चौथी निवेशक महिला।
- महिला निवेशकों की संख्या 2021 में 0.64 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 3 करोड़ हो गई। यानी चार साल में महिला निवेशक लगभग 4 गुना बढ़ीं। निवेश के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

आंकड़े करोड़ में, स्रोत : एनएसई पल्स

स्टार्टअप; कुल 2 लाख में करीब एक लाख महिलाएं को-फाउंडर

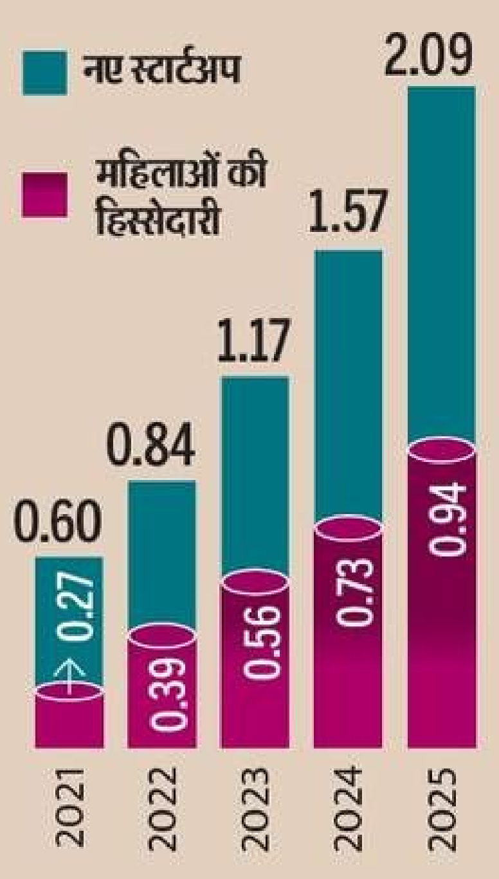

आंकड़े लाख में, स्रोत : डीपीआईआईटी, संसद, पीआईबी

पर्सनल फाइनेंस गाइड

पांच साल में 17 फीसदी बढ़ी निवेश योग्य संपत्ति

भारतीय परिवारों की कुल संपत्ति 1,300-1,400 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें निवेश योग्य वित्तीय संपत्ति करीब 35% है। बीते 5 साल में यह 17% बढ़ी है। ये पैसा बैंकों से निकलकर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और पीएफ जैसे ज्यादा रिटर्न वाले फाइनेंशियल मार्केट में जा रहा है।

पांच साल में म्यूचुअल फंड निवेश 6 गुना, शेयरों में भी दोगुना...

निवेश के साधन	2020-21	2024-25
इक्विटी (शेयर)	1.3%	2.1%
म्यूचुअल फंड	2.1%	13.1%
पीएफ, पेंशन फंड	16.6%	22.2%
छोटी बचत*	7.9%	6.5%
करेंसी	12.6%	5.9%
जीवन बीमा	18.7%	15%

*मुख्य रूप से पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, पीपीएफ छोड़कर

सबसे ज्यादा निवेश अब भी बैंक एफडी में ही...

वित्त वर्ष 2024-25 में कुल घरेलू वित्तीय बचत में एफडी समेत बैंक डिपॉजिट की हिस्सेदारी 35.2% रही। लेकिन यह लगातार घट रही है। 2023-24 में यह 38.7% और 2011-12 में 57.9% थी।

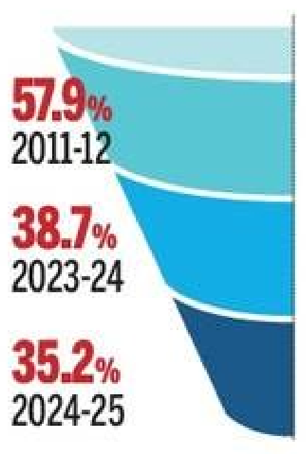

एफडी में निवेश घटने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि 5 साल से इसका औसत रिटर्न 7% से कम रहा। जबकि, इसी दौरान सीधे इक्विटी ने 16% और इक्विटी फंड्स ने सबसे ज्यादा सालाना 18% तक रिटर्न दिए।

रिटर्न देने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सबसे आगे

निवेश के साधन	1 साल	3 साल	5 साल
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट	6.0 - 7.5%	6.0 - 7.5%	6.0-7.0%
पोस्ट ऑफिस स्कीम्स	7.0 - 8%	7.0 - 7.5%	7.0-7.5%
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स	8 - 15%	15-22%	15-25%
सरकारी बॉन्ड्स	6.6 - 6.7%	6.5-7.0%	6.5-7.0%
सेंसेक्स	7.2%	11.81%	16%
ईपीएफ	8.25%	8.25%	8.25%

*रिटर्न सालाना कम्पाउंडेड (सीएजीआर)

भारतीयों के पास 24,000 टन सोना, पूरी दुनिया का 11%

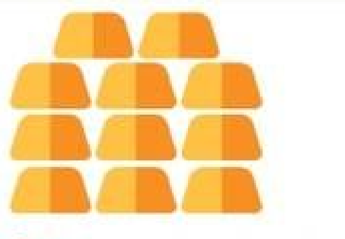

गोल्ड: भारतीय परिवारों के पास लगभग 24 हजार टन सोना है, जो पूरे वैश्विक भंडार का करीब 11 फीसदी तक पहुंच गया है।

इक्विटी: घरेलू इक्विटी होल्डिंग्स बढ़कर करीब 84 लाख करोड़ रुपए की हो गई हैं। देश में अभी 21.6 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं।

म्यूचुअल फंड: 31 दिसंबर तक देश में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एयूएम रिकॉर्ड 80.23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

स्रोत : रिजर्व बैंक, एनएसई, बीएसई, एम्फी, बेन-ग्रो रिपोर्ट

देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नींव

ग्रोथ एजेंडा: 7 अहम सेक्टर्स में एक लाख करोड़ रु. से अधिक के निवेश का 5 साल का रोडमैप

इंडस्ट्री की 3 चुनौतियों पर मेगा एक्शन

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली. बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने को इंडस्ट्री के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप पेश किया है। सरकार ने इंडस्ट्री के समक्ष पेश तीन बड़ी चुनौतियों का समाधान देने की बात की है। **पहली चुनौती-** लागत में प्रतिस्पर्धा की समस्या, **दूसरी-** एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और **तीसरी-** इंफ्रास्ट्रक्चर व टेक्नोलॉजी का गैप। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र ने 7 अहम सेक्टरों में 5 वर्षों में एक लाख करोड़ रु. के निवेश का खाका तैयार किया है। **एक्सपर्ट्स के अनुसार यह मेगा एक्शन देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नींव रखेगा।**

चुनौती 1: महंगे प्रोडक्ट और प्रतिस्पर्धा

भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में अपने प्रतियोगियों की तुलना में 25% तक अधिक महंगे हैं। देश में परिवहन खर्च कुल उत्पादन लागत का 8-10% है, जबकि ग्लोबल औसत 4-5% है।
समाधानः फ्रेट कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स समय 30% कम, लागत 20% बचेगी। 20 राष्ट्रीय जलमार्ग व कंटेनर-शिप निर्माण से कार्गो लागत 30% कम होगी।

चुनौती 2: अभी उद्योग आधी रफ्तार पर

देश के 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर आज अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 50-60% इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और कर्मचारियों के पास नई तकनीक से जुड़ी ट्रेनिंग भी नहीं है।
समाधानः इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, मशीनें अपग्रेड व स्किल ट्रेनिंग भी। 5 साल में उत्पादन 30% तक बढ़ेगा, प्रति कर्मी आउटपुट 25-35% बेहतर होगा।

चुनौती 3: रिसर्च और तकनीक गैप

हमारी इंडस्ट्री में आधुनिक, एकीकृत बुनियादी ढांचा नहीं है। 70% से अधिक तकनीकें विदेश से आती हैं। अभी रिसर्च और तकनीक का बड़ा गैप है।
समाधानः तकनीकी आधुनिकीकरण को बायोफार्मा-सेमीकंडक्टर्स के लिए रिसर्च सेंटर्स बनेंगे। 'डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स' बनाने हेतु 20,000 करोड़ का बजट आवंटित होगा। हाईटेक टूल देश में ही बनेंगे।

मैन्युफैक्चरिंगः इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल व कंटेनर पर फोकस

- **इलेक्ट्रॉनिक्सः** ईसीएमएस योजना का बजट 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रु. होगा। इससे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रेफ्रिजरेटर जैसे आइटम के छोटे-छोटे पुर्जे बनेंगे। फोन स्क्रीन, कैमरा सर्किट व सेल कवर जैसे 60% आइटम देश में बनाने को पुश।
- **केमिकल पार्कः** क्लस्टर-आधारित प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर 3 केमिकल पार्क बनेंगे। दो जगहों पर हाई-टेक टूल रूम स्थापित होंगे।
- **कंटेनरः** कंटेनर विनिर्माण ईकोसिस्टम बनाने को 5 वर्षों में 10,000 करोड़। अभी हमारा 95% आयात-निर्यात विदेश में बने कंटेनरों में होता है।

असरः इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में आयात निर्भरता 25-30% कम होंगी। स्वदेशी सेक्टर्स बूस्ट होंगे। नई नौकरियों के अवसर व एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। देश ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सेदार बनेगा।

एमएसएमईः तेज रफ्तार देने के लिए मल्टी-लेवल सपोर्ट पैकेज

- **एमएसएमई** हमारे देश के इंडस्ट्री की रीढ़ है। इसे बेहतर बनाने के लिए मल्टी लेवल सपोर्ट पैकेज दिया गया है।
- **इक्विटी हेल्पः** 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड।
- **सेल्फ-रिलायंट फंडः** अति लघु उद्योग को 2 हजार करोड़ अतिरिक्त राशि।
- **लिक्विडिटी सपोर्टः** एमएसएमई को समय पर भुगतान को TReDS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अनिवार्य। एमएसएमई बिल तुरंत डिस्काउंट करा सकेंगे। जेम पोर्टल भी TReDS से जुड़ेंगे। **कॉरपोरेट मित्रः** टियर-II और टियर-III शहरों में कॉर्पोरेट मित्रों का कैडर तैयार होगा।

असरः एमएसएमई में मल्टी लेवल रणनीति से समय पर भुगतान व पेशेवर मदद मिलेंगी, कारोबार आसानी से बढ़ेंगे, लागत घटेगी। छोटे कारोबारी बाजार में उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे।

टेक्सटाइलः खादी-स्पोर्ट्स गुड्स के ग्लोबल बाजार की तैयारी

- **टेक्सटाइल पार्कः** मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे। नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल विस्तार और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी।
- **महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहलः** खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाएगा।
- **स्पोर्ट्स गुड्सः** देश को स्पोर्ट्स गुड्स के ग्लोबल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- **टेक्स-इको पहलः** विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी व सस्टेनेबल वस्त्रों और परिधानों को बढ़ावा मिलेगा। पीएलआई स्कीम के तहत मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

असरः टेक्सटाइल, खादी सेक्टर में निवेश बढ़ेंगे। उत्पादों की ग्लोबल मार्केट में पहुंच बढ़ेगी। सूरत (गुजरात), लुधियाना (पंजाब) व तिरुपुर (तमिलनाडु) को फायदा संभव।

एपल को फायदाः फॉक्सकॉन-टाटा जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को मशीन देने पर कोई टैक्स नहीं

एपल व अन्य विदेशी कंपनियां अब अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स (जैसे फॉक्सकॉन और टाटा) को मशीनें बिना टैक्स दे सकेंगे। इससे विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन व निवेश का भरोसा बढ़ेगा।

महत्वपूर्ण क्यो? तुरंत आईफोन सस्ता नहीं होगा। लेकिन भारत में उत्पादन बढ़ने से भविष्य में असर संभव। ग्लोबल आईफोन शिपमेंट का 25% हिस्सा भारत से जाता है। ये 2022 के बाद चार गुना बढ़ा।

रक्षा... ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा कदम

रक्षा बजट 15% बढ़ा, 8 साल में सबसे ज्यादा

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ये पिछले साल से 15% ज्यादा है। प्रतिशत के लिहाज से यह 8 साल की सबसे बड़ी वृद्धि है। चीन और पाक से बढ़ती चुनौतियों के बीच सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने पर जोर है। नए हथियार और सैन्य विमान खरीदने के लिए पूंजीगत व्यय 22% बढ़ाया है। केंद्रीय बजट का 14.7% हिस्सा रक्षा को मिला है। ये मंत्रालयों में सर्वाधिक है। आधुनिकीकरण पर 1.85 लाख करोड़ रु. खर्च होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में रक्षा बजट व पूंजीगत व्यय बढ़ना रक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को दर्शाता है।

8 साल में ऐसे बढ़ा रक्षा बजट

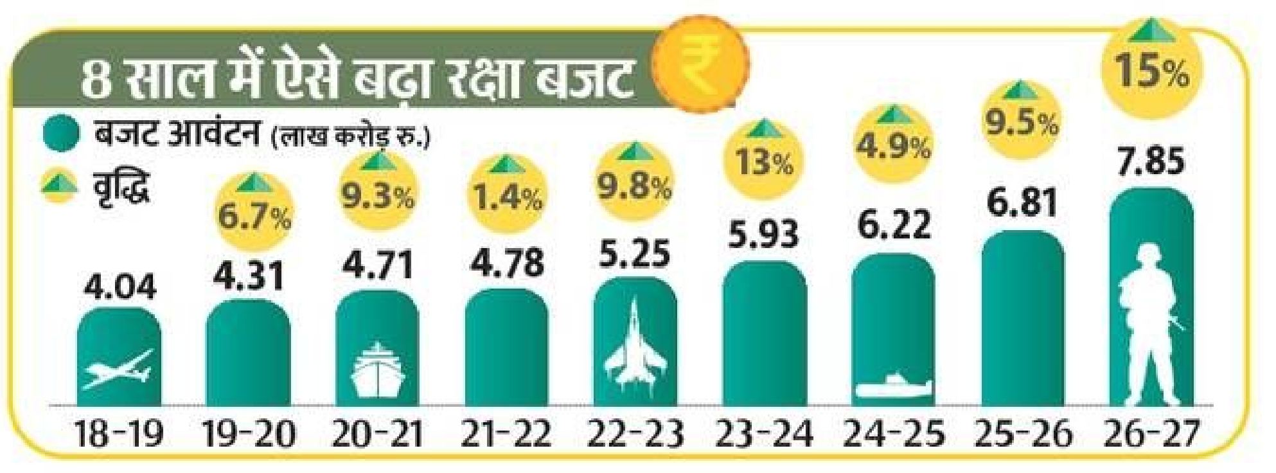

2.19 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए, इनसे नए हथियार व सैन्य साजो-सामान खरीदे जाएंगे

63,733 करोड़ रुपए विमान और एयरो इंजनों पर खर्च होंगे यानी रक्षा बजट का 8 फीसदी

25,023 करोड़ रुपए नौसेना बेड़े के लिए आवंटित किए हैं, जो रक्षा बजट का लगभग 3% है

- डिफेंस आवंटन अगले वित्त वर्ष की अनुमानित जीडीपी का दो प्रतिशत है और यह 2025-26 के बजटीय अनुमान की तुलना में 15.19 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है

चित्र चरित्र

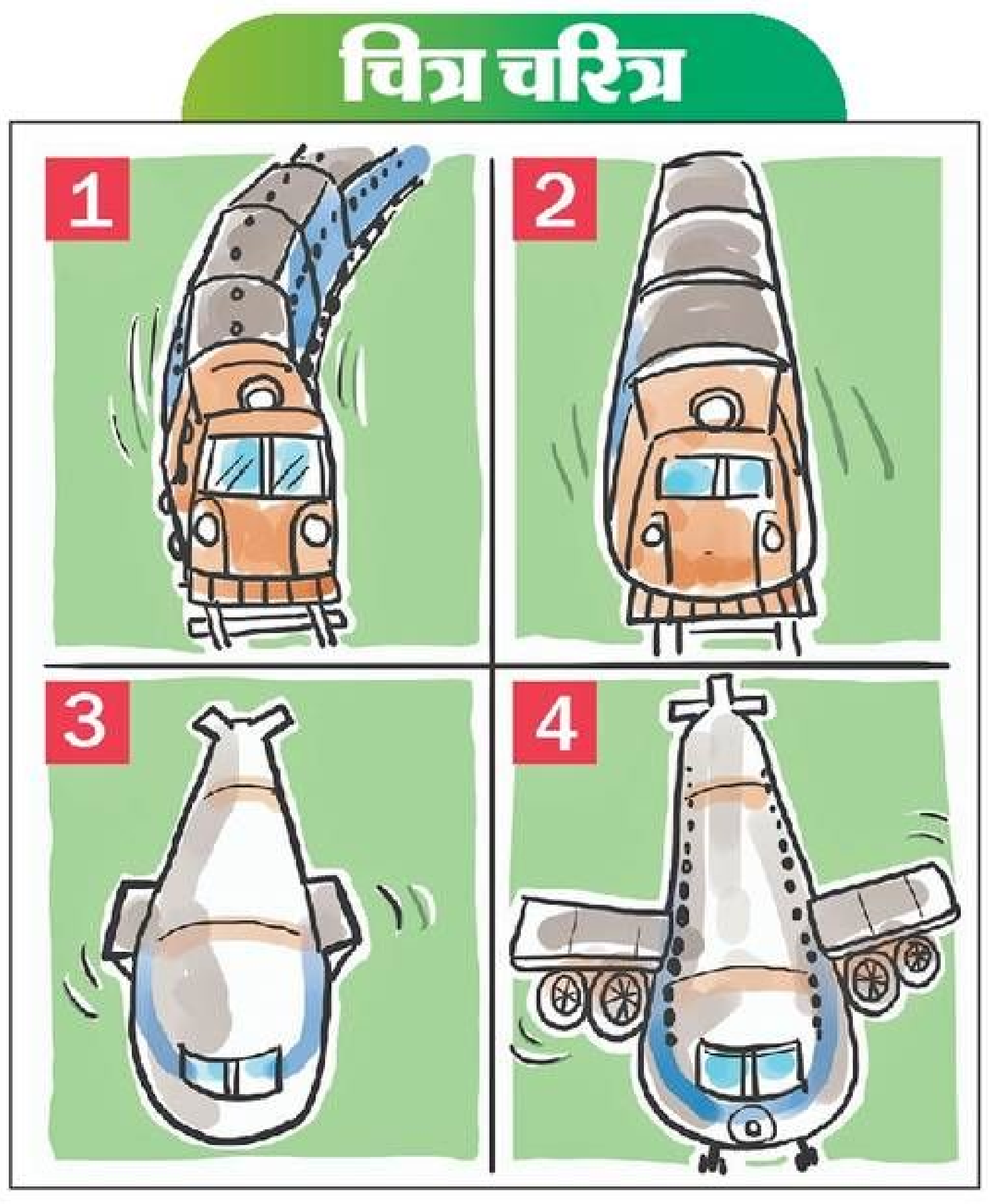

बजट एनालिसिस

नए रोजगार का इको-सिस्टम तैयार हो रहा

अनस रहमान जुनैद
संस्थापक,
हुरुन इंडिया

केंद्रीय बजट 2026-27 ऐसे समय में आया है, जब भारत की संपत्ति सृजन की कहानी नए स्तर पर पहुंच रही है। भारत ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं रहा, जहां सफलता गिने-चुने घरानों तक सीमित हो। भारतीय अरबपतियों की सामूहिक संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर से पार हो चुकी है। सिर्फ एक साल में 75 नए अरबपति बने हैं। इस पृष्ठभूमि में बजट संकेत देता है कि भारत अगले दशक में कैसी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है।

कैपेक्स सही प्राथमिकताः बजट में निवेश आधारित विकास पर जोर है। पूंजीगत व्यय बजट का केंद्र बना हुआ है। कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया है। ये पिछले साल 11.2 लाख करोड़ था। राज्यों का अनुदान जोड़ने पर प्रभावी कैपेक्स करीब 17.15 ट्रिलियन हो जाता है। यह जीडीपी का 4.4% है। शॉर्ट टर्म रियायतों से दीर्घकालिक समृद्धि नहीं आती। समृद्धि का आधार सड़क, बंदरगाह, औद्योगिक कॉरिडोर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो कारोबार बढ़ाते हैं।

सही औद्योगिक दांवः बजट का रणनीतिक फोकस उन क्षेत्रों पर है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा परिभाषित करेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का आईएसएम 2.0 के रूप में विस्तार अहम कदम है। भारत करीब 90% चिप आयात करता है। विनिर्माण और प्रौद्योगिकी शक्ति बनने के लिए यह निर्भरता घटानी होगी। चिप डिजाइन प्रोत्साहन के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का आवंटन 40 हजार करोड़ किया गया है। ये ऐसे इकोसिस्टम के आधार हैं, जो न सिर्फ रोजगार पैदा करेंगे, बल्कि बड़ी कंपनियों को भी जन्म देंगे। इसी तरह, बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम लंबे समय से अपेक्षित कदम है। भारत जेनेरिक दवाओं में वैश्विक नेता रहा है। अगली छलांग बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स और जटिल थैरेपीज में है। यही वे क्षेत्र हैं, जहां से भारत की अगली लहर की मिड कैप और लार्ज कैप संपत्ति का सृजन होगा।

एमएसएमई और स्टार्टअप के फ्रंट पर सकारात्मक संकेतः एमएसएमई रोजगार और विकास के इंजन हैं। 10 हजार करोड़ का प्रस्तावित एसएमई ग्रोथ फंड, टीआरईडीएस के तहत तरलता समर्थन का विस्तार और कूरियर निर्यात सीमा को हटाना व्यावहारिक कदम हैं। स्टार्टअप के लिए धारा 80-IAC के तहत टैक्स हॉलीडे 31 मार्च 2030 तक बढ़ाना राहत देने वाला कदम है। 10 हजार करोड़ के डीप टेक फंड ऑफ फंड्स का क्रियान्वयन इसका संकेत है कि भारत सिर्फ उपभोक्ता प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि गंभीर तकनीकी कंपनियां खड़ी करना चाहता है।

अमेरिकी निर्यातकों को बड़ी राहत दिख रही

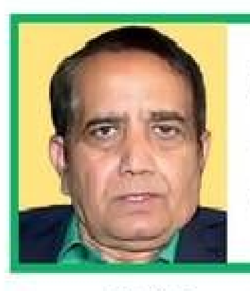

अजय श्रीवास्तव
संस्थापक,
जीटीआरआई

बजट में टैरिफ और सीमा शुल्क संबंधी कुछ बदलाव अमेरिकी निर्यातकों के लिए भारत में नए अवसर खोलते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में ये बजट अमेरिका के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अनुकूल साबित होता दिख रहा है। नागरिक और रक्षा विमानन क्षेत्र में विमान पुर्जों तथा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल से जुड़े इनपुट्स पर सीमा शुल्क खत्म करने का सीधा लाभ अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनियों, इंजन निर्माताओं और मेंटेनेंस सेवा देने वाली फर्मों को होगा।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी लाभः परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बजट घोषणाएं और दूरगामी हैं। 2035 तक सभी पंजीकृत परमाणु संयंत्रों के लिए न्यूक्लियर जेनरेशन इक्विपमेंट, एब्जॉर्बर रॉड्स और प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स पर शून्य सीमा शुल्क अमेरिकी निर्माताओं और तकनीकी प्रदाताओं को दीर्घकालिक नीति स्पष्टता देती है, जो इस क्षेत्र में दुर्लभ है। स्वच्छ ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में भी अमेरिकी निर्यात के लिए बाधाएं कम हुई हैं। लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए कैपिटल गुड्स और सोलर ग्लास में प्रयुक्त सोडियम एंटीमोनाइट के ड्यूटी-फ्री आयात से उन्नत मशीनरी और सामग्री आपूर्ति करने वाली अमेरिकी कंपनियों की लागत घटेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में अतिरिक्त दवा, दुर्लभ रोगों की औषधियों तथा एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट-पैनल डिटेक्टर जैसे अहम मेडिकल डिवाइस कंपोनेंट्स पर शून्य शुल्क से अमेरिकी फार्मा और मेड टेक निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच और आसान होगी। कुल मिलाकर, ये कदम बिना किसी शोर-शराबे के भारत में अमेरिका के पूंजी-प्रधान और टेक्नोलॉजी-आधारित निर्यात को मजबूती देते हैं।

घरेलू इनपुट की ऊंची लागतः कई अहम मुद्दे बजट से बाहर हैं। स्टील, रसायन और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख घरेलू इनपुट की ऊंची लागत कम करने के लिए ठोस टैरिफ या नियामक कदम नहीं उठाए। इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता लगातार दबाव में बनी हुई है। सीमा शुल्क में बदलाव चुनिंदा वस्तुओं तक सीमित रहे। व्यापक टैरिफ रेशनलाइजेशन न होने से दर संरचना लगभग अपरिवर्तित रही। लंबे समय से जारी जटिलताएं बरकरार हैं। वैश्विक व्यापार के बढ़ते विखंडन और खासतौर पर अमेरिकी बाजार में ऊंची टैरिफ बाधाओं के बावजूद, प्रभावित निर्यातकों के लिए आकस्मिक योजना या सहायता रणनीति पेश नहीं की। पिछले बजट में घोषित निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत अब तक कोई भी फंड वितरण नहीं हुआ है।

भास्कर इन्फो • यूपीआई पेमेंट

यूपीआई के एक्सप्रेसवे पर भारत, 5 साल में डेबिट कार्ड पेमेंट 72% घटे

भारत की डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ने से देश पिछले 5 साल से यूपीआई के एक्सप्रेसवे पर फर्राटे से दौड़ रहा है। क्रेडिट कार्ट पेमेंट 200% और ई-वॉलेट भुगतान 130% बढ़े हैं।

यूपीआई पेमेंट 5 साल में करीब 9 गुना बढ़ गया, डिजिटल पेमेंट राशि भी 6 गुना बढ़ी है

	पेमेंट संख्या			पेमेंट राशि		
पेमेंट माध्यम	2025	2020	अंतर	2025	2020	अंतर
यूपीआई	2163.46	223.41	+869%	27.96	4.16	+572%
एनईएफटी	87.77	30.76	+185%	43.76	25.58	+71%
आईएमपीएस	37.99	35.60	+6.7%	6.62	2.92	+127%
क्रेडिट कार्ड	53.98	17.37	+211%	2.04	0.63	+224%
डेबिट कार्ड	10.49	37.65	–72%	0.37	0.65	-43%
ई-वॉलेट	80.94	35.21	+130%	0.20	0.13	+54%
चेक	4.76	7.91	–40%	6.20	6.18	+0.3%
कुल पेमेंट	2515.31	434.16	+479%	311.87	148.99	+109%

- पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा पेमेंट 72% डेबिट कार्ड में कम हुए।

नोट - पेमेंट संख्या करोड़ में, डिजिटल पेमेंट राशि लाख करोड़ रुपए में।

पिछले तीन साल में डिजिटल पेमेंट की संख्या 5 गुना बढ़ी

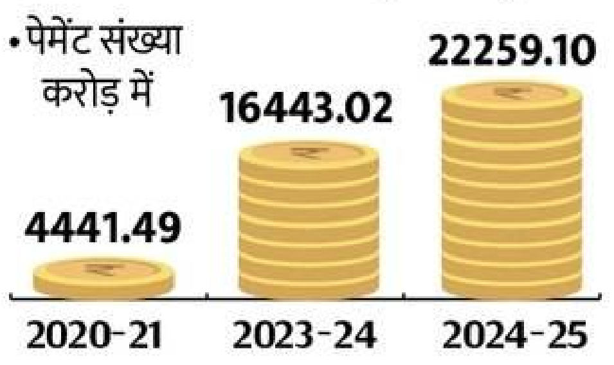

... लेकिन, डिजिटल ट्रांजैक्शन की राशि सिर्फ 2 गुना बढ़ी

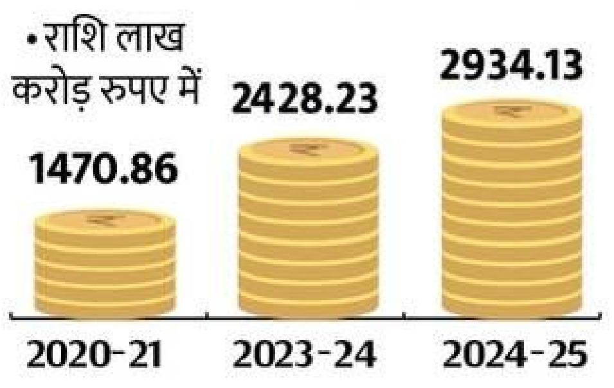

देश में एटीएम से पैसा निकालने वाले एक साल में 9.2 फीसदी घट गए हैं

- देश में दिसंबर-24 तक कुल 2.53 लाख एटीएम थे, दिसंबर-25 तक 2.51 लाख रह गए। बैंक शाखाएं 2.8% बढ़कर 1.64 लाख हो गईं।
- देश में जनवरी-2026 तक कुल 250 करोड़ बैंक खाते हैं। इनमें 56 करोड़ जनधन खाते हैं। जबकि 2014 में कुल बैंक खाते 97.77 करोड़ थे। 2019 में 164.32 करोड़ खाते थे। उसके बाद से यह संख्या बढ़ रही है।
- देश में बैंकों में कुल जमा राशि 253.77 लाख करोड़ रु. है। इसमें 220.49 लाख करोड़ रु. की राशि लंबी अवधि की बचत योजनाओं में जमा है। शेष 33.28 लाख करोड़ रु. की राशि डिमांड डिपॉजिट है।
- देश में जमा दर सालाना आधार पर 12% की दर से बढ़ रही है।
- आरबीआई के अनुसार 97.6% बैंक खातों में जमा 5 लाख रु. तक की राशि का बीमा है। कुल राशि की बात करें तो 41.5% राशि ही का ही बीमा है। यह एक वर्ष पहले 43.1% है।

एटीएम से विड्रॉल घट रहे

वर्ष	संख्या	राशि
2024-25	603.08	30.63
2023-24	664.40	32.59
2020-21	609.05	28.89

संख्या करोड़ में, राशि लाख करोड़ रु. में

सड़क, रेल, जल और हवाई मार्ग सब फोकस में

म्युनिसिपल बॉन्ड • 1000 करोड़ रु. तक बॉन्ड लाने पर मिलेगा 100 करोड़ रु. तक का अनुदान

अब आत्मनिर्भर निकायों की तैयारी

भास्कर न्यूज | मुंबई

फंड की कमी से जूझ रहे नगरीय निकायों को आम बजट में आत्मनिर्भर बनाने की ठोस तैयारी नजर आई है। वित्तमंत्री सीतारमण ने म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिये नगर निगमों को बाजार से सीधे पूंजी जुटाने का अवसर दिया है। अब नगरीय निकाय 1000 करोड़ रु. तक के बॉन्ड जारी कर सकेंगे, जिस पर सरकार की ओर से 100 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। म्युनिसिपल फाइनेंस पर काम करने वाले जनागृह के डायरेक्टर (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट) प्रभात कुमार ने बताया कि पहले नगर निगम अधिकतम 200 करोड़ रु. तक के बॉन्ड ही ला पाते थे, वहीं अब इस व्यवस्था से उनकी बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है। इससे पहले इंदौर ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिये 244 करोड़ रु. जुटाकर शहर में सौर ऊर्जा के जरिये वाटर सप्लाई करने के लिए 60 मेगावाट का एक सोलर एनर्जी प्लांट लगाया था। भोपाल में नगर निगम ने 200 करोड़ रु. जुटाए थे। बेंगलुरु ने बॉन्ड के जरिये 125 करोड़ रु. जुटाए थे। लेकिन वे वित्तीय सुधार नहीं कर सके।

इन्फ्रा रिस्क फंडः प्रोजेक्ट अटकने से कर्जदाता को हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार

इन्फ्रा प्रोजेक्ट में 'पॉलिसी पैरालाइज' का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने 'इन्फ्रा रिस्क गारंटी फंड' बनाया है। सड़क, रेल और मेट्रो, पोर्ट और सिटी इन्फ्रा में काम कर रहीं कंपनियों के प्रोजेक्ट में अगर विलंब होगा तो कर्जदाता बैंक व एनबीएफसी को होने वाले नुकसान के एक हिस्से की भरपाई इस रिस्क फंड से होगी। नारेडको के चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी के अनुसार अब सरकार जोखिम की गारंटी लेगी तो वित्तीय संस्थाएं बड़े पैमाने पर कर्ज देंगी।

- लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को प्रमुख कर्तव्यों में शामिल किया
- इन्फ्रास्ट्रक्चर में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 12.2 लाख करोड़ किया
- केंद्र और राज्यों का पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 22% ज्यादा रहा

बंगाल से गुजरात तक फ्रेट कॉरिडोर

2000 किमी लंबा ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएगा रेलवे

डानकुनी (बंगाल) से सूरत जुड़ेगा। झारखंड, बिहार, यूपी और मप्र से गुजरेगा।

40 घंटे का समय बचेगा, अभी मालगाड़ी को औसत 5 दिन लगते हैं।

100 किमी/घंटे की गति से चलेंगी मालगाड़ियां, अभी गति 30 किमी/घंटे है।

सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे

मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट। यात्रा समय 50% घटेगा।

देश में 20 नए इनलैंड वाटरवे बनेंगे

भारत में 20 नए इनलैंड वाटरवे बनेंगे। जिनकी शुरुआत ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच बहने वाले नेशनल वाटरवे-5 से होगी। करीब 12,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश आएगा।

कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम

बजट में कोस्टल और इनलैंड वाटरवे कार्गो (तेरह सागर और नदी के मार्ग) की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना पेश की गई है। इससे माल ढुलाई अधिक सस्ती और आसान तरीके से हो सके।

एविएशनः सीप्लेन योजना से बढ़ावा

इस आम बजट में सीप्लेन संचालन के लिए वीजीएफ, विमान व रक्षा एमआरओ पुर्जों के आयात पर कस्टम ड्यूटी छूट, जिससे लागत घटेगी और घरेलू क्षमता बढ़ेगी।

रेयर अर्थ कॉरिडोरः चीन पर निर्भरता घटेगी

रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) की सप्लाई आज एक बड़ा मुद्दा है। भारत इन रेयर अर्थ एलिमेंट में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह कॉरिडोर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में विकसित होंगे। इनका उद्देश्य दुर्लभ खनिजों की खोज, माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। भारत अभी 90% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन से आयात करता है। इसका लाभ सेमीकंडक्टर, ईवी, डिफेंस इक्विपमेंट, ग्रीन एनर्जी इत्यादि सेक्टर में होगा।

- **कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंटः** आम बजट में कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट (सीआईई) के विनिर्माण में मजबूती लाना है। इसका उद्देश्य तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना है। इसमें हाई राइज बिल्डिंगों में इस्तेमाल होने वाले लिफ्ट, फायर-फाइटिंग उपकरण और टनल बोरिंग मशीनों पर खास फोकस होगा।

बैलेंस शीट

रुपया कहां से आएगा

रेवेन्यू से जमा	रकम*
इनकम टैक्स	14,66,000
कॉरपोरेशन टैक्स	12,31,000
जीएसटी	10,19,020
कस्टम	2,71,200
एक्साइज	3,88,910
संघ राज्य क्षेत्रों पर टैक्स	10,256
अन्य कर	17,700
सकल टैक्स आय	**44,04,086**
घटाया- राज्यों का हिस्सा	**-15,37,165**
कुल टैक्स आय	28,66,922
नॉन टैक्स रेवेन्यू	6,66,228
नॉन डेट रिसीप्ट	1,18,397
सरकार के पास कुल जमा	**53,47,315**
डेट रिसीप्ट	**16,63,066**
नकद शेष का कम आहरण	**32,702**

कुल जमा : 53.47 लाख करोड़ रु. (100%)

रुपया कहां जाएगा

सरकार का खर्च	रकम*
ब्याज	14,03,972
ट्रांसपोर्ट	5,98,520
डिफेंस	5,94,585
सब्सिडी (उर्वरक, खाद्य, पेट्रोलियम)	4,10,495
पेंशन	2,96,214
ग्रामीण विकास	2,73,108
गृह (केंद्र शासित प्रदेश सहित)	2,55,234
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,62,671
शिक्षा	1,39,289
ऊर्जा	1,09,029
स्वास्थ्य	1,04,599
शहरी विकास	85,522
सामाजिक कल्याण	62,362
वाणिज्य एवं उद्योग	70,296
आईटी और दूरसंचार	74,560
विज्ञान विभाग	55,756
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन	45,500
विदेशी मामले	22,119
वित्त	20,649
पूर्वोत्तर विकास	6,812
अन्य	5,56,021

कुल खर्च : 53.47 लाख करोड़ रु. (100%)

(*रकम करोड़ रुपए में, स्रोत- वित्त मंत्रालय)

कृषि/मनरेगा/ ग्रामीण विकास

कृषि को 7%, रोजगार पर 45% ज्यादा धन

कृषिः नारियल, काजू के लिए अलग बजट, 20 हजार पशु चिकित्सकों के लिए सब्सिडी

केंद्रीय बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.63 लाख करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 7% ज्यादा है। भारत-विस्तार एआई कृषि प्लेटफार्म शुरू करने की घोषणा की है, जिस पर किसानों को मौसम की जानकारी, फसल सलाह और कृषि से जुड़ा डेटा मिलेगा। नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए अलग से बजट रखा गया है।

पशु चिकित्सकों को सुविधाः बजट में 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों और पशु चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लोन-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी प्रस्तावित की गई है। इससे प्राइवेट सेक्टर में पशु चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक लैब, कॉलेज और ब्रीडिंग सुविधाएं स्थापित हो सकेंगी।

गारंटीः वीबी जीरामजी को 96 और मनरेगा को मिले 30 हजार करोड़, दोनों योजना जारी

मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जीरामजी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 2026-27 में यह आवंटन दो हिस्सों में बांट दिया गया है। नई वीबी जीरामजी के लिए 96 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही पुरानी मनरेगा के लिए भी 30 हजार करोड़ दिए गए हैं। इसे मिलाकर कुल प्रावधान 1.25 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। उल्लेखनीय है कि नई योजना में रोजगार गारंटी के दिन 125 कर दिए गए हैं। पहले यह 100 ही थे। पुरानी योजना में 100 फीसदी पैसा केंद्र से आता था। नई योजना में 60 से लेकर 90% तक पैसा केंद्र देगा। यानी राज्य सरकारों को अब 10 से 30% तक योजना का खर्च के बोझ को उठाना पड़ेगा।

चित्र चरित्र

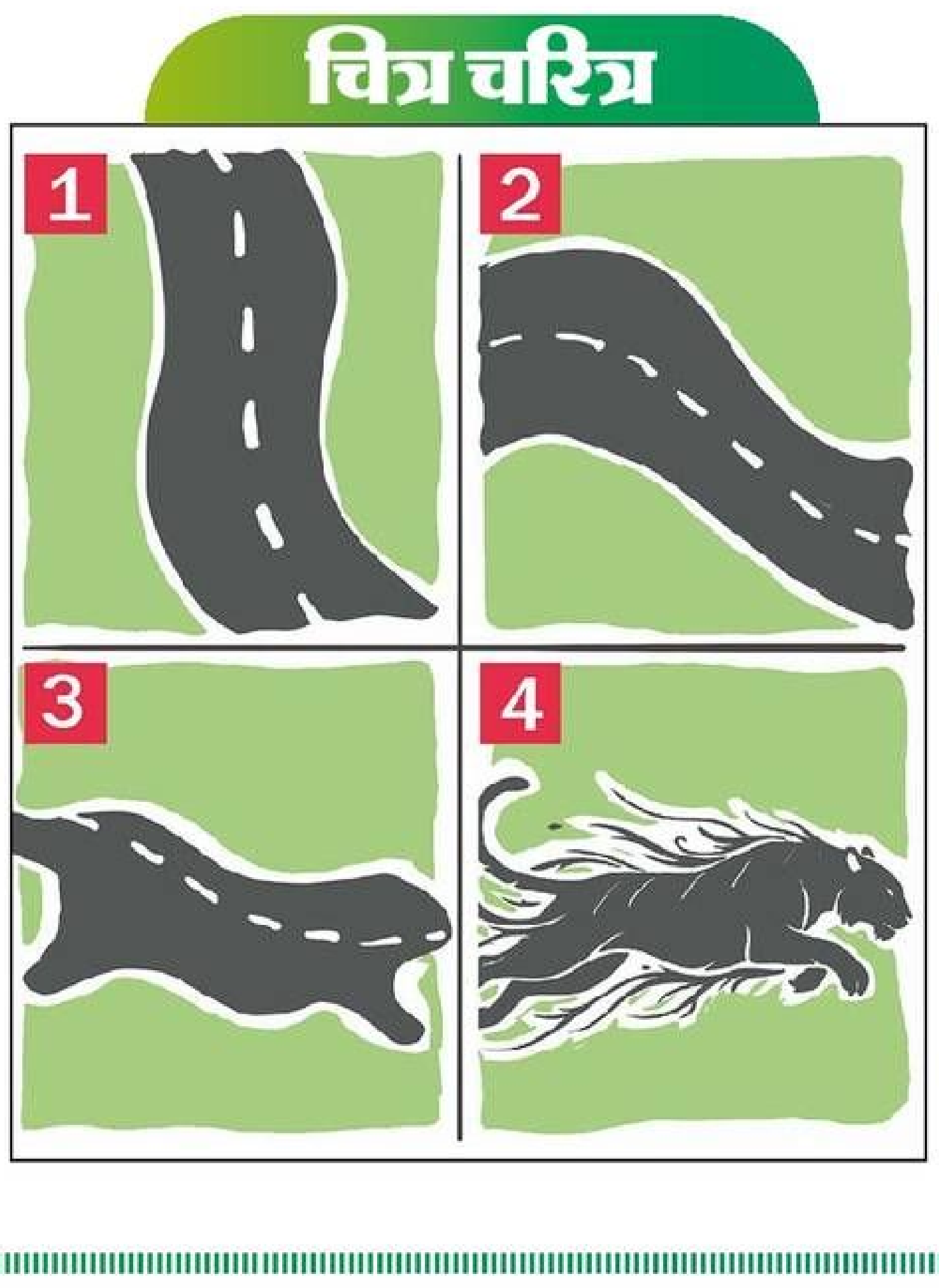

कॉरपोरेट प्रतिक्रिया

स्थिरता व आत्मनिर्भरता वाला बजट; रक्षा, इन्फ्रा, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर

स्पेशल इकोनॉमिक जोन से घरेलू व्यापार में तेजी आएगी

बजट से युवा और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर नियमों में ढील देना बड़ा कदम है जिससे घरेलू व्यापार बढ़ेगा। खनिज क्षेत्र के लिए नए कॉरिडोर और टैक्स छूट से आम लोगों को फायदा होगा।
-अनिल अग्रवाल, चेयरमैन, वेदांता

भविष्य की नींव रखेगा देश को 'धुरंधर' बनाएगा

बजट भविष्य की नींव रखने वाला है। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी और डेटा सेंटर व परमाणु ऊर्जा पर जोर भारत को 'धुरंधर' बनाएगा। इससे युवाओं के कौशल विकास, समावेशी विकास और टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिश है।
-हर्ष गोयनका, चेयरमैन, आरपीजी

वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने में मदद मिलेगी

बजट में बायोफार्मा को सात रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल करते हुए 'बायोफार्मा शक्ति' योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 साल में 10 हजार करोड़ खर्च होंगे। इससे दवा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश वैश्विक बायोफार्मा हब बनेगा।
-किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन

10 हजार करोड़ रु. का फंड एसएमई के लिए फायदेमंद

10 हजार करोड़ रु. का 'एसएमई ग्रोथ फंड' और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ की सुविधा छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा सहारा है। सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने से उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
-सी.एस. शेट्टी, चेयरमैन, एसबीआई

चार नए रेयर अर्थ कॉरिडोर से ईवी कार सस्ती होंगी

लिथियम-आयन सेल बनाने वाली मशीनों पर कस्टम ड्यूटी छूट और चार नए रेयर अर्थ कॉरिडोर से ईवी गाड़ियां सस्ती होंगी। छोटे डीलरों के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड व सीएनजी पर ड्यूटी राहत भरे कदम हैं। दुर्घटना मुआवजे पर टैक्स छूट से राहत मिली है।
-सी.एस. विग्नेश्वर, अध्यक्ष, फाडा

किफायती आवास के लिए घोषणा न होने से निराशा

रियल एस्टेट के लिए निराशा रही। किफायती आवास के लिए बड़ी घोषणा नहीं हुई, इन घरों की बिक्री 2019 के 38% से गिरकर 2025 में मात्र 18% रह गई है। इस क्षेत्र के खरीदारों और डेवलपर्स के लिए ब्याज राहत जैसे सीधे हस्तक्षेप की सख्त जरूरत थी।
-अनुज पुरी, चेयरमैन, एनरॉक

डेटा सेंटर्स पर टैक्स छूट से भारत वैश्विक हब बनेगा

12.2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कैपेक्स निजी निवेश और विकास को रफ्तार देगा। डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स हॉलिडे से भारत वैश्विक हब बनेगा। शेयर ऑप्शन पर एसटीटी से बाजार में उतार-चढ़ाव संभव है।
-नीलेश शाह, एमडी, कोटक महिंद्रा एएमसी

मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ब्याज पर टैक्स से छूट सही

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के ब्याज पर टीडीएस और टैक्स से छूट देना बेहतर कदम है। जिससे पीड़ितों को मुआवजा मिलना आसान होगा। शेयर बायबैक को कैपिटल गेन की तरह टैक्स करना छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद है। **-अश्वनी धनवत,** सीआईओ, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

तेज सुधार का समय

आम बजट 2026 को एक सुधारवादी बजट के रूप में देखना ज्यादा मुफीद रहेगा। इस बजट पर किसी तरह का सियासी या चुनावी दबाव नहीं था और इसलिए भी इसमें आर्थिक सुधार की कोशिशें ज्यादा नजर आ रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें कोई लोक-लुभावन या चमकदार घोषणाएं नहीं हैं। किसी सुधारवादी बजट की यह खासियत होती है कि उसे देखकर लगता है, कोई नया या बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। वास्तव में, आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कदम बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कदम जमाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत ही जिन तीन कर्तव्यों की चर्चा से की है, उस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। पहला कर्तव्य, अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा, अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता विकसित करना। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि देश के प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग तक संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों की पहुंच हो। ये घोषित कर्तव्य बहुत स्पष्ट हैं। इनसे सरकार की प्राथमिकताओं का पता चलता है। यह पिछले बजट जैसा निर्णायक भले न हो, पर सकारात्मक रूप से हस्तक्षेपकारी है।

शहरी विकास से लेकर पर्यटन विकास तक और शिक्षा से स्वास्थ्य तक किए गए प्रयास सराहनीय हैं। बजट 2026 के प्रस्ताव आम आदमी को प्रभावित करेंगे।

यह बजट साफ संकेत है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुरे दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ताजा बजट में सबसे प्रशंसनीय पहल यह है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 ट्रिलियन कर दिया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि सरकार मूलभूत ढांचे में निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने की अपील करती रहती है। अपनी ओर से भी सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाकर निजी क्षेत्र को प्रेरित किया है। एक सड़क भी बनती है, तो उससे अनेक उद्योगों को बल मिलता है, रोजगार बढ़ता है। भारत का बुनियादी विकास अगर तेजी से होता रहेगा, तो व्यापकता में उसके विकास का रथ कहीं नहीं थमेगा। शहर विकास से लेकर पर्यटन विकास तक और शिक्षा से स्वास्थ्य तक किए गए प्रयास सराहनीय हैं। बजट 2026 के प्रस्ताव आम आदमी को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। आयकर स्लैब में पिछली बार ही भारी बदलाव हुआ था, तो इस बार उसमें बदलाव की बहुत उम्मीद नहीं थी। कर सुधार और कर रियायत, दो ऐसे मोर्चे हैं, जिन पर बजट में प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं। इन सुधारों का लाभ निवेश को मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अपने देश में व्यापार करने की सुविधा बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। दुनिया यह मान रही है कि भारत संभावनाओं का क्षेत्र है, लेकिन इन संभावनाओं को साकार करने की जिम्मेदारी बजट को सही ढंग से लागू करने में दिखनी चाहिए।

बजट बहुत सावधानी से बनाया गया है और यह संदेश दे रहा है कि आम लोग भी बहुत सावधानी से अपने आर्थिक फैसले लें। मिसाल के लिए, चांदी की कीमतों को देखा जा सकता है। साढ़े चार लाख रुपये किलोग्राम की कीमत तक पहुंच गई चांदी तीन लाख रुपये से भी नीचे उतर आई है। अर्थात, यह किसी आर्थिक फैसले पर टिकने का दौर नहीं है। यह जरूरत और सहूलियत के हिसाब से लचीले फैसलों का समय है। फिर भी, जो लोग बजट से कुछ ज्यादा पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की लोकलुभावन घोषणाएं महज बजट की मोहताज नहीं हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

02 फरवरी, 1951

चीन की निन्दा

संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति के सामने कोरिया और दूर पूर्व के संबंध में मुख्य रूप से दो प्रस्ताव उपस्थित थे। एक प्रस्ताव एशियाई और मध्य-पूर्व के देशों की ओर से रखा गया था और दूसरा अमेरिका ने रखा।

पहले प्रस्ताव में अविलम्ब सात राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव था। उसमें यह भी कहा गया था कि सात राष्ट्रों का सम्मेलन सबसे पहले कोरिया में युद्ध विराम के बारे में समझौता करे और उसके बाद कोरिया के भविष्य एवं दूर पूर्व की अन्य समस्याओं पर चर्चा करे। अमेरिकी प्रस्ताव में कोरिया में हस्तक्षेप करने के लिए चीन को आक्रमणकारी ठहराया गया है। उसमें यह सुझाव भी दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक कार्रवाई कमेटी को तुरन्त जांच-पड़ताल करके रिपोर्ट देनी चाहिए कि कोरिया में आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए किन उपायों का अवलंबन किया जा सकता है। राजनीतिक समिति ने अमेरिकी प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया। अमेरिकी प्रस्ताव के स्वीकृत होने के पहले लेबनान ने उसमें दो संशोधन रखे थे। अमेरिकी प्रस्ताव में कहा गया था कि चीन ने कोरिया में युद्ध विराम संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। लेबनान का पहला संशोधन इस शब्दावली को बदल देता है और अब अमेरिकी प्रस्ताव कहता है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के युद्ध विराम संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है।... अमेरिकी प्रस्ताव में कोरिया की समस्या को शान्तिपूर्वक हल करने का प्रयत्न करने के लिए तीन आदमियों की एक कमेटी नियुक्त करने की बात कही गई है।...

एशियाई और मध्य-पूर्व के देशों को अमेरिकी प्रस्ताव के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह थी कि यह चीन को आक्रमणकारी घोषित करके उसकी निन्दा करता है। अमेरिकी प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने के पहले भारतीय प्रतिनिधि श्री नृसिंहराव ने राजनीतिक समिति को यह सूचित कर दिया था कि यदि अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो चीन शान्ति-चर्चा में भाग लेने से इनकार कर देगा। इसका अर्थ यह होगा कि कोरिया और दूर पूर्व की समस्याओं को शान्तिपूर्वक समाधान करने के लिए अब तक जो प्रयत्न किये गये, वे विफल हो जायेंगे।

देश को सही दिशा में बढ़ाएगा बजट

यहां स्कैन करें

एन के सिंह | 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष

दुनिया में आज जो हालात हैं, उसकी रोशनी में ही भारत के आम बजट को देखना चाहिए। बेशक, इस बजट में कुछ पहलू खास हैं, जिनसे देश की उम्मीदों को बल मिलता है।

भारत के आम बजट 2026 को किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, इसे विश्वसनीय, जिम्मेदार और दूरदर्शी बजट कहा जा सकता है। अव्वल तो बजट-चर्चा शुरू करने से पहले हमें दुनिया के हालात पर जरूर नजरें फेर लेनी चाहिए। उसके बाद ही यह सोचना चाहिए कि ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जिनसे हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो। वृद्धि भी कम नहीं, कम से कम उतनी हो, जितनी नए आर्थिक सर्वेक्षण में बताई गई है।

रविवार को पेश केंद्रीय बजट में खास यह है कि व्यापार या उद्योग को विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में देखा गया है। वित्त मंत्री ने दूरदर्शिता दिखाते हुए सहयोगी देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सीमा शुल्क सुधार की बड़ी कोशिश की है। इससे निवेश दक्षता और व्यापार संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लगातार उच्च विकास दर के अनुकूल स्थितियां बनेंगी। संक्षेप में कहें, तो इस वर्ष वित्त मंत्री का मूल मंत्र पूंजी, प्रौद्योगिकी और निर्यात प्रतिस्पर्धा है।

सुखद है कि पहली बार विकास दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। इस विकास दर को पाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। बजट के अनेक पहलू हैं, जिनसे उम्मीदों को बहुत बल मिलता है। अमेरिका के साथ जारी टैरिफ संबंधी तनाव के बावजूद भारत ने पिछले महीनों में कई मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। यूरोपीय संघ से भी भारत का व्यापार समझौता हुआ है। भारत और यूरोप की आबादी को जोड़ लें, तो एक बहुत बड़ा बाजार हो जाता है। अतः यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार समझौता एक बड़ा कदम है।

हालांकि, भारत को आत्मनिर्भरता को संरक्षित रखते हुए, विशेषकर बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था में भी, विश्वसनीय साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यह मानना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और नए बदलाव अव्यवस्थित हैं। इसे 'कार्नीवाद' कहा जा सकता है : एक स्पष्ट चेतावनी है कि हम बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में बहुपक्षीय व लचीले गठबंधन बनाने में सक्षम देश ही बदलाव को राह दिखाएंगे। भारत के आर्थिक फैसले भी तय करेंगे कि दुनिया में नए गठबंधन कैसे आकार लेंगे? गठबंधन बनाने की चुनौतियों में वित्त, निवेश, ऊर्जा, जलवायु, जैव विविधता और सुरक्षा शामिल है। इस बजट में इन चुनौतियों से दो-दो हाथ करने का इरादा दिखता है।

आज हम गौर कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की यह एक बड़ी कामयाबी है, सरकार ने अपनी वित्तीय जिम्मेदारी को ठीक से निभाया है। वित्तीय संतुलन का यह मार्ग मैंने अपनी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के माध्यम से भी तैयार किया था, जिसे इस सरकार ने मंजूरी दी। सही राह पर हम बने हुए हैं। इसी के तहत हमने इस वर्ष भी वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य था, उसे पाया है और तभी आगामी वर्ष में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.3 प्रतिशत रखा गया है।

बजट से पता चलता है कि देश के ऋण में गिरावट आई है। अगले वर्ष और गिरावट आएगी। हमारा लक्ष्य है कि 2030-31 में ऋण को जीडीपी के अनुपात में 51 प्रतिशत तक लाया जाए। हालांकि, हमें राज्यों के ऋण के बारे में भी सोचना चाहिए। राज्यों के ऋण और घाटे पर थोड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के ऋण अनुपात के अनुरूप ही राज्यों के ऋण को लाना होगा।

ताजा बजट की एक खासियत यह भी है कि अर्थव्यवस्था के कुछ नए उभरते क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। रेअर अर्थ (विशेष रासायनिक तत्व), कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (कार्बन पृथक्करण), आई क्लाउड (सुरक्षित स्टोरेज सेवा), इन सभी नए क्षेत्रों को बजट ने बल देने के जरूरी प्रयास किए हैं।

बजट में रोजगार बढ़ाने के दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्रों को देखा गया है। श्रमिकों की ज्यादा जरूरत वाले वस्त्र और चमड़ा उद्योग पर जोर दिया गया है। पर्यटन विकास के लिए निश्चित कदम उठाए गए हैं। टूरिस्ट सर्किट की घोषणा हुई है। बजट यह भी कोशिश करता दिख रहा है कि स्वास्थ्य पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए। शिक्षा क्षेत्र में देखें, तो यह बड़ी घोषणा है कि पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बसाए जाएंगे।

बहरहाल, जब बजट में दिख रही तमाम कोशिशों को हम जोड़ते हैं, तब हमें रोजगार प्रधान विकास की नींव मजबूत होती दिखती है। आज देश में ऐसा आर्थिक विकास चाहिए, जो रोजगार के अवसर बढ़ाए।

टैक्स की चर्चा करें, तो जो टैक्स रेट बहुत कम हो गए थे, उसके विपरीत हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हां, टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, इससे कराधान में सुविधा बढ़ेगी। कर चुकाना आसान होगा।

आयात शुल्क संबंधी जो कदम हमने उठाए हैं, वह भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कैंसर की विशेष दवाइयों और परमाणु शक्ति पर जो रियायत हमने दी है, वह बिल्कुल सही है। साथ ही, जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जिससे एआई का उपयोग बढ़ रहा है, इस क्षेत्र को साल 2027 तक रियायत दी गई है। जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, उस पर भी बजट में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

बजट के साथ ही 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखा गया है। एक्शन टेकेन रिपोर्ट का कार्यक्रम भी पेश किया गया है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष रहते मैंने भी राज्यों के राजस्व में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी, 16वें वित्त आयोग ने भी इतना ही लक्ष्य रखा है, जिसे सरकार ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा करते हैं, अब इस आम बजट से रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति में नई प्रगति जुड़ जाएगी।

गौरतलब है, जब केंद्रीय बजट पेश हो रहा था, तब शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। वैसे, किसी भी बजट को केवल शेयर सूचकांक के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कई बार शेयर बाजार में तुरंत प्रतिक्रिया दिखती है, पर हमें देखना चाहिए कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रस्तावित बजट में तीन लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सड़क, पुल, पाइपलाइन, बंदरगाह इत्यादि के निर्माण में तेजी आएगी, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

बहरहाल, एक कठिन वैश्विक परिवेश में, यह आम बजट भारत को न केवल आर्थिक विकास करने के लिए, बल्कि विवेक और लचीलेपन के साथ विकास को नियंत्रित करने के लिए तैयार करता दिख रहा है। यह बजट एक बहुत सकारात्मक पहल है, यह देश की आर्थिक तरक्की और दुनिया के बदलते माहौल के साथ कदमताल करता लग रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रक्षा मद में अधिक खर्च करना समय की मांग

यहां स्कैन करें

सुशांत सरीन | रक्षा विशेषज्ञ

इस समय दुनिया के जो हालात हैं, उसमें किस वक्त बड़ा सैन्य संघर्ष छिड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन-रूस और हमास-इजरायल के संघर्ष के तनाव से दुनिया अभी जूझ ही रही है कि ईरान का संकट दिन-ब-दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। अगर तेहरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले हुए, तो उसके असर से हम अछूते नहीं रहेंगे। गौर करने वाली बात है कि चीन और पाकिस्तान की चुनौती के साथ अब बांग्लादेश भी हमारे लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में, रक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन पर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की ही नहीं, आम नागरिकों की भी गहरी नजर टिकी थी।

पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी इस रक्षा बजट का अच्छा संकेत है। यह धन सेना के आधुनिकीकरण और साजो-सामान की खरीद पर खर्च होगा।

इस लिहाज से देखें, तो इस साल के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जो पिछले साल आवंटित 6.81 लाख करोड़ रुपये से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बैठता है। यकीनन, इसके लिए वित्त मंत्री की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि, मैं यहां संशोधित रक्षा बजट के हिसाब से अपनी बात रखना चाहूंगा। चालू वित्त वर्ष के संशोधित रक्षा बजट के हिसाब से देखें, तो मोटे तौर पर इस बार 50 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दिखती है। अच्छी बात यह है कि इस 50 हजार करोड़ में से लगभग 30 हजार करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय में जा रहा है। यानी यह रकम सेना के आधुनिकीकरण और साजो-सामान पर खर्च होगी। इसमें से करीब 16,000 करोड़ रुपये राजस्व मद में जा रहा है, यानी यह राशि तनख्वाह आदि में खर्च होगी, लगभग 2,000 करोड़ रुपये पेंशन मद में और 1,000 करोड़ रुपये मंत्रालय के बजट पर खर्च किए जाएंगे। इस लिहाज से देखें, तो यह बढ़ोतरी सही जगह पर ठीक अनुपात में दिखती है।

आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो भारत रक्षा मद में सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में एक है। हमसे ज्यादा खर्च करने वाले छह देश हैं- अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और सऊदी अरब। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चीन का रक्षा खर्च हमसे करीब चार गुना अधिक है, जबकि पाकिस्तान हमारा नौवां हिस्सा ही खर्च करता है, मगर क्षमता के नजरिये से देखें, तो पाकिस्तान पर हमारी बढ़त जरूर है, पर वह हमसे आनुपातिक रूप से बहुत पीछे नहीं है। इसी तरह, चीन की क्षमता चार गुना ही अधिक होनी चाहिए थी, पर वहां काफी अंतर है। हमारे नीति-नियंताओं को इस पर सोचने की जरूरत है।

निस्संदेह, हमारी फौज बहुत बड़ी है, मगर इस स्थिति में बदलाव की जरूरत है। सेना नौकरी देने का महकमा नहीं, यह देश की सुरक्षा तय करने वाला क्षेत्र है। इसलिए हमें न सिर्फ सैनिकों की संख्या सीमित करने की दरकार है, बल्कि पेंशन आदि पर होने वाले खर्च में कमी लाने की भी जरूरत है। गौर कीजिए, नए रक्षा बजट में सिर्फ पेंशन मद में 1,71,338 हजार करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इसमें कोई दोराय नहीं कि हमें पैदल फौजों की जरूरत है, मगर 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमने साफ-साफ महसूस किया कि अब जो सैन्य संघर्ष हो रहे हैं या भविष्य के युद्ध होंगे, वे टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। हमें तय करना है कि हम तालिबान की तरह लाखों की कुर्बानी देकर जीत हासिल करना चाहते हैं या अमेरिका की तरह न्यूनतम शहादत पर सफलता अर्जित करना चाहेंगे?

जाहिर है, हम तालिबानी तरीका नहीं अपना सकते। हमें अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमने इस दिशा में काफी अहम कदम उठाए भी हैं। हम हथियार निर्माण के स्वदेशीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया में गुणवत्ता की किसी किस्म की अनदेखी न हो। हमने हवाई सुरक्षा प्रणाली पर काफी काम किया है, मगर हमें 'अर्ली वार्निंग सिस्टम', एंटी-शिप मिसाइल, मानवरहित ड्रोन आदि मे निवेश करने की जरूरत है। हमने देखा है कि हमसे बहुत कम धन खर्च करने वाले देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम ज्यादा बेहतर है। ये तमाम क्षेत्र हैं, जो विशेष ध्यान की मांग करते हैं। वैसे कुल मिलाकर, यह रक्षा बजट सही मदों में राशि आवंटित करता दिखता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रेल से बढ़ेगी भारतीय तरक्की की रफ्तार

यहां स्कैन करें

विजय दत्त | पूर्व अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड

यह निर्विवाद तथ्य है कि भारतीय रेलवे देश की यातायात और माल परिवहन का मुख्य आधार माना जाता है। आज भी अधिसंख्य यात्री सफर के लिए ट्रेनों और माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे पर नजर रखते हैं। इसलिए रेल बजट में सबकी दिलचस्पी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में भारतीय रेलवे को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं।

सबसे बड़ी घोषणा तो सात हाईस्पीड कॉरिडोर बनाने की हुई है। अभी तक ऐसा हाईस्पीड कॉरिडोर केवल अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर का अपने निर्णायक दौर में है। मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर परियोजना 2018 में शुरू हुई। इसके करीब 70 प्रतिशत हिस्से में काम चल रहा है। अगले साल से इसके चालू होने की संभावना है। प्रस्तावित सात कॉरिडोर में से पांच अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडोर से जुड़ने वाले हैं। जैसे, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और बेंगलुरु से चेन्नई। ये सब कॉरिडोर एक-दूसरे से जुड़कर अहमदाबाद से चेन्नई-बेंगलुरु तक एक ही हाईस्पीड कॉरिडोर बन जाएंगे। इस तरह पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में हाईस्पीड कॉरिडोर का विस्तार हो जाएगा। दो कॉरिडोर उत्तर से पूरब के होंगे, जो दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित हैं। इस कॉरिडोर से पूर्वोत्तर तक हाईस्पीड पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी।

हाईस्पीड ट्रेनों के परिचालन से देश के मुसाफिरों को तो काफी सहूलियत होगी ही, इससे पर्यटन उद्योग को भी बहुत मदद मिलेगी।

प्रदूषण से लड़ाई में भारतीय रेलवे ऐतिहासिक योगदान देने को तैयार है। रेलवे के पूर्ण विद्युतीकरण होने से इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। याद रखिए, रेल कॉरिडोर का लाभ कितना बड़ा होता है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि एक रेलमार्ग की क्षमता 30 सड़कों के बराबर होती है। इससे सड़कों पर परिवहन दबाव कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और मुसाफिरों की जल्दी पहुंच सुनिश्चित होगी। उच्च तकनीक वाली हाईस्पीड ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रतिघंटा होने से ये समय के मामले में विमानन सेवाओं से प्रतिस्पर्द्धा करती हैं। विमान यात्रा में एयरपोर्ट तक पहुंचने, वहां चेकिंग के लिए मानक समय आदि को जोड़ लें, तो यात्रियों के लिए हाईस्पीड ट्रेनें अधिक सुविधाजनक मानी जाएंगी। स्पष्ट है, रफ्तार बढ़ने से अन्य बहुत सारे परिवर्तन भी आएंगे।

देश में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। 'बुद्ध सर्किट' को विस्तार देने की बात की जा रही है। इसमें हाईस्पीड ट्रेनों से पर्यटकों को बहुत मदद मिलेगी। रेलवे पर उत्तर भारत में खासकर दीवाली, छठ या कुंभ आदि मेलों के समय का जो भारी दबाव है, उसे सुगम बनाने की बात की गई है। मेट्रो रेल के बजट में आठ से दस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। ध्यान देने की बात है कि आज भारत और दुनिया रेल की ओर बढ़ रही है। समस्या बस एक है। विद्युत से चलने वाली ट्रेनें तो कार्बन उत्सर्जन नहीं करतीं, लेकिन उनके संचालन के लिए जो विद्युत आपूर्ति हो रही है, वहां पर अभी उत्सर्जन की समस्या है। रेलवे को अभी पचास प्रतिशत विद्युत आपूर्ति ही अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हो रही। 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूर्ण आपूर्ति की बात है। यह भारत ही नहीं, दुनिया के लिए रेलवे का एक बड़ा योगदान होगा।

पिछले कॉप सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पंचामृत' की बात की थी। उसमें उन्होंने 2070 तक भारत को पूर्ण कार्बन मुक्त बनाने की बात कही थी। साल 2030 तक भारतीय रेलवे को पूर्णतः कार्बन मुक्त करने की बात है। यह लक्ष्य समय से पहले ही शायद हासिल हो जाए। चीन के पास 4,000 किलोमीटर हाईस्पीड रेल कॉरिडोर है। भारत में अभी यह लगभग 500 किलोमीटर ही है। जब ये सातों कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे, तो भारत का भी दुनिया में अपना स्थान होगा। गौर कीजिए, सन् 1925 में पहली विद्युत रेल भारत में चली थी। अब तक इसका 99.3 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। इस सौवें साल में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाएगा। तब भारत दुनिया में पूर्ण विद्युतीकृत रेल वाला पहला देश हो जाएगा। साथ ही यह दुनिया से की गई प्रतिबद्धता को भी पूरा कर पाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बड़ा एलान नहीं, पर आम आदमी की जिंदगी को कुछ आसान बनाने का इंतजाम

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का/ जो चीरा तो इक कतरा-ए-खूं न निकला। हालांकि, सरकार ने या वित्त मंत्री ने न तो ऐसा कोई वादा किया था, न ही ऐसा कोई संकेत दिया था। फिर भी, न जाने क्यों बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में फिर मध्यवर्ग या आम वेतनभोगी परिवारों को कुछ खुशखबरी मिल सकती है। अफसोस! बजट के बाद उनके हाथ बस निराशा ही लगी। खास बात यह है कि इसी उम्मीद में इंसान को आखिरी वक्त तक पूरा बजट भाषण सुनना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स में फेरबदल के उल्लेख बजट के एकदम अंत में आते हैं।

अब यह तो एकदम साफ है कि इनकम टैक्स में कोई फेरबदल नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव नहीं होगा, यानी पिछले साल के बजट में इनकम टैक्स में जो राहत मिली थी, अब 31 मार्च 2027 तक उसी से गुजारा करना पड़ेगा। हां, इस बीच नया 'इनकम टैक्स ऐक्ट' लागू हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरने में बदलाव हो जाएगा। इसका पता नया फॉर्म आने पर चलेगा।

टैक्स के मोर्चे पर ध्यान देने वाली एक बात जरूर है कि करदाता की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कुछ और आगे बढ़ेगी। हालांकि, करमुक्त कमाई की सीमा 12 लाख रुपये ही बनी रहेगी, लेकिन कम टैक्स भरने वाले लोगों को राहत देने का एक इंतजाम किया गया है। आयकर के शुरुआती स्लैब में आने वाले लोगों के लिए 'निल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट' का काम अब स्वतः हो जाएगा।

कुल मिलाकर मध्यवर्ग के लिए यह बजट अलग से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन हिसाब जोड़ना हो और कान घुमाकर पकड़ने की कोशिश करें कि इस बजट में ऐसा क्या कुछ है, जिसका फायदा हो सकता है, तो इसे पता करना आसान नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। बस, कुछ तबकों की जिंदगी कुछ आसान करने का इंतजाम किया गया है।

विदेश यात्रा के पैकेज बुक करवाने वालों और विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की फीस भरने पर टीसीएस या 'टैक्स कलेक्शन एट सोर्स' की दरों को घटाया गया है। इसका किसी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि टैक्स भरने वाले लोगों को पहले भी इसका रिफंड मिलता था, अब भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें उतनी ही कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। फर्क इतना होगा कि जितनी रकम इस चक्कर में अटकी रहती थी, अब उससे कम अटकेगी। मामूली राहत की यह खबर भी किसके लिए है? जो लोग हर साल एक या दो विदेश यात्रा करते हैं या जिनके बच्चे महंगी फीस भरकर विदेशी स्कूल या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं।

करदाता की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश अब कुछ और आगे बढ़ेगी। हालांकि, करमुक्त कमाई की सीमा 12 लाख रुपये ही बनी रहेगी, लेकिन कम टैक्स भरने वाले लोगों को राहत देने का एक इंतजाम किया गया है।

दूसरी तरफ, यह कहा जा सकता है कि बजट में बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिनका फायदा लंबे समय में दिखेगा। ऐसे कदम तलाशना भी आसान नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सरकार जो चाहती है, वह हो भी जाए, तो उसका असर दिखने में लंबा समय लगेगा। यह कैसे चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, तो लॉजिस्टिक्स खर्च कम होगा। इससे कंपनियों के पास मुनाफे की गुंजाइश बढ़ेगी। अब वे दाम घटा सकते हैं या अपने कामगारों का वेतन बढ़ा सकते हैं। दोनों सूरत में आम आदमी तक फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इतिहास है कि वेतन बढ़ाने का काम यहां आसानी से होता नहीं है।

शेयर बाजार में हाहाकार मचा है, क्योंकि वायदा सौदों पर लगने वाला 'सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स' बढ़ा दिया गया है। हालांकि, चाणक्य के अनुसार यह वैसा टैक्स है, जैसे खाने में नमक, शायद उससे भी कम, लेकिन सरकारी खजाने में इससे अच्छी-खासी रकम आती है। बाजार के कुछ जानकारों का कहना है कि यह टैक्स बढ़ाकर सरकार ने बहुत से छोटे निवेशकों का भला ही किया है, क्योंकि शेयर बाजार में सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के बजाय उस पर लगाम कसी जाएगी, तो आखिरकार यह बाजार की सेहत और निवेशकों की जेब के लिए अच्छा रहेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

2027
तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय एक लाख तक पहुंचाना लक्ष्य

500
जलाशय और अमृत सरोवर के निर्माण से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा

1.3
लाख करोड़ रुपये की वृद्धि रक्षा मद में हुई, 14.68 प्रतिशत है कुल बजट का

> बजट सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को गति देगा और रणनीतिक एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इससे जीवन सुगम होगा, शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी।
> **-धर्मेंद्र प्रधान**, केंद्रीय शिक्षा मंत्री

वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं से जुड़े कई अहम ऐलान किए, अपने उत्पाद बेचने के बेहतर मौके मिलेंगे

महिला उद्यमियों को बढ़ावा देगी 'शी मार्ट'

स्वावलंबन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में महिलाओं से जुड़े कई अहम ऐलान किए। इसका सीधा फायदा देश की आधी आबादी को होगा। बजट में लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे 'शी मार्ट' से जोड़ा गया। इससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के बेहतर मौके मिलेंगे। वित्त मंत्री ने हर जिले में महिला छात्रावास की भी घोषणा की।

लखपति दीदी योजना की अभूतपूर्व सफलता के बाद सरकार अब 'शी मार्ट' की नई अवधारणा लेकर आई है। यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सीधे बड़े बाजारों से जोड़ेगी। 'शी मार्ट' आधुनिक रिटेल आउटलेट होंगे, जिन्हें पूरी तरह से महिला उद्यमियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके जरिए महिलाएं बिचौलियों के बिना अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगी और अपना खुद का ब्रांड स्थापित कर सकेंगी।

ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाओं को अधिक फायदा : बजट 2026 में ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। स्थानीय स्तर पर रिटेल और बिजनेस इकोसिस्टम तैयार करने की योजना है, ताकि महिलाएं अपने ही इलाके में रोजगार और उद्यम के मौके बना सकें। शाी मार्ट को चलाने व आगे बढ़ाने में क्लस्टर-लेवल फेडरेशन की अहम भूमिका होगी। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को संगठित ताकत मिलेगी और उनके कारोबार को बढ़ाने मदद मिलेगी।

महिलाएं बनेंगी मालकिन : शी मार्ट योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मालकिन के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। वे सिर्फ लाभार्थी के रूप में नहीं रहेंगी। वो अपने काम को नए आयाम तक पहुंचाने में भी पूरी मदद की जाएगी।

उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा : शी मार्ट योजना के तहत महिला द्वारा तैयार उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को खुद के काम को मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। दूर दराज क्षेत्रों में बनने वाले उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

महिला कामगारों में होगा इजाफा : केंद्र ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा था देश में वर्ष 2050 तक महिला कामगारों की भागीदारी 50% से अधिक हो जाएगी। ये तेजी देश की जीडीपी के लिए बेहद अहम है। समाज के हर वर्ग को काम से पैसे के प्रवाह को बढ़ाना है।

आधी आबादी की ताकत बढ़ेगी : ईवाई के सोशल स्किल विशेषज्ञ अमित वात्सयान का कहना है लखपति दीदी और शी मार्ट योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आजीविका के नए अवसर खुलेंगे।

आधी आबादी अर्थव्यवस्था की रीढ़ : गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मौजूदा समय में 40% महिला आबादी कामगार है। इसमें से अधिकतर कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। वहीं दूसरे बड़े देशों में ये हिस्सेदारी 54 फीसदी के करीब है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका भारत तेजी से अपनी आधी आबादी की शक्ति के जरिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

लखपति दीदी के लाभार्थी

राज्य	संख्या	तीन साल में बजट
मध्य प्रदेश	12,84,957	1465.27
उत्तर प्रदेश	11,15,982	4433.45
बिहार	14,47,75	3079.50
उत्तराखंड	43,266	233.42
झारखंड	4,81,9	1161.1
हरियाणा	58,577	286.67

(स्रोत : पीआईबी/डिजिटल संसद 2025 बजट करोड़ रुपये में)

प्रमुख घोषणाएं

- महिला उद्यमियों के लिए शी मार्ट की स्थापना
- हर जिले में महिला छात्रावास बनाया जाएगा
- लखपति दीदी योजना को विस्तार मिलेगा
- महिलाओं को स्टार्टअप्स बढ़ावा दिया जाएगा

क्या है शी मार्ट

बजट में लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे 'शी मार्ट' से जोड़ा गया। शी मार्ट महिलाओं के लिए समर्पित ऐसे बाजार या मंच हैं, जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने का सीधा अवसर मिलेगा। इसके तहत ग्रामीण महिलाएं कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और छोटे व्यवसायों में अपने उत्पाद बेच सकेंगी और अपनी आय बढ़ा सकेंगी।

निर्भया फंड को 200 करोड़

बजट 2026 में केंद्र सरकार ने निर्भया फंड को भी दो सौ करोड़ रूपए आवंटित किए। निर्भया फंड भारत सरकार द्वारा 2013 के केंद्रीय बजट में स्थापित एक समर्पित वित्तीय कोष है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है। यह 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद शुरू किया गया था।

हर जिले में महिला छात्रावास

बजट में देश के हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। हॉस्टल की सुविधा सुनिश्चित करने की योजना है। वित्त मंत्री ने कहा, हर जिले में छात्रावास का मकसद छात्राओं के लिए समान रूप से शैक्षिक अवसर बढ़ाना व सुरक्षित रहने की जगह देना है। ग्रामीण इलाकों में निरंतर चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे कि किशोरियों के बीच में स्कूल छोड़ने की दर। हर जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का मकसद शिक्षा के रास्ते में आने वाली उनकी इस अड़चन को दूर करना है। यह कदम उन जिलों पर फोकस करेगा जहां दूरी, सुरक्षा की चिंता और पैसे की कमी पढ़ाई जारी रखने में रुकावट बनती हैं।

'लखपति दीदी' योजना का होगा विस्तार

वित्त मंत्री ने लखपति दीदी योजना के विस्तार का भी ऐलान किया। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इसका लक्ष्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं छोटे-छोटे उद्योग शुरू करें और हर साल कम से कम एक लाख की कमाई करें। 2027 तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय एक लाख तक पहुचाना लक्ष्य सरकार का लक्ष्य है। योजना के विस्तार से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

नारी शक्ति पर सरकार की अच्छी पहल

विशेषज्ञ की राय

राकेश श्रीवास्तव
पूर्व सचिव भारत सरकार

बजट में लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे शी मार्ट से जोड़ा गया है। शी मार्ट के जरिए महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने की योजना सरकार का अच्छा कदम है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। महिलाओं को सबसे ज्यादा आर्थिक सुरक्षा की दरकार है। लखपति योजना के तहत भी महिलाओं को करोड़पति बनाने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है। स्वंयसेवी सहायता समूहों को मजबूत बनाने और लखपति दीदी जैसी योजनाएं भी सरकार ने जारी रखी हुई हैं।

निर्भया कोष पर फोकस बने रहने से महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। हालांकि इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जरूरत है। वीबी- जी राम जी के अंतर्गत बाल देखभाल को शामिल करने से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में विविधता आएगी। सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य पर जोर देने से बाल पोषण को बढ़ावा देने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

बजटीय परिव्यय में 3.27 लाख करोड़ रुपये से 4.49 लाख करोड़ रुपये तक की पर्याप्त वृद्धि महिला एवं बाल विकास योजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

मुफ्त कानूनी सहायता के लिए 100 करोड़ आवंटित

■ **प्रभात कुमार**

नई दिल्ली। भले ही आम बजट में विधि एवं न्याय मंत्रालय के बजट 2026-27 में कटौती की गई है लेकिन केंद्र सरकार ने जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

केंद्र ने बजट में कानून मंत्रालय द्वारा लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 100 करोड़ की बढ़ोतरी की है। बजट में, इस बार कानून मंत्रालय के लिए 4509.06 करोड़ आवंटित करने का प्रावधान किया है जो कि 2025-26 की तुलना में 489 करोड़ रुपये कम है। 2024-25 में सरकार ने बजट में कानून मंत्रालय को 7189.58 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया था और 2025-26 में 4998.24 रुपये का प्रावधान किया है। इसी तरह अब सरकार ने 2026-27 के लिए 489 करोड़ की कमी के साथ महज 4509 करोड़ रुपये आवंटन का प्रावधान किया है। हालांकि, कानून मंत्रालय को दिए गए बजट में केंद्र सरकार कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली मद में बजट में 100 करोड़ अधिक आवंटन का प्रावधान किया गया है।

ईवीएम के लिए बजट में वृद्धि

सरकार ने कानून मंत्रालय को दिए बजट में ईवीएम के लिए बजट में करीब 80 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में ईवीएम के लिए 99 .21 करोड़ आवंटित करने का प्रावधान किया है।

विदेशी मीडिया में प्रमुखता से छाया रहा केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट रविवार को विदेशी मीडिया में भी छाया रहा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत के बजट को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में कवर किया।

> भारत के बजट में बुनियादी ढांचे और घरेलू विनिर्माण पर अरबों रुपये आवंटित किए गए। - **द न्यूयॉर्क टाइम्स**

> भारत ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा है। बुनियादी ढांचे पर खर्च बरकरार । -**रायटर्स**

> निवेशकों के लिए अनुकूल बजट है। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील दी। - **द गार्जियन**

> रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय और 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा साहसी कदम है। -**बीबीसी**

> राजकोषीय अनुशासन संग विकास का संतुलन और ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन को टक्कर देने की तैयारी है।
> -**वाशिंगटन पोस्ट**

> बजट में भारत सरकार का ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर ज्यादा रहा।
> -**अलजजीरा**

'वीबी-जी राम जी' के लिए बंपर बजट

नई योजना

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने नई योजना 'वीबी-जी राम जी' को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692.31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मनरेगा के लिए मौजूदा वित्त में 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 88,000 करोड़ रुपये किया गया। 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन-ग्रामीण' (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत साल में 125 दिनों के काम का वादा किया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के तहत बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल की दो दशक पुरानी ग्रामीण रोजगार योजना का स्थान लेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा योजना तब तक जारी रहेगी, जब तक 'वीबी-जी राम जी' पूरी तरह अमल में नहीं आ जाती और इसके तहत लंबित कार्य पूरे नहीं हो जाते।

ग्रामीण विकास विभाग को 1,94,368.81 करोड़ : बजट दस्तावेजों के अनुसार, मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल 1,94,368.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के 1,86,995.61 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक है। वर्ष 2026-27 के लिए भूमि संसाधन विभाग को 2,654.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में इस विभाग के लिए 2,651 करोड़ रुपये का आवंटन था, जबकि संशोधित अनुमान के अनुसार वास्तविक खर्च 1,757.4 करोड़ रुपये रहा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 19,000 करोड़ मिले : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए वर्ष 2026-27 का आवंटन 19,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो 2025-26 के बराबर ही है। हालांकि, संशोधित अनुमान के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में इस पर खर्च 11,000 करोड़ रुपये हुआ था।

ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 19,200 करोड़ का प्रस्ताव : दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2026-27 का आवंटन बढ़ाकर 19,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले साल यह राशि 19,005 करोड़ रुपये थी, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक 16,000 करोड़ खर्च हुए।

गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे ज्यादा धन : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे ज्यादा 2,27,429 करोड़ रुपये का प्रावधान है, हालांकि यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में 325 करोड़ रुपये कम है। वहीं, सरकार का लक्ष्य 2027 तक लखपति दीदी की संख्या को बढ़ाकर तीन करोड़ तक पहुंचाना है।

125
दिनों के काम का वादा प्रतिवर्ष

30
हजार करोड़ रुपये मनरेगा को भी मिले

पीएमएवाई-जी को 54,916.70 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए इस साल 54,916 .70 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। पिछले बजट में यह राशि 54,832 .00 करोड़ रुपये थी और संशोधित अनुमान में खर्च 32,500 .01 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 67,670 करोड़ आवंटित

इसके अलावा 'जल जीवन मिशन-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन' के लिए आवंटन 17,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 67,670 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन 63,500 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा गया है। पीएम फसल बीमा योजना में 12,200 करोड़, पीएम आशा के लिए 7,200 करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया गया है।

वर्ष 2027 तक तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

लखपति दीदी योजना के तहत अब तक दो करोड़ महिलाएं सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य 2027 तक इस संख्या को तीन करोड़ तक पहुंचाना है।

क्या है रिफॉर्म एक्सप्रेस

रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब है- नीतिगत फैसलों में तेजी लाना और पुराने और जटिल कानूनों का सरलीकरण करना। साथ ही इसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और निवेश तथा रोजगार सृजन पर फोकस करना है। रिफॉर्म एक्सप्रेस हमारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी गति बनाए रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि सरकार का मूल मंत्र 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' है। रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव कर रही है।

रेयर अर्थ मेटल : दुर्लभ खनिजों के लिए प्रोत्साहन

वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार उन राज्यों को समर्थन देगी जहां रेयर अर्थ मेटल मौजूद हैं। रेयर अर्थ मेटल 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है, जिसमें लैंथेनाइड्स के साथ-साथ स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं।

हालांकि इनके नाम में 'रेयर' यानी दुर्लभ शब्द जुड़ा है, लेकिन असल में ये धरती की परत में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दुनियाभर में रेयर अर्थ मेटल में अभी चीन का दबदबा है। इन दुर्लभ पदार्थों का इस्तेमाल ईवी वाहन, मोबाइल बैट्री, स्मार्टफोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव इत्यादि क्षेत्रों में होता है।

SWEATER
JACKETS
SALE
WINTER OFFER
Hi-Fashion New Collection
BRANDED Sweaters, Jacket, Sweat Shirt, Lower, Cardigan & winter wears
upto 60% off
By Economy Sales: 9212758425
ARROW | Raymond | ColorPlus | Levi's | PARK AVENUE
• PUNCHKUIAN ROAD,Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
• GURUGRAM 306, City Center, Sector 29 (Near Hotel Pllazio)
• WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
• NOIDA , Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

एन बी सी सी NBCC A Navratna CPSE
ASPIRE
माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली आवास परियोजना लर्नेड कोर्ट रिसीवर के माध्यम से
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा निष्पादित
ई-नीलामी के माध्यम से मालसूची की थोक बिक्री
एस्पायर लेज़र वैली
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
मालसूची आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी. एच. के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन - 35 मिनट
एस्पायर सिलिकॉन सिटी
फेज़-IV, सेक्टर-76, नोएडा, उत्तर प्रदेश
मालसूची - आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी.एच.के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
स्पेक्ट्रम मॉल, नोएडा के पास और निकटतम मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर-50 (एक्वा लाइन) एवं सेक्टर-76 मेट्रो हैं तथा आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन - 25 मिनट
एस्पायर सेंचुरियन पार्क
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी.एच.के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन - 30 मिनट
एस्पायर लेज़र पार्क
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी.एच.के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन - 30 मिनट
ई.एम.डी. जमा करने की अंतिम तिथि: 10.02.2026
ई-नीलामी 11.02.2026 को आयोजित की जाएगी
ई.एम.डी. राशि 9.70 करोड़ रु. से 20.90 करोड़ रु. तक
6 पैकेज जिनका मूल्य 485 करोड़ रु. से 1,045 करोड़ रु. तक है
प्री-बिड मीटिंग दिनांक 03-02-2026 को आयोजित की जाएगी
कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें:
www.nbccindia.in I www.receiveramrapali.in
या कॉल करें : 9772907414
कृपया ई-नीलामी दस्तावेज के लिए क्यूआर स्कैन करें:

आम बजट 2026-27

उत्तर प्रदेश ● उत्तराखंड ● बिहार ● झारखंड

2200 करोड़ की व्यवस्था की गई दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए

5000 करोड़ की व्यवस्था की गई टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के विकास के लिए बजट में

900 करोड़ रुपये यूपी के हिस्से पांच सालों में करीब आने का अनुमान लगाया जा रहा है

> बजट संतुलित और भविष्योन्मुखी है। यह आत्मनिर्भरता को दर्शाता है और विनिर्माण क्षेत्र में हमारी स्थिति को मजबूत करेगा। इससे व्यापार करने में आसानी होगी। बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
> –एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएम

चुनावी राज्यों को साधने से ज्यादा सुधारों और मिशन 2047 पर जोर

विश्लेषण

■ रामनारायण श्रीवास्तव

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार सुबह संसद में आम बजट को पेश करने कांजीवरम की साड़ी पहनकर पहुंची तो एकबारगी लगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी बजट में चुनावी राज्यों के लिए कुछ खास होगा। पर, जैसे-जैसे बजट भाषण आगे बढ़ा वित्त मंत्री की सुधार एक्सप्रेस चुनावी राज्यों के स्टेशनों पर बिना रुके 'मिशन-2047' की तरफ तेजी से बढ़ गई।

हालांकि, कुछ घोषणाओं में चुनावी राज्यों का उल्लेख जरूर हुआ। दो माह के भीतर देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज होना है। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम एवं पद्दुचेरी शामिल हैं। ऐसे में, अटकलें थीं कि वित्त मंत्री इन राज्यों को अपनी घोषणाओं से सीधा संदेश देगी। दरअसल, पिछली बार वित्त मंत्री ने बजट में जिस तरह से बिहार को साधा था, उससे ऐसा सोचना लाजिमी था। तब वित्त मंत्री मधुबनी कला से सजी साड़ी पहन कर आई थीं और छह बार बिहार का नाम लिया था। मखाना, मधुबनी एवं मिथिलांचल का भी खासा उल्लेख था।

इस बार यह परंपरा तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी से शुरू तो हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। बजट भाषण में पश्चिम बंगाल का नाम भी नहीं आया। असम का एक बार, तमिलनाडु और केरल का दो बार उल्लेख किया गया। पद्दुचेरी का तो सवाल ही नहीं उठा।

अलबत्ता तेजपुर, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, चेन्नई जैसे चुनावी राज्यों से जुड़े शहरों का विभिन्न घोषणाओं में उल्लेख जरूर हुआ। दक्षिण में भी किसानों और उत्पादन के हिसाब से काजू, नारियल एवं चंदन की घोषणाओं से कुछ संदेश गया। मनरेगा पर मचे बवाल में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान का जिक्र हुआ और खादी, हैंडलूम एवं हस्तकला को मजबूत करने की बात हुई।

पश्चिम बंगाल के नादिया में रविवार को हथकरघा श्रमिक कपड़ा सुखाते हुए। केंद्रीय बजट में उद्योगों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। •प्रेट्र

मध्य वर्ग का जिक्र नहीं

भाजपा का मजबूत समर्थक मध्य वर्ग का पिछले बजट भाषण में आधा दर्जन से ज्यादा बार उल्लेख किया गया था, इस बार वह गायब था। आयकर में ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं थी, सो दिखा भी नहीं। भाजपा के भीतर माना जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें भाजपा के मिशन में सबसे अहम पश्चिम बंगाल है, जहां घोषणाओं से ज्यादा फायदा नहीं होता। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति थी।

देश की मजबूती अहम

सरकार के लिए यह साल शताब्दी के चार चरणों में दूसरे चरण का आधार वर्ष है। इसलिए यहां पर मिशन विकसित भारत 2047 की नींव रखी जानी थी। सरकार ने वही किया। इसे सियासी तौर पर दूरदृष्टि वाली राजनीति कही जा रही है, जिसमें मौजूदा वैश्विक परिदृष्य में देश की मजबूती को अहम माना जा रहा है।

देश को मजबूत करने में तेजी लाने वाला बजट : शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम बजट भारत को वैश्विक मंच पर पारंपरिक से लेकर नए दौर के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की रफ्तार को तेज करेगा।

शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, विनिर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, विकसित भारत बजट एक ऐसा बजट है जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के सपनों को सशक्त बनाता है, ताकि वे उन सपनों को साकार कर सकें। बजट राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लक्ष्य को पूरा करता है। बजट 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की परिकल्पना और अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप पेश करता है। पूंजीगत व्यय के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित करके, बजट ने प्रधानमंत्री के भविष्य के लिए तैयार भारत के दृष्टिकोण को गति प्रदान की है, जहां विकास प्रमुख शहरों से परे तक फैला है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने बजट को लेकर एक्स पर पोस्ट किया

टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के विकास पर विशेष ध्यान रखा

यूपी के 45 शहरों में और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी

उत्तर प्रदेश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। केंद्रीय बजट ने यूपी के छोटे से लेकर बड़े शहरों तक में विकास की राह खोल दी है। केंद्र सरकार के बजट में इस बार टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

केंद्र सरकार का फोकस सिर्फ महानगरों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उभरते हुए छोटे शहरों पर भी दिया गया है। टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के विकास के लिए बजट में 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

केंद्र सरकार ने इन शहरों में आने वाले समय में आबादी के हिसाब से सुख-सुविधा देने की घोषणा की है। यह पैसा पांच सालों में खर्च किया जाएगा। सर्वाधिक आबादी और इसके दायरे में आने वाले 45 शहरों को देखते हुए यूपी के हिस्से पांच सालों में करीब 900 करोड़ रुपये आने का अनुमान लगाया जा रहा है।

सड़क से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा : केंद्र का मानना है कि आने वाले समय में टियर-टू और टियर-थ्री वाले शहर अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। इसलिए इन शहरों के विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इन शहरों में विकास के पहिये को आगे बढ़ाते हुए जरूरत के हिसाब से काम कराए जाएंगे। इसमें सड़क, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

लखनऊ से लेकर नोएडा तक विकास : आबादी के हिसाब से यूपी देश को सबसे बड़ा राज्य है। टियर-टू की घोषणा के मुताबिक 15 शहर हैं। इन शहरों की आबादी पांच लाख से अधिक है। टियर टू वाले शहरों में लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी और मथुरा आ रहे हैं। बढ़ती आबादी के हिसाब से इन शहरों के विकास की सर्वाधिक जरूरत है। हालांकि, स्मार्ट सिटी परियोजना में इन शहरों में काम कराए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस योजना को बंद कर दिया है। इसीलिए नई योजना शुरू करते हुए विकास के लिए पैसा देने का फैसला किया गया है।

टियर थ्री में 30 शहरों का होगा विकास : यूपी में टियर थ्री के करीब 30 शहर बताए जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश आठ, पश्चिमी यूपी के छह, मध्य यूपी छह, बुंदेलखंड पांच व अन्य पांच शहर हैं। इन शहरों की आबादी एक लाख से लेकर तीन लाख तक है। अमृत के साथ स्टेट सेक्टर की योजनाओं से इन शहरों में बुनियादी सुविधाएं देने का काम कराया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नई योजना शुरू किए जाने से इनके और अधिक विकास की राह खुल गई है।

राज्य सरकार चाहती है कि स्थानीय स्तर पर इतनी सुविधाएं दे दी जाएं, जिससे लोगों का पलायन रुके और वे वहीं पर रोजी-रोजगार करें। इससे विकास की दर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।

हस्तिनापुर-सारनाथ की चमक और बढ़ेगी

लखनऊ। धार्मिक पर्यटन के मामले में अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग के साथ अब हस्तिनापुर और सारनाथ की चमक भी बढ़ेगी। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्राथमिकता दी गई है। देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को 'एक्सपीरिएंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित करने की योजना में सारनाथ और हस्तिनापुर को शामिल किया जाना यूपी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इन स्थलों का न सिर्फ तेजी से विकास होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ का विकास इस तरह किया जाएगा कि उसकी पवित्रता और ऐतिहासिक गरिमा बनी रहे।

नए भारत की संकल्पना की स्पष्ट दृष्टि : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026–27 की सराहना करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नए व विकसित भारत की संकल्पना का रोडमैप लेकर देशवासियों के सामने नया बजट प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व निर्णायक नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कर्तव्य भवन में बने पहले बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद ज्ञापित किया।

कारोबार और रोजगार के मौके बढ़ेंगे

बिहार

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्रीय बजट के प्रावधानों से बिहार में कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से सिलीगुड़ी और दिल्ली से बिहार जुड़ जाएगा। वहीं जलमार्गों के विकास से नदी किनारे शहरों से माल ढुलाई आसान हो जाएगी। इससे व्यापार बढ़ेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

बजट में पूर्वोदय राज्यों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की गयी है। इससे जुड़ी विकास योजनाओं से बिहार को फायदा होगा। यहां औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना और युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। देश में सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसमें वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ज्यादातर हिस्सा बिहार होकर ही गुजरेगा। वाराणसी से दिल्ली तक अलग कॉरिडोर होगा।

इस तरह बिहार दिल्ली तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। वहीं, सात जलमार्गों के विकास से जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। गंगा के अलावा गंडक, कोसी, घाघरा, कर्मनाशा, पुनपुन और सोन नदी के रास्ते परिवहन शुरू होगा। इन नदियों के किनारे बसे शहरों से एक-जगह से दूसरी जगह तक माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी।

35 लाख एमएसएमई इकाइयों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा

20 वर्ष में 21 फीसदी से अधिक हो गया है उद्योगों का योगदान राज्य में

औद्योगिक निवेश का अवसर मिलेगा : नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय बजट में विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाने के लिए पूर्वोदय राज्यों और उत्तर–पूर्व क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की गई है। इससे जुड़ी विकास की योजनाओं से बिहार को औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना और युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शहरों के विकास के लिए किए प्रावधानों से शहरीकरण को नई गति मिलेगी।

केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं : खरगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को केंद्रीय बजट को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास नीति, दृष्टि, समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि वंचित वर्गों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई तथा किसानों की भी उपेक्षा हुई है।

खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी सरकार के पास अब नए विचारों की कमी दिखती है। बजट-2026 भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। मिशन मोड अब चैलेंज रूट बन गया है। अब कोई नीति-दृष्टि नहीं है। हमारे अन्नदाता किसान आज भी सार्थक कल्याणकारी समर्थन या आय सुरक्षा योजना का इंतज़ार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के दौर से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन बजट में इसका ज़िक्र तक नहीं है और न ही एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई सहायता दी गई है।

वित्त आयोग की सिफारिशों का और अध्ययन करना होगा, लेकिन वे भी गंभीर वित्तीय दबाव में चल रही राज्य सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिखतीं तथा संघवाद इसकी बलि बन गया है।

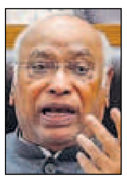

कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की आलोचना की

राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय करों में 1841 करोड़ बढ़ी

उत्तराखंड

■ चंद्रशेखर बुड़ाकोटी

देहरादून। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों में उत्तराखंड का हिस्सा 1841 करोड़ रुपये तक और बढ़ जाएगा। रविवार को संसद में पेश आम बजट के प्रावधानों की बदौलत ऐसा होने जा रहा है।

इसके साथ ही पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत उत्तराखंड को 500 करोड़ रुपये अधिक मिलने का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए किए गए प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है।

वर्तमान वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में उत्तराखंड के लिए 15 हजार 573 करोड़ रुपये तय किए गए थे। इस वर्ष इस राशि में 1841 करोड़ रुपये और बढ़ जाएंगे। इससे नए वित्तीय वर्ष के लिए यह राशि 17 हजार 414 करोड़ हो जाएगी।

सरकार से कोई उम्मीद नहीं : विपक्ष

नई दिल्ली, विसं। विपक्ष ने वर्ष 2026-27 के आम बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि देश को भाजपा की अगुवाई वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह बजट सिर्फ पांच फीसदी लोगों के लिए बनाया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिया।

बजट विकसित राष्ट्र की दिशा में कदम : नवीन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय बजट को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अगला कदम करार दिया है।

उन्होंने इसे गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने वाला बताया है।

नवीन ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों के अटूट भरोसे को दिखाता है। नवीन ने एक बयान में कहा है कि बजट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नीतियों और सुशासन की निरंतरता को साफ तौर पर दिखाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था लगभग सात प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, उससे संकेत मिलता है कि जीएसपी और जीडीपी लगातार मजबूत हो रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट की सराहना की

तीन रसायन पार्क स्थापित करेगा केंद्र

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र ने रविवार को कहा कि वह तीन विशेष रसायन पार्क की स्थापना में राज्य सरकारों की मदद के लिए एक योजना शुरू करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम तीन डेडिकेटेड रसायन पार्क स्थापित करने में राज्यों की सहायता के लिए एक योजना शुरू करेंगे।

दुर्लभ खनिज कॉरिडोर का लाभ राज्य को मिलेगा

झारखंड

■ सत्यदेव यादव

रांची। लोकसभा में रविवार को वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट से झारखंड को भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से लाभ मिलेगा। राज्य को दुर्लभ खनिज कॉरिडोर का लाभ मिलेगा।

बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार रांची की मानसिक आरोग्यशाला (सीआईपी) जहां निमहांस की तरह विकसित होगी वहीं राज्य में पर्यटन और शहरी विकास को भी गति मिलेगी।

अस्पतालों में ट्रॉमा व आपातकालीन सेवाओं का विस्तार, टियर-2 और टियर-3 शहरों के सुनियोजित विकास तथा हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण जैसे ऐलान राज्य के सामाजिक-आर्थिक भविष्य को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में झारखंड बनेगा पूर्वी भारत का केंद्र : रांची में संचालित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (सीआईपी) को निमहांस की तरह विकसित करने का है। यह संस्थान अब सुपर-स्पेशियलिटी इलाज, उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा।

आदिवासी इलाकों में ट्रॉमा सेंटर से राहत मिलेगी

स्वास्थ्य क्षेत्र में ही बजट ने जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की घोषणा की है। इस पहल से गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। माता की सेहत में सुधार होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। लाभ के मौके मिलेंगे।

वृष : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। आय में वृद्धि भी हो सकती है।

मिथुन : वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास में कमी भी हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में भी वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव व स्थान परिवर्तन हो सकता है।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

तुला : आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। भवन सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। अच्छे खानपान में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक : नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। कारोबार का विस्तार हो सकता है। पिता से तथा परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिवार व किसी मित्र का साथ मिल सकता है।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चे बढ़ेंगे। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

2 फरवरी, सोमवार, **शक संवत्:** 13 माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 20 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 13 शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्:** फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि रात्रि 01.53 बजे तक पश्चात द्वितीया तिथि, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 10.48 बजे तक पश्चात मघा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में रात्रि 10.48 मिनट तक उपरांत सिंह राशि में।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारंभ। गण्डमूल विचार।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हम एक ऑफिस बनवा रहे हैं जो कि पश्चिम मुखी है। कृपया बताएं किन बातों का ध्यान रखें?
–भावित जोशी, दिल्ली

- मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पश्चिम या पश्चिम के पुष्पदंत पद में बनाएं।
- दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार बिल्कुल भी न बनाएं।
- कैश काउंटर दुकान के उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में रखें।
- अपना बैठने का स्थान दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाएं।
- इस दिशा में एक छोटा सा पीतल का ऊंट रखें।
- इस दिशा में वरुण देवता का चित्र एवं इनका यंत्र लगाना शुभ रहेगा।

वर्ग पहेली : 8228

1		2		3		■	4	■
	■		■		■	5		
6						■		■
	■		■		■	7		
■	8			■	9			■
10			■	11	■		■	12
■		■	13					
14			■		■		■	
■		■	15					

बाएं से दाएं
1. गिरों को उठाने वाला; ईश्वर (6)
5. बयार; वायु; समीर; हवा (3)
6. किसी ठीक बात को गलत समझा जाना; कुछ का कुछ समझा जाना; भूल से कुछ का कुछ समझा जाना; भ्रम (6)
7. तला; पदतल; पैर के नीचे का भाग (3)
8. कस्बे से बड़ी मानव बस्ती जहां अधिकतर पक्के मकान हों; नगर (3)
9. देना; सुपुर्द करना; हवाले करना (3)
10. छल; धोखा; दुराव; छिपाव; दंभ (3)
13. गल जाना; घोलना; मिलाना; सम्मिलित करना (3,3)
14. रस से सराबोर तली हुई घेरेदार मिठाई (3)
15. प्रशंसा होना; तारीफ होना; बड़ाई होना (4,2)

ऊपर से नीचे
1. अनुरक्त होना; पराग से युक्त करना (4)
2. क्रोध का भाव; गुस्से या धूप के कारण चेहरा लाल हो जाने की स्थिति; तमतमाने का भाव (6)
3. इंद्र; अग्नि; शिव (4)
4. अवज्ञा करना; तिरस्कार करना; अवज्ञा; अपमान (5)
7. तप करना; व्रतचर्या करना (3,3)
8. कसम खाना; प्रतिज्ञा करना; सौगंध उठाना; हलफ उठाना (3,2)
11. जल का प्रवाह; पानी की धारा (4)
12. ज्ञात; प्रचलित; देखा भाला; परखा हुआ; प्रसिद्ध (2,2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8227

■	1 अ	2 वि	श्वा	3 स	क	4 र	ना	■
5 ए	■	वे	■	दा	■	वि	■	6 ह
7 क	चू	च	8 र	■	9 आ	■	10 भी	र
पं	■	11 क	स	म	सा	ना	■	क
12 ध	ल	■	ही	■	न	■	13 भू	त
दो	■	14 अ	न	र्थ	हो	15 ना	■	क
16 का	या	■	ता	■	17 ना	म	दा	र
ज	■	18 बा	■	19 प	■	दे	■	ना
■	20 र	ण	नी	ति	ब	ना	ना	■

सुडोकू : 8210

* मध्यम

4				6				5
7								4
	1	2				3	7	
		4	7		6	5		
			1		9			
		9	8		5	2		
	2	8				7	6	
9								2
5				7				1

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8209

8	5	6	3	7	2	4	1	9
4	1	7	9	8	6	3	2	5
3	9	2	1	5	4	8	7	6
9	7	4	8	2	5	6	3	1
6	2	3	7	9	1	5	4	8
1	8	5	6	4	3	2	9	7
5	6	9	2	3	7	1	8	4
7	3	1	4	6	8	9	5	2
2	4	8	5	1	9	7	6	3

निर्णायक कदम की रूपरेखा बजट में

कनेक्टिविटी, विनिर्माण क्षमता और क्षेत्रीय संतुलन पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए, बजट विश्व स्तरीय, भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक निर्णायक कदम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

***नितिन गडकरी**, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री*

बजट 2026-27

फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर

आधुनिकीकरण के काम होंगे

सरकार एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत करने जा रही है, जो पश्चिम बंगाल को गुजरात से जोड़ेगा। रेल बजट में 2.78 लाख करोड़ का प्रावधान है। रेलवे सुरक्षा, आधुनिकीकरण, यात्री सुविधा के काम होंगे।

अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री

बुनियादी ढांचा मजबूत कर स्किल्ड रोजगार और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के दावे

भोपाल, जयपुर और रायपुर जैसे शहर देंगे महानगरों को टक्कर

भोपाल, इंदौर, जयपुर, अजमेर, रायपुर जैसे टियर-2 के अलावा टियर-3 शहरों के विकास पर सरकार ने फोकस किया है। इससे उक्त शहरों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और महानगरों पर दबाव कम होगा। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। यह ऐलान बताता है कि सरकार अब भी पब्लिक इनवेस्टमेंट को अर्थव्यवस्था की डिमांड का सबसे मजबूत सहारा मान रही है। इसी के साथ संकेत भी हैं कि केंद्र सरकार अगले साल भी हाईवे, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और देश में चल रहे या प्रस्तावित दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के खर्च में कटौती के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर छोटे शहरों को भी गति मिलेगी।

पूंजीगत खर्च बढ़ने से बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस कर देश में विकास दर और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा।

निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्तमंत्री

- **उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे**
- **सड़क व ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार की कोशिश**
- **बिजली-पानी जैसी जरूरतों का विस्तार होगा**
- **देश में शहरीकरण का संतुलन बनेगा, पलायन कम होगा**

विशेषज्ञ की राय

प्रो. (डॉ.) अतुल दुबे,
अर्थशास्त्री, भोपाल

बजट में अवसर और भविष्य की तस्वीर

नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार की घोषणाएं यह संकेत देती हैं कि अब विकास की गति को लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी तय करेगी। सरकार का मानना है कि जब सामान तेज और सस्ते दामों पर पहुंचेगा, तभी उद्योग प्रतिस्पर्धी बनेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट में सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि रफ्तार, अवसर और भविष्य की तस्वीर दिखती है।

आम आदमी पर असर

न ज्यादा खुशी और न ही गम, उम्मीद अधूरी

बजट में आम आदमी के लिए यूं तो सीधे कोई घोषणा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के मौके, यात्री सुविधाएं बढ़ाने की बात है। इसके अलावा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए का प्रावधान जारी रहेगा। इसके तहत पीएम सूर्य घर योजना के जरिए सोलर पैनल पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। कई राज्यों के लोगों को रेल सुविधाओं की सौगात भी आगामी वर्षों में मिलेगी।

राज्य पर असर

चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश

रेयर अर्थ कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अराकू घाटी और पुदीगई मलाई में स्थायी पर्वतीय ट्रेल्स विकसित की जाएंगी। महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, प. बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्रप्रदेश को रेल कॉरिडोर से लाभ मिलेगा।

इंडस्ट्री

12.2 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय, यह अब तक की सबसे ज्यादा राशि

11.2 लाख करोड़ रुपए थी यह राशि पिछले बजट में।

रिफॉर्म एक्सप्रेस से दौड़ेंगे देश के उद्योग-धंधे...

वित्त मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग के मद में 70,296 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हालांकि उद्योग और खनिज के मद में 1,90,138.90 करोड़ की व्यवस्था की है। इसमें ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए 21,995.69 करोड़, उद्योग में 163702.34 करोड़ और अलौह खनन व धातुकर्म उद्योग के लिए 3489.32 करोड़ हैं। अन्य उद्योगों के लिए 464.72 व उद्योग व खनिजों पर अन्य व्यय के लिए 468.83 करोड़ रखे हैं। सरकार का पूरा जोर देश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। सरकार ने आर्थिक सुधारों को गति देने 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' का ब्लूप्रिंट पेश किया है। केंद्र अब राज्यों के साथ मिलकर सुधारों को जमीन पर उतारने की तैयारी में है।

बायो-फार्मा पावर: 10,000 करोड़ का बूस्टर

- फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देश को वैश्विक हब बनाने के लिए 'बायो-फार्मा शक्ति' की घोषणा की है। इसके तहत आने वाले पांच साल में 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- **फायदा:** ज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के जरिए विकास और किफायती दवा उपलब्ध कराना।
- **देश में** बायो-फार्मा के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान बनेंगे।

10 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी माइक्रो-स्मॉल यूनिट के लिए

200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर रिवाइव होंगे।

सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स: 40,000 करोड़ का प्रावधान

- टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 'सेमीकंडक्टर मिशन' को विस्तार दिया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के तहत लक्ष्य से दोगुना हासिल करने के बाद सरकार का उत्साह बढ़ा है। इस सेक्टर में 40 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
- **फायदा:** स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार हो सकेगी।

एमएसएमई: ग्रोथ के लिए 10 हजार करोड़ प्रस्तावित

- छोटे उद्योगों यानी (एमएसएमई) को 'चैम्पियन' बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए माइक्रो और स्मॉल यूनिट के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की गई।
- **फायदा:** शहरों को विकास का इंजन बनाने में मदद मिलेगी। आर्थिक ढांचा मजबूत होगा।

रेयर अर्थ मिशन: आयात निर्भरता घटाने की तैयारी

- महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन या अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक कदम उठाया है। रेयर अर्थ तत्वों के खनन और शोध के लिए चार राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कॉरिडोर बनेंगे।
- **फायदा:** आयात कम करना, घरेलू स्तर पर स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की सप्लाई चेन बनाना।

ऊर्जा

32,914 करोड़ का प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा के लिए

40 लाख और घरों को सोलर से करेंगे रोशन

सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में 1,09,029 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का आवंटन बढ़ाकर 32,914 करोड़ रुपए किया है। यह पिछले बजट से 30% ज्यादा है। पिछले बजट में 25,301.22 करोड़ था। पीएम सूर्य घर योजना को 22,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पीएम सूर्य घर योजना में राशि की वद्धि से सरकार नए वित्तीय वर्ष में 40 लाख घरों को कवर करना चाहती है। यानी, आम आदमी के लिए सोलर पैनल लगाना आसान होगा। इस पर सरकार की ओर से मिलने वाली 40% सब्सिडी जारी रहेगी। इससे पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। यह स्कीम से सरकार को बिजली की लागत में हर साल करीब 75000 करोड़ रुपए की बड़ी वित्तीय बचत होगी।

न्यूक्लियर पावर: कस्टम्स इ्यूटी छूट 2035 तक बढ़ी

- सरकार ने न्यूक्लीयर एनर्जी सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट दिया है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इम्पोर्ट होने वाले सामानों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी छूट 2035 तक बढ़ा दी है।
- पहले यह छूट बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर थी। इससे स्टील, कंट्रोल रॉड्स, रिएक्टर पार्ट्स, टर्बाइन कंपोनेंट्स 5-10% तक सस्ते होंगे।

क्लीन एनर्जी: 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य

- भारत 2047 तक क्लीन और सस्ती ऊर्जा के लिए बड़ी योजनाएं चला रहा है। अभी भारत में कुल बिजली क्षमता में न्यूक्लियर का हिस्सा 3% (7-8 गीगावाट) है।
- 2030 तक 22 गीगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य है। इससे क्लीन एनर्जी, सोलर, ग्रिड इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा।

रोजगार: प्लांट्स के लिए होगी युवाओं की जरूरत

- ऊर्जा स्टोरेज, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा और घरेलू सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। इसका फायदा बड़ी औद्योगिक कंपनियों को भी।
- यह देश के औद्योगिक विकास, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट देगा। देश-विदेश से निजी निवेश बढ़ेगा।
- वर्ष 2025 में देश में 1,08,494 गीगावाट सोलर ऊर्जा पैदा की गई।

शहरी विकास

85,522 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है शहरी विकास के लिए

निजी निवेश से बदलेगी शहरों की तकदीर

16% अलाउंस मिलता है हाउस रेंट का कर्मियों को। ऐसे टियर-2 शहरों में भोपाल, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सूरत, लखनऊ, नागपुर, पटना, रायपुर जैसे 97 शहर।

8% अलाउंस मिलता है कर्मियों को। ऐसे टियर-3 शहरों में उज्जैन, अजमेर, अलवर, झांसी, रुड़की, रोहतक, मथुरा समेत अन्य शहर हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में चार बार टियर-2 और टियर-3 शहरों का जिक्र किया। इससे साफ है कि देश के विकास की परिभाषा अब बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहेगी। टियर-2, टियर-3 शहर विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। सरकार का मानना है कि इन शहरों में बढ़ती आबादी, स्थानीय संसाधन और उभरते उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। इन शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। लेंडर्स को आंशिक क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। सीपीएसई की रियल एस्टेट एसेट्स का रिसाइक्लिंग के अलावा राज्यों को 2 लाख करोड़ का समर्थन दिया जाएगा। इससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लॉजिस्टिक्स और निवेश बढ़ेगा। छोटे दुकानदार, होटल, गाइड और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

बढ़ेंगी सुविधाएं: लोगों को सीधा फायदा

- मंदिरों और धार्मिक महत्त्व वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सरकार बढ़ावा देगी। ऐसे शहरों में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु-पर्यटक पहुंचते हैं। सुविधाएं नहीं होने से परेशानी होती है।
- इन शहरों में बेहतर सड़कें, साफ-सफाई, ठहरने की व्यवस्था, परिवहन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यटन बढ़ेगा। रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

आस्था से अर्थ: शहर बनेंगे मजबूत हब

- मध्यप्रदेश के उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर, उत्तरप्रदेश के वाराणसी जैसे धामिक महत्त्व के शहरों में पहले की अपेक्षा श्रद्धालु बढ़े हैं। यह आर्थिक गतिविधियों के मजबूत हब बनेंगे।
- युवाओं को वहीं काम के मौके मिलेंगे। पलायन कम होगा। आशा है कि आने वाले वर्षों में यही शहर रोजगार, निवेश, विकास के नए केंद्र बनेंगे।

देश में नेशनल हाईवे की लंबाई

97 हजार 830 किलोमीटर थी नेशनल हाईवे की लंबाई वर्ष 2013-14 में। तब से 60% से ज्यादा वृद्धि।

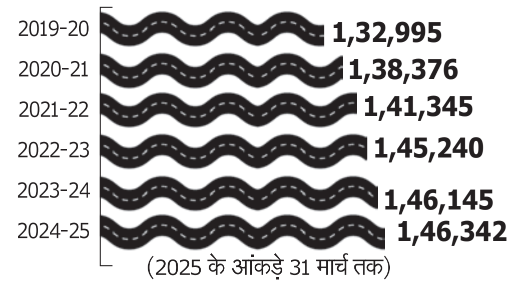

2019-20	1,32,995
2020-21	1,38,376
2021-22	1,41,345
2022-23	1,45,240
2023-24	1,46,145
2024-25	1,46,342

(2025 के आंकड़े 31 मार्च तक)

पानी

99,503 करोड़ का प्रावधान जल शक्ति मंत्रालय को... सिंचाई, नदियों का भी ध्यान

2028 तक हर घर को स्वच्छ जल, इस साल से काम होगा तेज

बजट में ग्रामीण पेयजल, सिंचाई, जल संरक्षण, नदियों की सफाई और सस्टेनेबल मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा गया है। जलशक्ति मंत्रालय को करीब 99,503 करोड़ का बजट दिया है। पेयजल, स्वच्छता पर 74,894 करोड़ की व्यवस्था दी है। मुख्य हिस्सा जल जीवन मिशन 67,670 करोड़ है। पिछली बार 67000 करोड़ रखे थे, पर 17000 करोड़ खर्च नहीं हुए। ऐसे में 2026-27 के लिए 67670 करोड़ रखे गए।

पूर्ण कवरेज: पानी की गुणवत्ता पर रहेगा खास ध्यान

- गांवों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का फ्लैगशिप प्रोग्राम में 2028 तक 100% कवरेज का लक्ष्य है। 2025-26 में कटौती के बाद अब मजबूत फोकस।
- नियमित सप्लाई, पानी की गुणवत्ता पर जोर। आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान।

स्वच्छता: गांवों में स्वच्छता के लिए 7192 करोड़ रुपए

- पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ आवंटित। पिछली बार 8,260 करोड़ थे। हालांकि रिवाइज्ड एस्टिमेट में खर्च 6,372 करोड़ बताया गया।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 7,192 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना: पिछले बजट से कुछ ही ज्यादा

- देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना (केन-बेतवा) के लिए 1906 करोड़ रखे गए हैं। बीते साल 2400 करोड़ थे। हालांकि संशोधित बजट में 1808.29 करोड़ रुपए किए गए।
- नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 2400 करोड़ का प्रावधान। इससे गंगा और सहायक नदियों की सफाई और संरक्षण पर जोर रहेगा।

सड़क से आसमान तक लगेंगे विकास को पंख...

120 नए शहर जोड़े जाएंगे उड़ान योजना के तहत

बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने उड़ान योजना को पंख दिए हैं। उन्होंने 120 नए शहरों को शामिल करने की घोषणा की। कहा कि अगले 10 साल में देश का हवाई नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। इसके लिए इंफ्रा को मजबूत बनाया जाएगा। नए हाईवे भी आकार लेंगे। 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये मुंबई-पुणे, हैदराबाद, बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी-सिलीगुड़ी रूट पर बनेंगे। ईको-फ्रेंडली सुविधाएं होंगी।

गलियारे: माल ढुलाई में होगी आसानी

- पूर्व में डाकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाले नए माल ढुलाई गलियारे की स्थापना करना।
- जहां खनिज की प्रचुर उपलब्धता, वहां औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे।

हिस्सेदारी: शेयरों का हिस्सा 12 प्रतिशत

- अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए काम करने वाले जहाज मरम्मत की व्यवस्था का सिस्टम बनेगा।
- अंतर्देशीय जलमार्गों और तटवर्ती शिपिंग के शेयरों की हिस्सेदारी 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% करने के लिए तटवर्तीय कार्गो संवर्धन स्कीम।

शिव रिपेयरिंग सेंटर: वाटर ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा

- स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने समुद्री जहाज वीजीएफ स्कीम लॉन्च होगी।
- पूर्वोदय एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास।
- शिप रिपेयरिंग सेंटर से वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत होगा। हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने और एआइ को स्किल से जोड़कर युवाओं को प्रशिक्षित करने की पहल।

विश्लेषण

रेल कॉरिडोर के लिए संभावनाएं तलाशें राज्य

वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करना होगा

प्रशांत सल्वान
एक्सपर्ट,
इंफ्रास्ट्रक्चर

Q बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए मिलेगी पर्याप्त राशि

वित्त मंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों के साथ-साथ मंदिर नगरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। राज्यों को इस योजना के तहत विभिन्न जिलों के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त होगी।

Q राज्य सरकारों को खुद शामिल करने पहल करनी होगी

सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है, ताकि इस क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन का निर्माण किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों को कॉरिडोर में खुद को शामिल करने संभावनाएं तलाशनी होंगी।

Q जरूरी रणनीतियां बनाकर उठाया जा सकेगा लाभ

'चैंपियन एसएमई' के तहत भविष्य के चैंपियनों को विकसित करने 10,000 करोड़ का एसएमई विकास कोष बनाया गया है। चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही, 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि सूक्ष्म उद्यमों को निरंतर समर्थन दिया जा सके और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाई रखी जा सके। राज्य सरकारों को इस कोष से अधिकतम आवंटन आकर्षित करने के लिए एमएसएमई रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता है। वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए, भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग कर वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर छूट दी गई है।

बजट toons

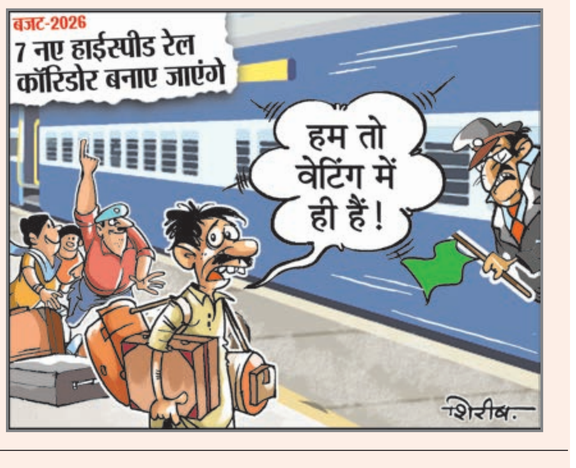

बजट-2026
7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे
हम तो वेटिंग में ही हैं!
शिरीष

आम बजट को विस्तार से पढ़ने और इसके सभी आयामों को समझने के लिए www.patrika.com पर जाएं।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

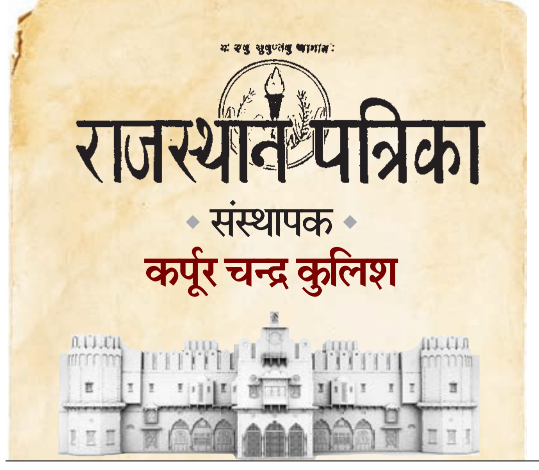

तेज हो बजट लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार

केंद्रीय बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के जिन तीन कर्तव्यों की चर्चा की उसमें वैश्विक परिस्थितियों का सामना करते हुए आर्थिक विकास को तेज व सतत बनाए रखने, जनआकांक्षाओं को पूरा करने व संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक सबकी पहुंच की बात कही। इन्हीं कर्तव्यों को ध्यान में रखकर उन्होंने बजट पेश करने का दावा भी किया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का उद्देश्य रखते हुए ही बजट में विकास, रोजगार, आत्मनिर्भरता, गरीबी कम करना और वैश्विक चुनौतियों से निपटने जैसे बिंदुओं पर जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने यह बजट ऐसे दौर में पेश किया है जब टैरिफ के दबाव के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर दूसरे कारणों से व्यापारिक उथल-पुथल का सिलसिला जारी है। ऐसे माहौल में वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करना बड़ी चुनौती है। इसीलिए विदेशी निवेश को भारत की बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ने के लिए वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने की योजना बनाने की बात कही है। भारतीय इकॉनोमी की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले एमएसएमइ सेक्टर के लिए 'एमएसएमइ विकास निधि' का प्रावधान भी औद्योगिक प्रोत्साहन की दिशा में ठोस कदम कहा जा सकता है। इससे एमएसएमइ सेक्टर और मजबूत होगा। बायोफॉर्मा शक्ति को महसूस करते हुए बजट में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इको-सिस्टम का निर्माण करने की बात कही गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ माइनिंग में निवेश बढ़ाने की घोषणा को भारत को वैश्विक टेक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम ही कहा जाएगा। उच्च-मूल्य कृषि पर बजट का विशेष जोर है। साथ ही ग्रामीण और उप-शहरी रोजगार बढ़ाने के लिए पशुपालन में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा व्यय बढ़ाकर सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि सुरक्षा के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शुगर व कैंसर की दवा सस्ती करने को भी आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला कहा जाएगा। लेकिन चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ करने की आवश्यकता थी। बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। क्योंकि आम आदमी की जेब में रकम तब ही पहुंच पाती है जब रोजगार के अवसर भी बढ़ें। सही मायने में दीर्घकालीन उद्देश्यों को लेकर उठाए गए तमाम कदम भविष्य के विकास की राह भी खोलने वाले होते हैं।

मोटे तौर पर बजट में सरकार ने रिफॉर्म पर जोर दिया है लेकिन जिस 'रिफॉर्म्स एक्सप्रेस' का दावा किया जा रहा है वह भी कोई जादुई चिराग नहीं हो सकता। रिफॉर्म्स वस्तुतः एक सतत प्रकिया है। सही मायने में विकास की रफ्तार को टॉप गियर में डालने के सरकार के प्रयास तब ही सफल होंगे जबकि बजट में तय किए गए लक्ष्यों को पाने की रफ्तार भी तेज हो।

विश्लेषण : राजकोषीय अनुशासन बना रहे और विकास की दीर्घकालीन क्षमता को धीरे-धीरे मजबूत करने पर जोर

बजट 2026 : सावधानी व व्यावहारिकता का भाव

खर्च की दिशा में बजट ने पूंजीगत निवेश पर जोर कायम रखा है। बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है, जो विकास के लिहाज से जरूरी है, बशर्ते यह उच्च गुणवत्ता का हो और निजी निवेश को पीछे न धकेले। सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई पर फोकस भी खास महत्व रखता है।

आज भारत की अर्थव्यवस्था की बाहरी तस्वीर आश्वस्ति प्रदान करने वाली दिखाई देती है। तिमाही आधार पर विकास दर मजबूत बनी हुई है, महंगाई काबू में है, बैंकों के मुनाफे बेहतर हुए हैं और एनपीए में भी कमी आई है। लंबे समय तक कर्ज घटाने के बाद कंपनियों की माली हालत में भी सुधार है। लेकिन यही सतही शांति दरअसल सतर्क रहने का संकेत देती है। इसी कारण केंद्रीय बजट को किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक कड़ी परीक्षा के रूप में देखना जरूरी है। क्योंकि यह 'सब कुछ ठीक-ठाक' वाली स्थिति पूरी तरह स्थायी नहीं है।

दरअसल यह 'गोल्डीलॉक्स' चमक शर्तों पर टिकी है। विकास की रफ्तार का बड़ा सहारा केंद्र सरकार का भारी पूंजीगत खर्च रहा है। यह इंजन हमेशा के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि इससे कर्ज पर दबाव बढ़ता है। दूसरी ओर, कम महंगाई का एक कारण खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट भी है, जो लंबे समय तक बनी रहे, यह जरूरी नहीं। बजट-पूर्व संकेत भी चेताते हैं कि वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल से दिसंबर के बीच देश के आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन साल भर पहले की तुलना में सिर्फ 2.6 प्रतिशत ही बढ़ पाया, जो अर्थव्यवस्था की अंदरूनी कमजोरी की ओर इशारा करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवां बजट इस मूल भाव के साथ पेश किया– सावधानी के साथ व्यावहारिक फैसले। यानी सरकारी खर्च और घाटे को तय रास्ते पर बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने व विकास क्षमता बढ़ाने की दिशा में हल्का-सा धक्का देने की कोशिश।

सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालें। सरकार ने कुल खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव किया है, जो पिछले संशोधित अनुमान से करीब 7.7 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं उधारी को छोड़कर सरकार की आमदनी 36.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने के वादे के अनुरूप है। यह संयम इसलिए जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में हालात अचानक बदल सकते हैं। विदेश से पैसा जुटाना कभी भी महंगा हो सकता है और किसी देश की साख पर जरा-सी आंच भी विदेशी पूंजी की लागत बढ़ा देती है। लेकिन सरकार के लिए पैसा जुटाने का माहौल सहज नहीं है। इस साल केंद्र सरकार ने करीब 17.2 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बनाई है और राज्यों की उधारी अलग से 12.6 लाख करोड़ है– दोनों मिलकर बॉन्ड बाजार पर भारी दबाव डालते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें नरम किए जाने के बावजूद लंबे समय के सरकारी बॉन्डों पर ब्याज करीब 7 प्रतिशत पर अटका हुआ है। यह स्थिति निजी कंपनियों को नया निवेश करने से हतोत्साहित करती है। सरकारी राजस्व की बढ़त भी कमजोर है। अप्रैल-नवंबर में केंद्र सरकार का कर संग्रह सिर्फ 3.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पूरे साल के लिए 10.8 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान था। अगर इस साल अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि 8 प्रतिशत के आसपास ही रहती है या लोगों का खर्च कमजोर बना रहता है, तो राजकोषीय गणित संभालना कठिन होगा। तब विकास को सहारा दे रहे उसी पूंजीगत खर्च में कटौती का दबाव बन सकता है।

अजीत रानाडे
वरिष्ठ अर्थशास्त्री
(द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

एक चिंता घरेलू वित्तीय बचत की घटती हिस्सेदारी है। पेंशन, बीमा और दीर्घकालीन घरेलू पूंजी को मजबूत करना जरूरी है, ताकि विकास के लिए स्थायी संसाधन उपलब्ध हों।

इसी बीच प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) में किया गया हल्का बदलाव भी इसी वजह से था– सरकार को कुछ अतिरिक्त राजस्व मिले और शेयर बाजार के डेरिवेटिव कारोबार में जरूरत से ज्यादा सट्टेबाजी पर लगाम लगे। हालांकि इससे बाजारों में उथल-पुथल हुई, जिससे उबरने की उम्मीद है। खर्च के मोर्चे पर देखें तो बजट में पूंजीगत खर्च पर जोर बरकरार रखा गया है। बुनियादी ढांचे पर होने वाला सरकारी निवेश करीब 9 प्रतिशत बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है– बशर्ते यह उच्च-गुणवत्ता का हो और निजी निवेश को हाशिये पर न धकेले।

इसके साथ ही बजट ने सेवाओं के क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि कंटेंट निर्माण, डिजाइन, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा मेडिकल टूरिज्म को भी इसमें शामिल किया गया है। सेवाओं के इन क्षेत्रों में भारत को पहले से तुलनात्मक बढ़त हासिल है, पर बड़ी बढ़त के लिए कौशल-उत्पादकता में छलांग जरूरी होगी। यानी असली चुनौती है– बेहतर प्रशिक्षण और ज्यादा उत्पादक कामकाज। इसी सोच के तहत शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता तक की पूरी कड़ी जोड़ने, औद्योगिक क्लस्टरों को प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ने और पुराने क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। मसलन, वस्त्र और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों को उसी क्षेत्र के औद्योगिक क्लस्टरों से जोड़ा जाएगा। साथ ही देश भर में फैले 200 से अधिक पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को फिर से सक्रिय करने की योजना है। इससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सप्लायर नेटवर्क, परिवहन व्यवस्था, गुणवत्ता मानक और कुशल श्रमिक–सभी एक साथ मजबूत होंगे।

छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) पर बजट का ध्यान खास तौर पर सराहनीय है। समय पर भुगतान न मिलना और काम चलाने के लिए पूंजी की कमी छोटे कारोबारों को अंदर ही अंदर खत्म कर देने वाली समस्याएं हैं। टीआरईडीएस के जरिए बिल डिस्काउंटिंग को मजबूत करने जैसे कदम भले ही बहुत आकर्षक न लगें, लेकिन ऐसे ही सुधार छोटे उद्यमों को टिकाए रखते हैं और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाते हैं। फिर भी निजी निवेश वह कड़ी है, जो अब तक कमजोर बनी हुई है। यहीं बजट जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे एक सरल, लेकिन प्रभावी सुधार से चूक गया। पूंजीगत सामान पर टैक्स क्रेडिट का वर्षों तक फंसा रहना नई फैक्ट्रियां लगाने और क्षमता बढ़ाने के फैसलों को टाल देता है। यह सुधार निवेश की लागत घटा सकता था और निजी क्षेत्र को ठोस प्रोत्साहन दे सकता था। बजट का एक कमजोर पक्ष यह भी है कि इसमें वितरण के सवालों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। ऊंची विकास दर और आर्थिक स्थिरता के साथ असमानता बढ़ सकती है, खासकर तब जब रोजगार सृजन धीमा हो। कृषि का हिस्सा घटने के बावजूद बड़ी आबादी का उसी पर निर्भर रहना इसी असंतुलन को दिखाता है। यदि इन मुद्दों को सीधे और साफ ढंग से नहीं साधा गया, तो आर्थिक आंकड़ों और नीतिगत दावों पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। एक और चिंता घरेलू वित्तीय बचत की घटती हिस्सेदारी है। पेंशन, बीमा और दीर्घकालीन घरेलू पूंजी को मजबूत करना जरूरी है, ताकि विकास के लिए स्थायी संसाधन उपलब्ध हों। इस दिशा में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए उच्चस्तरीय समिति का प्रस्ताव सकारात्मक संकेत देता है। कुल मिलाकर यह बजट आत्ममुग्धता से परे संतुलित और समझदारी भरा कहा जा सकता है। इसमें राजकोषीय सतर्कता, पूंजीगत खर्च और कौशल निर्माण पर ध्यान दिया गया है। लेकिन यदि भारत की विकास यात्रा को सरकार-केंद्रित मॉडल से निकालकर निजी निवेश आधारित बनाना है, तो आगे का रास्ता बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि ऐसे शांत और ठोस सुधारों से निकलेगा, जो निवेश के रास्ते खोलें, रोजगार की गुणवत्ता सुधारें और विकास के लाभ समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाएं। क्षमता निर्माण की इस सोच का मतलब यह भी होना चाहिए कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और शोध जैसे क्षेत्रों पर अपना खर्च ठोस रूप से बढ़ाए।

शिक्षा बजट में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी

भविष्य की तैयारी या फिर पुरानी समस्याओं से किनारा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.39 लाख करोड़ का आवंटन करना एक स्वागत योग्य कदम है, जो पिछले वर्ष के 1.28 लाख करोड़ के मुकाबले लगभग 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह आंकड़ा पहली नजर में शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन यदि हम इसकी गहराई में उतरें, तो यह बजट 'भविष्य की उड़ान' और 'भूतकाल के बोझ' के बीच एक संघर्ष जैसा प्रतीत होता है। बजट 2026 की सबसे बड़ी विशेषता इसका उद्योग-केंद्रित दृष्टिकोण है। इस बजट के अनुसार औद्योगिक गलियारों के पास 5 एकीकृत 'यूनिवर्सिटी टाउनशिप' विकसित की जाएंगी। इनका उद्देश्य अनुसंधान और शिक्षा को सीधे उद्योगों से जोड़ना है। छात्राओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। आइआइटी में भविष्य की तकनीक के लिए विशेष लैब बनाई जाएंगी। पूर्वी भारत में एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया जाएगा। एआइ और स्किलिंग 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में ऑडियो-विजुअल, गेमिंग एवं कॉमिक्स (एवीजीसी) कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी।

'भारतीय भाषा पुस्तक योजना' के तहत भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकों का विस्तार किया जाएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए टीसीएस की दरों में कटौती की गई है, जिससे विदेश में शिक्षा लेना थोड़ा सस्ता हो सकता है। तीन नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे। डिजिटल माध्यम से स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भाषा की बाधा को तोड़कर ज्ञान को सुलभ बनाएगी। लेकिन हमें उन चुनौतियों पर ध्यान देना होगा जिन्हें अक्सर चमकदार घोषणाओं के नीचे दबा दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट कहा गया था कि भारत को अपनी शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। वर्तमान में, यह आवंटन लगभग 2.8 से 3 प्रतिशत के बीच झूल रहा है। सबसे गंभीर समस्या शिक्षकों की भारी कमी है। डिजिटल उपकरण केवल 'साधन' हैं, 'साध्य' नहीं। आज भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में 30 से 50 प्रतिशत तक शैक्षणिक पद रिक्त पड़े हैं। बजट में इन पदों को भरने के लिए किसी भी 'विशेष भर्ती अभियान' समर्पित फंड का अभाव खलता है। जब शिक्षक ही नहीं होंगे, तो प्रयोगशालाएं और डिजिटल बोर्ड धूल ही फांकेंगे।

राज्य विश्वविद्यालयों की उपेक्षा: बजट का बड़ा हिस्सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिमट जाता है। भारत के 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो आज भी फंड और उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। शोध के लिए मिलने वाला अधिकांश फंड भी प्रीमियम संस्थानों तक ही सीमित रहता है, जिससे छोटे विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की संस्कृति दम तोड़ रही है। जब तक हम अपने राज्य विश्वविद्यालयों को आधुनिक नहीं बनाएंगे, तब तक हम एक 'असमान समाज' का निर्माण करते रहेंगे। नए युग की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की बातें तो हैं, लेकिन पुराने लैब को आधुनिक बनाने या ग्राउंड लेवल पर शिक्षकों को 'हैंड्स-ऑन' ट्रेनिंग देने के लिए बजट अपर्याप्त लगता है। बजट 2026 तकनीक और आधुनिकता पर तो जोर देता है, लेकिन यह उस 'जवाबदेही' और 'गुणवत्ता' के सवाल पर मौन है जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रही है। एआइ और आधुनिक लैब निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे एक जीवंत शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकते। हमें यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार और गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता का समाधान केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए हमें शिक्षकों की भर्ती, उनके निरंतर प्रशिक्षण और संस्थानों की स्वायत्तता पर निवेश करना होगा। यदि आधारभूत ढांचा (शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं) कमजोर है, तो उस पर खड़ी की गई डिजिटल इमारत कभी भी ढह सकती है। यह बजट भविष्य की ओर एक साहसी कदम तो है, लेकिन यह अपनी पुरानी और बुनियादी समस्याओं से किनारा करता हुआ भी दिखता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार केवल नए संस्थान खोलने पर ही नहीं, बल्कि मौजूदा संस्थानों की आत्मा (शिक्षकों और शोध की गुणवत्ता) को पुनर्जीवित करने पर भी ध्यान दे।

प्रो. अशोक कुमार
शिक्षाविद एवं पूर्व कुलपति
@patrika.com

छात्राओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि हमें उन चुनौतियों पर ध्यान देना होगा जिन्हें अक्सर चमकदार घोषणाओं के नीचे दबा दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट कहा गया था कि भारत को अपनी शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। वर्तमान में यह आवंटन लगभग 2.8 से 3 प्रतिशत के बीच झूल रहा है। सबसे गंभीर समस्या शिक्षकों की भारी कमी है।

विस्तार, स्थिरता और रणनीति का बजट

भारत की विकास यात्रा के लिए संगठित-विश्वसनीय रोडमैप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 को सरकार की मध्यम अवधि की आर्थिक रणनीति के एक सुविचारित समेकन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में जहां व्यापार तनाव लगातार बने हुए हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि धीमी पड़ रही है और आपूर्ति शृंखलाओं को लेकर नई चिंताएं उभर रही हैं, यह बजट घरेलू क्षमता निर्माण पर भरोसा जताता है। इसका संदेश स्पष्ट है- सार्वजनिक निवेश का विस्तार, निजी पूंजी को आकर्षित करना, तकनीकी क्षमता को गहरा करना और सुधार व विनियमन-मुक्ति की लंबी, अपेक्षाकृत अल्प-प्रचारित प्रक्रिया को आगे बढ़ाना।

बजट में अवसंरचना के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता जारी है। 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो चालू वर्ष के लगभग 11.2 लाख करोड़ से करीब 9 प्रतिशत अधिक है। यह पिछले कई वर्षों की उस प्रवृत्ति का विस्तार है, जिसमें केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2015 के 2 लाख करोड़ रुपए से तेजी से बढ़ा है। यह सार्वजनिक व्यय की संरचना में उपभोग से निवेश की ओर एक निर्णायक बदलाव को रेखांकित करता है। इस व्यय के भीतर परिवहन अवसंरचना को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जो मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलूरु, चेन्नई-बेंगलूरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेंगे। इन परियोजनाओं को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से और मिश्रित वित्तपोषण मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यात्री परिवहन के साथ-साथ बजट लॉजिस्टिक्स दक्षता पर भी जोर देता है। उन्नत फ्रेट कॉरिडोर, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विस्तार और लगभग 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन, भारत की अब भी ऊंची अंतरराष्ट्रीय तुलना वाली लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित हैं। इसके पूरक के रूप में, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए पांच वर्षों में 5000 करोड़ रुपए का समर्पित वित्तीय समर्थन प्रस्तावित है, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी अवसंरचना, औद्योगिक क्लस्टर और सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके। यदि अवसंरचना बजट की भौतिक रीढ़ है, तो तकनीक और नवाचार उसकी रणनीतिक धार हैं। 40,000 करोड़ रुपए के विस्तारित परिव्यय के साथ 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की घोषणा भारत को वैश्विक मूल्य शृंखला में ऊपर ले जाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। सेमीकंडक्टर अब केवल औद्योगिक इनपुट नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता से जुड़ी रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड प्रस्तावित किया गया है, जो व्यापक सब्सिडी के बजाय लक्षित विकास पूंजी उपलब्ध कराएगा, ताकि सक्षम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विस्तार कर सकें और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जुड़ सकें।

समष्टि आर्थिक दृष्टि से बजट संतुलन साधने का प्रयास करता है। जीडीपी के 4.3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य, पूंजीगत व्यय बढ़ाते हुए भी समेकन की दिशा में एक सार्थक कदम है। सकल बाजार उधारी लगभग 17.2 ट्रिलियन और शुद्ध उधारी 11.7 ट्रिलियन अनुमानित है, जिसे ऋण बाजार की स्थिरता को ध्यान में रखकर समायोजित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच अनुमानित की गई है, जो इस विश्वास को दर्शाती है कि घरेलू निवेश और सुधार गति बाहरी चुनौतियों का सामना कर सकती है।

समग्र रूप से, बजट 2026 एक स्पष्ट मंशा का दस्तावेज है। यह बड़े लोकलुभावन कदमों से परहेज करते हुए अवसंरचना, तकनीक और क्रमिक सुधारों पर आधारित विकास मॉडल को मजबूत करता है। इसकी अहमियत किसी एक घोषणा में नहीं, बल्कि दिशा की निरंतरता में निहित है। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सरकार ने घरेलू क्षमताओं के निर्माण, नियामकीय बाधाओं को कम करने और सार्वजनिक निवेश को निजी पहल के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करने का मार्ग चुना है। प्राथमिकताओं के एक स्पष्ट संकेत के रूप में यह बजट भारत की अगली विकास यात्रा के लिए एक संगठित और विश्वसनीय रोडमैप प्रस्तुत करता है।

प्रो. गौरव वल्लभ
अंशकालिक सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
@patrika.com

समग्र रूप से यह बजट एक स्पष्ट मंशा का दस्तावेज है। यह बड़े लोकलुभावन कदमों से परहेज करते हुए अवसंरचना, तकनीक और क्रमिक सुधारों पर आधारित विकास मॉडल को मजबूत करता है। इसकी अहमियत किसी एक घोषणा में नहीं, बल्कि दिशा की निरंतरता में निहित है। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में घरेलू क्षमताओं के निर्माण, नियामकीय बाधाओं को कम करने और सार्वजनिक निवेश को निजी पहल के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करने का मार्ग चुना है।

बज toons

आम बजट को विस्तार से पढ़ने और इसके सभी आयामों को समझने के लिए www.patrika.com पर जाएं।

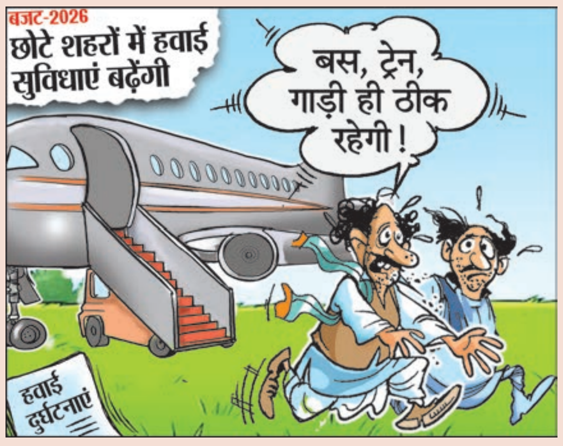
बजट-2026
छोटे शहरों में हवाई सुविधाएं बढ़ेंगी
बस, ट्रेन, गाड़ी ही ठीक रहेगी!
हवाई दुर्घटनाएं

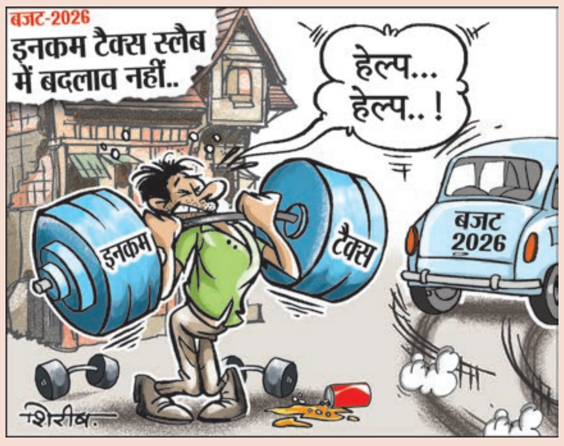

Don't Mind @Memes

सभी तरह के इंवेस्टर्स- बजट के बाद
सिल्वर इंवेस्टर्स
गोल्ड इंवेस्टर्स
इंट्राडे ट्रेडर्स
लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स

मिडिल क्लास- बजट के दौरान

नहीं, हमारा नाम नहीं है...

सशक्त करने वाला बजट

'विकसित भारत' लक्ष्य को सशक्त करने वाला यह बजट फ्यूचर-रेडी भारत की मजबूत नींव है। समावेशी विकास, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, युवा अवसर, एमएसएमई को गति देकर बजट हर वर्ग की समृद्धि सुनिश्चित करेगा।

***धर्मेन्द्र प्रधान,** केन्द्रीय शिक्षा मंत्री*

बजट 2026-27

सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर

गरीब कल्याण में कटौती का बजट

बजट न तो किसी स्पष्ट राजनीतिक दिशा को दिखाता है और न ही इसमें ठोस नीतियां नजर आती हैं। आम लोगों के लिए असरदार योजना दिखाई नहीं देती। इसका नाम बदलकर गरीब कल्याण में कटौती बजट रख दें।

***रणदीप सिंह सुरजेवाला,** सांसद, कांग्रेस*

शिक्षा-स्किल डवलपमेंट को एक साझा रणनीति से जोड़ा, दुर्लभ बीमारियों का इलाज सस्ता

युवाओं को कौशल, शिक्षा को दिशा, सेहत को डोज

मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि विकसित भारत की राह युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार से होकर ही निकलेगी। बजट का फोकस केवल नई योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर है। शिक्षा और स्किल डवलपमेंट को एक साझा रणनीति से जोड़ा गया है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप, स्किल सेंटर और रिसर्च हब का प्रस्ताव शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने की ठोस कोशिश है। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र को बजट में बड़ी डोज दी गई है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को सस्ता करना, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा मेडिकल टूरिज्म पर फोकस किया गया है। समाज कल्याण में दिव्यांगजनों को कौशल और सम्मानजनक रोजगार से जोड़ना और 'खेलो इंडिया मिशन' को मिशन मोड में आगे बढ़ाकर खेलों को कॅरियर के रूप में स्थापित करने की दिशा तय की गई है।

स्वास्थ्य-चिकित्सा

हाई-क्वालिटी आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के निर्यात पर सरकार का खास जोर

इलाज से लेकर आयुष तक व्यापक सुधार

- **एक साल में 1.5 लाख केयरगिवर प्रशिक्षित करेंगे**
- **17 कैंसर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती**

इस बार स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र को बजट में खास प्राथमिकता दी गई है। कैंसर, डायबिटीज और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर फोकस किया गया है। आयुष और पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। आयुर्वेद, योग और वेलनेस को बढ़ावा देने से शोधकर्ताओं और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। मेडिकल टूरिज्म, शोध और मानव संसाधन विकास के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने पर फोकस किया गया है।

तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे

- तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों से आयुर्वेद शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को नई दिशा मिलेगी। यहां आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान को जोड़ा जाएगा। देश को कुशल वैद्य, शोधकर्ता और हेल्थ प्रोफेशनल्स मिलेंगे।
- चिकित्सा पर्यटन के लिए राज्य सरकार व निजी क्षेत्र की साझेदारी से 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब विकसित किए जाएंगे। इनमें अस्पताल, मेडिकल शिक्षा, रिसर्च, आयुष केंद्र व पुनर्वास सुविधाएं होंगी। इससे चिकित्सकों, नर्स व एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (एएचपी) के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे।
- हाई-क्वालिटी वाले आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के निर्यात पर सरकार का खास जोर है। जब आयुर्वेदिक दवाएं, तेल और हर्बल प्रोडक्ट्स अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचते हैं, तो इसका सीधा लाभ औषधीय जड़ी-बूटियां उगाने वाले किसानों को मिलेगा। ऑर्गेनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

चिकित्सा शिक्षा: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान

- अगले पांच वर्षों में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य प्रोफेशनल (एएचपी) जोड़ेंगे। इनमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, मनोविज्ञान जैसे 10 विषय शामिल होंगे।
- बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल के लिए मजबूत केयर सिस्टम तैयार होगा। देखभाल करने वालों को योग, वेलनेस और मेडिकल उपकरण चलाने जैसे कई कौशल सिखाए जाएंगे। एक साल में 1.5 लाख सार-संभाल करने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- जिला अस्पतालों में आपात और ट्रोमा केयर सुविधाएं 50 प्रतिशत तक बढ़ेंगी। रांची और तेजपुर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को और मजबूत किया जाएगा।
- मानसिक स्वास्थ्य और आपात देखभाल के लिए उत्तर भारत में एक नया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाएगा।

निवेश-शोध: बायोफार्मा में शोध के लिए 10 हजार करोड़

- कैंसर और डायबिटीज के मरीजों की 17 कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं से आयात शुल्क हटाया गया।
- बायोफार्मा सेक्टर में नई दवाओं के शोध और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में 10 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- जामनगर स्थित डब्लूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपग्रेड किया जाएगा।
- मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें आयुष केंद्र भी शामिल होंगे।

युवा - खेल

10 साल का मैकेनिज्म किया गया तैयार

'खेलो इंडिया मिशन' से कॅरियर

युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। 'खेलो इंडिया मिशन' के जरिए अगले एक दशक में खेल व्यवस्था को मजबूत, व्यवस्थित और रोजगारोन्मुख बनाने का लक्ष्य रखा है। यह पहल खेल को केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता और कॅरियर के नए अवसर भी खोलेगी।

खेल व्यवस्था मजबूत होगी

- खेल क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोले जाएंगे। 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू कर अगले दस साल में खेल व्यवस्था को मजबूत करने का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा।
- मिशन के तहत खिलाड़ियों के लिए शुरुआत से लेकर उच्च स्तर तक प्रशिक्षण व्यवस्था होगी। इसकी नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी।

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा

- कोच और सपोर्ट स्टाफ का सहयोग मिलेगा, जिसका अलग से प्लेटफॉर्म होगा।
- खेल विज्ञान और तकनीक का उपयोग करने पर फोकस होगा।
- लीग, प्रतियोगिताएं और आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित की जाएगी।

युवाओं को रोजगार और कौशल, शिक्षा को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है।

निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्तमंत्री

- **स्वास्थ्य चिकित्सा पर खर्च 4.75% बढ़ाया गया**
- **एवीजीसी क्षेत्र में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा**
- **50% जिला अस्पतालों में ट्रोमा केयर केंद्र होंगे**
- **1000 इंडिया क्लीनिकल ट्रायल साइटों का नेटवर्क**

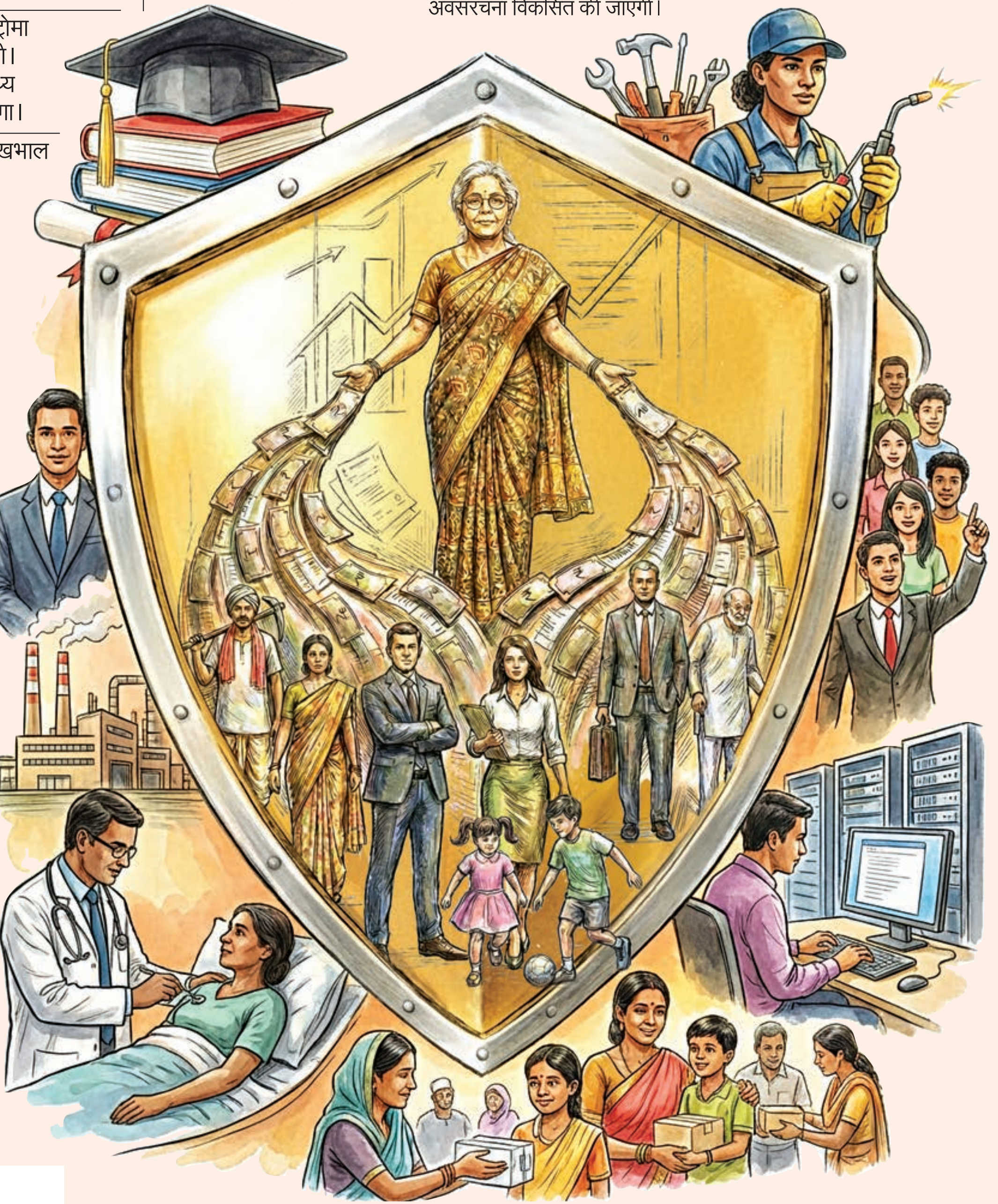

शिक्षा-स्किल डवलपमेंट-रोजगार

15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में बनेंगी एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब

तकनीक से जुड़ेगा कौशल, रोजगार बढ़ेंगे

शिक्षा, स्किल डवलपमेंट और रोजगार को एक साझा रणनीति में पिरोकर बजट में वर्ष 2047 के विकसित भारत की स्पष्ट रूपरेखा सामने रखी है। शिक्षा को डिग्री तक सीमित न रखकर सीधे रोजगार, उद्यमिता और वैश्विक जरूरतों से जोड़ा गया है। एआइ जैसी नई तकनीकों से कौशल और रोजगार की दिशा तय की गई है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप का प्रस्ताव शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने की कोशिश है।

यूनिवर्सिटी टाउनशिप

औद्योगिक क्षेत्रों के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप- औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी, ताकि ऐसे युवा तैयार करें जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। इनमें कॉलेज, विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, स्किल सेंटर और हॉस्टल होंगे।

रोडमैप तैयार करेगी उच्च-स्तरीय स्थायी समिति

- शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति का गठन होगा। यह समिति सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का मुख्य आधार बनाने पर काम करेगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों से रोजगार और कौशल की जरूरतों में क्या बदलाव आएगा और उसी अनुसार अनुशंसा करेगी।
- एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 बड़े टेलीस्कोप और प्लैनेटेरियम विकसित किए जाएंगे।
- 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी, जिससे रचनात्मक युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।

डिजाइन क्षेत्र को बढ़ावा, राष्ट्रीय संस्थान खुलेगा

- कुशल डिजाइनरों की कमी देख पूर्वी भारत में एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- स्थानीय युवाओं को डिजाइन शिक्षा और रोजगार दोनों मिलेंगे।
- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र तेजी से उभर रहा है।
- वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार की जरूरत होगी।

शिक्षा पर खर्च 8.27% बढ़ा

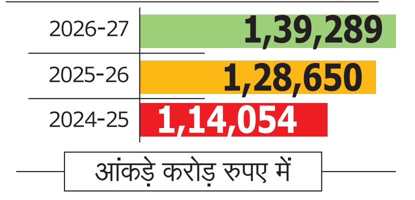

आंकड़े करोड़ रुपए में

आइटी

एआइ से बदलेगा कामकाज का स्वरूप

21वीं सदी पूरी तरह तकनीक पर आधारित है। इसके तहत तकनीक का लाभ खेत में काम करने वाले किसान, एसटीईएम क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं, नए कौशल सीखने वाले युवा और दिव्यांगजनों तक भी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एआइ मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान निधि और अनुसंधान-विकास-नवाचार कोष जैसे प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।

विशेष प्रशिक्षण से उन्नत होंगे कौशल, एआइ से मैपिंग

एआइ और उभरती तकनीकों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी प्रोफेशनल और इंजीनियरों के कौशल को उन्नत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। एआइ की मदद से यह मैपिंग की जाएगी कि किस क्षेत्र में किस तरह के कामगार, नौकरियां और प्रशिक्षण अवसर मौजूद हैं, ताकि युवाओं को सही समय पर सही कौशल मिल सके।

आइटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया गया है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने में काम आएगी तकनीक

बजट में किसान, महिलाएं, युवा और दिव्यांगजन जैसे वर्गों को तकनीकी बदलाव का साझेदार बनाने की मंशा दिख रही है। एआइ के जरिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को सुलभ बनाने और नए कौशल विकसित करने की संभावनाएं खुलेंगी। राष्ट्रीय अनुसंधान निधि और अनुसंधान-विकास-नवाचार कोष से विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप्स और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ेगा। डिजिटल डिवाइड, कौशल अंतर और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर समानांतर काम जरूरी होगा।

समाज कल्याण

दिव्यांगजनों को कौशल से सक्षम बनाने की योजना

सम्मानजनक और स्थायी रोजगार

समाज कल्याण को इस बार संवेदनशीलता और समावेशन के नए नजरिए से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों को सहायता के नहीं, बल्कि सशक्त नागरिक के रूप में केंद्र में रखा गया है। कौशल विकास, रोजगार और तकनीक के समन्वय के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। समाज कल्याण में इस बार दिव्यांगजनों पर विशेष फोकस किया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से लेकर उनके कौशल विकास से जुड़ने का दायरा बढ़ाया जाएगा। उद्देश्य है कि उन्हें सम्मानजनक और स्थायी रोजगार भी मिले।

दिव्यांग समूह को विशेष प्रशिक्षण

- सूचना प्रौद्योगिकी, एवीजीसी, होटल और फूड सेक्टर में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रोजगार अवसर तैयार किए जाएंगे।
- हर दिव्यांग समूह के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- समय पर अच्छे सहायक उपकरण मिलें, यह सुनिश्चित होगा।

पीएम दिव्याशा केंद्र मजबूत होंगे

- उत्पादन, रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के लिए सहयोग मिलेगा।
- असिस्टिव टेक्नोलोजी मार्ट बनाए जाएंगे। यहां उपकरण देखकर और उपयोग कर खरीदे जा सकेंगे।
- पीएम दिव्याशा केंद्रों को मजबूत किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क होगा तैयार

- सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जिससे गरीब और वंचित वर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही महिलाओं के लिए उद्यमिता अवसर बढ़ाने की पहल की गई है।

विशेषज्ञ की राय

डॉ. अरविंद अग्रवाल,
पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार

'युवा शक्ति' केंद्रित एक दूरदर्शी बजट

केंद्रीय बजट 2026-27 युवा शक्ति और मानव पूंजी विकास पर केंद्रित एक दूरदर्शी बजट है। यह बजट आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट मानव संसाधन में निवेश को प्राथमिकता देकर दीर्घकालिक आर्थिक विकास की नींव रखेगा।

आम युवा पर असर

स्थानीय नौकरी के रास्ते खुलेंगे

युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि सरकार अब अवसर देने के साथ-साथ उसकी क्षमता को भी गढ़ना चाहती है। शिक्षा और स्किल को एक ही रणनीति में पिरोकर बजट ने पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने की दिशा दिखाई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं का सस्ता होना सीधे परिवारों का आर्थिक बोझ घटाएगा। आयुर्वेद और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से नए रोजगार भी पैदा होंगे।

बजट toons

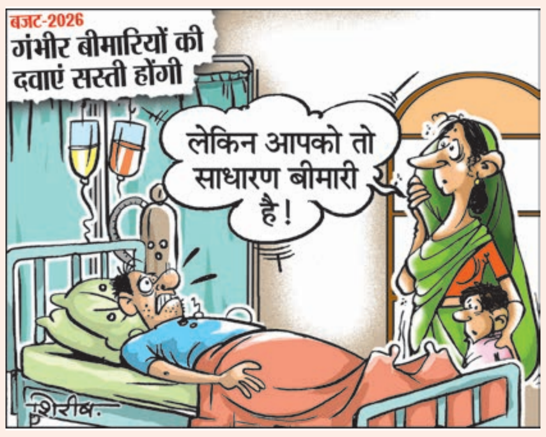
बजट-2026
गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी
लेकिन आपको तो साधारण बीमारी है!
शिरीष

विश्लेषण

युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने की कोशिश

शिक्षा, कौशल और तकनीक के जरिए भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव रखने की तरफ कदम

किसी भी देश के भविष्य की असली कसौटी उसकी युवा पीढ़ी की तैयारी होती है। भारत में लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इस मानव संसाधन को दक्ष, उपयोगी और सक्षम बनाना आर्थिक विकास का मूल आधार है। केंद्रीय बजट शिक्षा और कौशल को दीर्घकालिक आर्थिक निवेश के रूप में देखता है, जो देश की उत्पादकता और रोजगार क्षमता को सुदृढ़ कर सकता है।

इस वर्ष शिक्षा के लिए कुल 1,28,650 करोड़ का आवंटन किया गया है। विशेष यह है कि यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। बजट में इस बार केवल राशि बढ़ाने पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और रोजगार-योग्यता को आपस में जोड़ने का प्रयास भी किया गया है।

डिजिटल शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और उद्योग-संबद्ध पाठ्यक्रमों पर विशेष फोकस रहा है, ताकि युवा केवल साक्षर ही नहीं, बल्कि काम करने योग्य और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। इसी तरह कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में संसाधन बढ़ाए गए हैं, जिससे नवाचार और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।

वर्तमान में भारत की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर लगभग 28 प्रतिशत है, जबकि सरकार का लक्ष्य अगले दशक में इसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का है। इस उद्देश्य से बजट में उच्च शिक्षा संस्थानों– विशेषकर तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों की क्षमता और गुणवत्ता में निरंतर निवेश का प्रावधान किया गया है। पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप और शिक्षा के लिए एआइ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस युवाओं के लिए एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देते हैं। औद्योगिक कॉरिडोर के निकट विकसित होने वाली ये यूनिवर्सिटी टाउनशिप पढ़ाई, शोध और उद्योग को एक साथ जोड़ेगी। इससे छात्रों को कक्षा के बाहर व्यावहारिक अनुभव, इंटर्नशिप और रोजगार के स्पष्ट अवसर मिल सकेंगे। एआइ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से तकनीक-आधारित शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल और भविष्य के अनुरूप कौशल को बढ़ावा मिलेगा। युवा उद्यमी और प्रशिक्षित श्रमिक बाज़ार की मांग के अनुरूप तैयार हो सकेंगे। यदि इन सभी को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह बजट युवाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए निर्णायक रूप से तैयार कर सकता है।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक,
आइआइएम, इंदौर

आम बजट को विस्तार से पढ़ने और इसके सभी आयामों को समझने के लिए www.patrika.com पर जाएं।